



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2012/माघ 21, 1933
No. 40] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2012/MAGHA 21, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी तथा संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2012

(अंतिम जांच परिणाम)

विषय : चीन जन.गण. और इजरायल के मूल के या वहां से निर्यातित सिंक्रोनस डिजिटल हाईआर्की ट्रांसमिशन उपकरण (एस डी एच उपकरण) के आयातों के बारे में पाटनरोधी शुल्क की जांच।

सं. 14/2/2009-डीजीएडी.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए;

पृष्ठभूमि :

1. यतः समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली या पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) को चीन जन.गण. और इजरायल (जिन्हें आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित सिंक्रोनस डिजिटल हाईआर्की ट्रांसमिशन उपकरण (जिसे आगे एसडीएच उपकरण या संबद्ध वस्तु कहा गया है) के पाटन का आरोप लगाते हुए घरेलू उद्योग की ओर से मै. तेजस नेटवर्क्स लि. (जिसे आगे आवेदक कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ और प्राधिकारी से संबद्ध वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु पाटनरोधी जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया।

2. और यतः प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य की पर्याप्तता और सत्यता के बारे में जांच करने के बाद नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार संबद्ध देशों के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 21 अप्रैल, 2009 को एक सार्वजनिक सूचना सं. जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया ताकि आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लागू किया जाएगा तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

3. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए 7 सितंबर, 2009 की अधिसूचना के तहत चीन जन.गण. और इजरायल के मूल के या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों की जांच की और उस पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की तथा वित्त मंत्रालय ने अनंतिम पाटनरोधी शुल्क 8 दिसंबर, 2009 की अधिसूचना सं. 132/2009-सी.शु. के तहत लगाया था ।

4. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने संबद्ध देशों की संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हुए 19 अक्टूबर, 2010 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए तथा वित्त मंत्रालय ने निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 16 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना सं. 125/2010-सी.शु. के तहत लगाया था ।

5. और यतः कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने 19 अक्टूबर, 2010 के अंतिम जांच परिणामों और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की गई सीमाशुल्क अधिसूचना को चुनौती देते हुए माननीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट), प्रधान पीठ, नई दिल्ली के समक्ष अपीलें दायर कीं ।

6. और यतः माननीय सेस्टेट ने हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग की गहन सुनवाई करने के बाद 11 अगस्त, 2011 को एक आदेश जारी किया जिसमें न्यायाधिकरण ने 3 अपीलकर्ता हितबद्ध पक्षकारों अर्थात् मै. हुआवाई टेक्नोलॉजीज कंपनी लि., चीन; मै. बुपालामृता मैग्नेटिक कंपोनेंट्स, हैदराबाद, भारत तथा मै. पृथ्वी इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशन लि., सिंकदराबाद, भारत की अपीलों को अपीलकर्ताओं तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों, यदि कोई हो, की निर्णयोपरांत सुनवाई का अवसर देने तथा ऐसी निर्णयोपरांत सुनवाई के परिणामस्वरूप अंतिम जांच परिणाम में यथावश्यक संशोधन करने के लिए यह मामला निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजते हुए अपीलों की अनुमति दी । माननीय न्यायाधिकरण के आदेश में निम्नानुसार उल्लेख है :

“तदनुसार हम आवेदकों को निर्णयोपरांत सुनवाई का अवसर देने और अंतिम जांच परिणाम में ऐसे उपांतरण करने जिन्हें ऐसे निर्णयोपरांत सुनवाई के परिणामस्वरूप आवश्यक समझा जाए, करने के लिए ये अपीलें निर्दिष्ट प्राधिकारी को वापस भेजने की अनुमति देते हैं । प्रतिवादी घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों, यदि कोई हो, को भी ऐसे निर्णयोपरांत सुनवाई में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी । अंतिम जांच परिणाम में किए गए किसी उपांतरण पर पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली आक्षेपित अधिसूचना में आवश्यक संशोधन कर सरकार द्वारा उन्हें प्रभावी बनाते हुए विचार किया जाएगा । यह प्रक्रिया इस आदेश की तारीख से 6 माह के भीतर पूरी की जाएगी और इस बीच यथास्थिति बनाए रखी जाएगी । चूंकि हम इन अपीलों की अनुमति वापस भेजकर प्रदान कर रहे हैं, इसलिए संबंधित स्थगन याचिकाएं, एम ए तथा सी ओ को निपटाया गया माना जाएगा । ”

प्रक्रिया

7. निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है :

i. माननीय सेस्टेट के उक्त आदेश के अनुसरण में प्राधिकारी ने 23 जनवरी, 2012 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को एक अवसर प्रदान किया। सार्वजनिक सुनवाई के समय जिन हितबद्ध पक्षकारों ने अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे उनसे उनके द्वारा व्यक्त मौखिक विचारों के लिखित अनुरोध दायर करने का आग्रह किया गया था और उन्हें हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर उत्तर दायर करने की अनुमति दी गई थी। मौखिक सुनवाई के बाद निम्नलिखित पक्षकारों ने अनुरोध दायर किए हैं :-

- (क) तेजस नेटवर्क्स लि., इंडिया
- (ख) कोरल टेलीकॉम, इंडिया
- (ग) हुवेई टेक्नोलॉजीज क. लि., चीन जन.गण.
- (घ) ई सी आई टेलीकॉम इजरायल
- (ङ.) हांगझोऊ ई सी आई टेलीकम्यूनिकेशन्स कं. लि., चीन जन.गण.
- (च) ई सी आई टेलीकॉम इंडिया प्रा.लि., इंडिया
- (छ) सेरागन नेटवर्क्स लिमिटेड, इजरायल
- (ज) आर ए डी डाटा कम्यूनिकेशन्स लि. इजरायल
- (झ) बुपालामृथा मैगनेटिक कम्पोनेंट्स लि., इंडिया
- (ट) पृथ्वी इन्फॉरमेशन्स सोल्यूशंस लि., इंडिया
- (ठ) यू टी स्टारकॉम, चाइना
- (ड) साइना कॉरपोरेशन, अमरीका
- (ढ) जैड टी ई कारपोरेशन, चाइना
- (ण) एअरसैल इंडिया लिमिटेड, तथा
- (त) वोडाफोन इंडिया लिमिटेड

ii. प्राधिकारी द्वारा आयोजित मौखिक सुनवाई के बाद विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की विस्तृत जांच तथ्यों और विधिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए की गई थी और इन पर प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के संदर्भ में संगत पाई गई सीमा तक वर्तमान प्रकटन विवरण में विचार किया गया है।

iii. अनेक भागीदार हितबद्ध पक्षकारों तथा इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रकटन विवरण में इन हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को सामूहिक रूप से सारांकित किया है।

iv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 क अनुसार वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया जा रहा है। इस प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर प्राधिकारी अपने अंतिम जांच परिणाम में संगत समझी गई सीमा तक विधिवत विचार करेंगे।

v. *** यह चिन्ह इस अंतिम जांच परिणाम में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमों के अंतर्गत गुण-दोष के अनुसार उसे गोपनीय ही माना है। मौखिक सुनवाई के बाद विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की प्राधिकारी ने इस प्रकटन विवरण में उचित शीर्षों के अंतर्गत जांच की है।

vi. इस प्रकटन विवरण में प्रयुक्त कुछेक संक्षेपाक्षर निम्नलिखित को दर्शाते हैं :-

क्र.सं	संक्षिप्ताक्षर	व्याख्या/अर्थ
1.	प्राधिकारी	निर्दिष्ट प्राधिकारी
2.	अधिनियम	वर्ष 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975
3.	नियमावली	सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, पाटनरोधी शुल्क का निर्धारण एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995
4.	विचाराधीन उत्पाद	विचाराधीन उत्पाद अर्थात् इस प्रकटन विवरण के संगत पैरा में यथापरिभाषित एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण
5.	सीकेडी	पूर्णतः नॉकड डाउन स्थिति
6.	एसकेडी	अर्ध नॉकड स्थिति
7.	नि.प्रा.	निर्दिष्ट प्राधिकारी
8.	घ.उ.	घरेलू उद्योग
9.	पा.रो.करार	डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार
10.	एस डी एच	सिंक्रोनस डिजिटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण
11.	तेजस	तेजस नेटवर्क्स लि.
12.	वी एम सी एल	वुप्पालाकृता मैग्नेटिक कंपोनेंट्स लि.
13.	पृथ्वी	पृथ्वी इन्फॉर्मेशन सॉल्यूशंस लि.
14.	बी एस एन एल	भारत संचार निगम लि.

दिनांक 23 जनवरी, 2012 को आयोजित दूसरी निर्णयात्मक मौखिक सुनवाई के पश्चात लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तरों में याचिकाकर्ता घरेलू उद्योग द्वारा किये गये अनुरोध

8. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये थे:-

- i घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत पूर्व अनुरोधों में शामिल सभी तथ्यों, तर्कों, दावों और विवरणों को आगे भी शामिल माना जाए भले ही दूसरी निर्णयात्मक मौखिक सुनवाई के उपरान्त लिखित अनुरोधों और प्रत्युत्तरों में उन्हें दोहराया न गया हो।
- ii याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि मौजूदा मामले के असाधारण तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा उद्गम के अर्थ पर विचार किया जाए और उसे परिभाषित किया जाए। प्रत्येक उत्पाद के संदर्भ में उत्पादन/विनिर्माण का अर्थ अलग-अलग होता है और ऐसे उत्पाद के विनिर्माण में शामिल प्रक्रियाओं का इस संदर्भ में अपना महत्व होता है। इसके अतिरिक्त "के मूल के" के अर्थ को उस स्थान से संबद्ध करना अपेक्षित होता है जहाँ उत्पाद का वास्तव में उत्पादन हुआ हो। ऐसे स्थान को केवल उस स्थान तक सीमित नहीं किया जा सकता है जहाँ स्कू ड्राइवर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उस उत्पाद को असेम्बल किया गया हो।
- iii "भारतीय उत्पाद" "भारत में विनिर्मित उत्पाद" से अलग है। याचिकाकर्ता द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (टीआरएआई) की दिनांक 12 अप्रैल 2011 की दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति से संबंधित सिफारिशों का संदर्भ दिया गया है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि (क) पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के पश्चात भी घरेलू उद्योग को पाटन का सामना न करना पड़े, (ख) चीन तथा इजराइल के बाहर के उत्पादकों को पाटनरोधी शुल्क का भुगतान केवल इसलिए न करना पड़े कि ऐसे कुछेक छोटे-मोटे प्रचालन चीन में किये जाते हैं और (ग) चीन तथा इजराइल के उत्पादकों को किसी भी रूप में उत्पाद के आयात द्वारा पाटन को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
- iv प्रारंभिक जाँच परिणामों के जारी होने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से पॉन्डिचेरी स्थित तेजस फैक्टरी का दौरा किया गया था। प्रारंभिक जाँच परिणामों से पहले बंगलौर का दौरा किया गया था जहाँ कम्पनी द्वारा सभी संगत वित्तीय सूचना रखी जाती है। चूंकि प्रारंभिक जाँच परिणामों से पहले किये गये दौरे का प्रयोजन वित्तीय सूचना की जाँच करना था अतः इस दौरे को बंगलौर तक सीमित रखा गया। इसके अतिरिक्त बंगलौर में कम्पनी का एक अनुसंधान एवं विकास स्कन्ध भी है। अनुसंधान एवं विकास इस उद्योग में उत्पादन का केन्द्र बिन्दु है।
- v प्रारंभिक जाँच परिणामों के बाद पॉन्डिचेरी में जाँच की गई थी। पहली सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग ने कभी भी यह सूचित नहीं किया था कि जाँच अवधि के दौरान पॉन्डिचेरी फैक्टरी

मौजूद नहीं थी और इस फैक्टरी द्वारा हाल ही में उत्पादन शुरू किया गया था । वस्तुतः पॉन्डिचैरी फैक्टरी जाँच अवधि के दौरान भी प्रचालनरत थी ।

- vi याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि प्राधिकारी ने इस बात पर विचार करते हुए कि मै. हैंगझोऊ ईसीआई टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनी लि. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार की पात्र है या नहीं, केवल स्वामित्व संबंधी मानदण्ड को ध्यान में रखा और अन्य छह मानदण्डों की उपेक्षा की और विशेष रूप से इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक चीन के प्रतिवादी निर्यातक पाटनरोधी नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित प्रत्येक मानकों के संदर्भ में कसौटी पर खरे न उतरें । इसके अतिरिक्त याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि प्राधिकारी द्वारा यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त तर्क नहीं दिये गये हैं कि मै. हैंगझोऊ ईसीआई टेलिकम्यूनिकेशन कम्पनी लि. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के संबंध में ऊपर उल्लिखित सभी मानदण्डों को पूरा करती है।
- vii इस विश्वास हेतु सुदृढ़ कारण मौजूद हैं कि चुनिंदा प्रतिवादी निर्यातकों (विशेष रूप से ईसीआई तथा जेडटीई) ने जानबूझकर प्राधिकारी से सूचना छिपाई है और घरेलू बिक्री तथा पीओआई के दौरान भारत को किये गये निर्यातों के संबंध में निर्यात संबंधी सभी लेन-देनों की सूचना नहीं दी है । अपनी क्षति तथा पाटन मार्जिन को कम करने के लिए जानबूझकर ऐसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाया गया है । अतः यह स्पष्ट है कि ईसीआई ने यह सिद्ध नहीं किया है कि कैसे वह बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार पाने की पात्र है ।
- viii ईसीआई द्वारा न केवल गलत सूचना दी गई है बल्कि अनुचित कार्यपद्धतियां अपनाकर उन्होंने शुल्क अपवंचन करना भी शुरू कर दिया है । ईसीआई ने इजराइल के रास्ते चीन से भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया है ताकि वे " उद्गम के देश, " के रूप में "इजराइल" को दर्शा सकें जबकि वस्तुएं चीन के मूल की हैं ।
- ix यह उल्लेखनीय है कि ह्वावेई ने सीईएसटीएटी के समक्ष प्रस्तुत विवाद के आधार पर कोई तर्क प्रस्तुत नहीं किया और सुनवाई के मुद्दे तक ही अपने तर्कों को सीमित रखा । इस बिन्दु पर एक लिखित नोट भी प्रस्तुत किया गया था जो माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर उनकी याचिका में मौजूद है ।
- x याचिकाकर्ता ने प्राधिकारी से इस तथ्य का संज्ञान लेने का अनुरोध किया है कि सुनवाई में मौजूद पक्षों द्वारा और सुनवाई में भाग न लेने वाले पक्षों द्वारा लिखित अनुरोध प्रस्तुत नहीं किये गये हैं ।

- xi हवावेई ने प्राधिकारी के समक्ष पूर्व में प्रस्तुत किये गये उन तर्कों के अतिरिक्त कोई नये आधार प्रस्तुत नहीं किये हैं जिन पर पिछले जाँच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा समुचित विचार किया गया था ।
- xii हवावेई के वकील ने मौखिक सुनवाई के दौरान 2 घण्टे से अधिक समय तक अपनी दलीलें प्रस्तुत की और अब उन्होंने अत्यधिक संक्षिप्त (2पृष्ठ) रूप में लिखित अनुरोध प्रस्तुत किया है । घरेलू उद्योग द्वारा प्राधिकारी से इस तथ्य पर विचार करने और इसे रिकॉर्ड करने का अनुरोध किया गया है । वास्तव में नियमावली के अन्तर्गत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा मौखिक रूप से उठाए गए किसी तर्क पर विचार करना तब तक अपेक्षित नहीं है जब तक कि ऐसे मौखिक तर्क को बाद में लिखित रूप में प्रस्तुत न किया जाए ।
- xiii जहाँ तक साक्ष्य की यथार्थता और पर्याप्तता का संबंध है, याचिकाकर्ता ने यह अनुरोध किया कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में भारतीय उत्पाद के संबंध में स्पष्ट सूचना प्रस्तुत की गई थी । याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादन और भारतीय उत्पादन के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है जिससे यह पूर्णतः सिद्ध होता है कि भारतीय उत्पादन में याचिकाकर्ता का हिस्सा लगभग 85% था ।
- xiv जहाँ तक सीएमएआई के पत्र की विश्वसनीयता का संबंध है यह सूचित किया गया था कि सीएमएआई ने अपने पत्र में 4 वक्तव्य प्रस्तुत किये हैं । अब तक यह सिद्ध नहीं किया गया है कि इनमें से कोई भी वक्तव्य तथ्यात्मक रूप से गलत है । इससे सीएमएआई द्वारा जारी पत्र की विश्वसनीयता स्वतः सिद्ध हो जाती है । जहाँ तक सीएमएआई के पत्र में पात्रता का संबंध है तो इसका उल्लेख केवल यह सूचित करने के लिए किया गया है कि इन आंकड़ों को 100% सही आंकड़े नहीं माना जाना चाहिए । इस संबंध में यह उल्लेख करना संगत होगा कि प्राधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता, विदेशी उत्पादकों और आयातकों से उनकी प्रश्नावलियों में अपेक्षित प्रमाणपत्र में अहर्ता संबंधी मानदण्ड भी शामिल है ।
- xv जहाँ तक घरेलू उत्पादकों की निर्णय पूर्व सुनवाई और मतगणना का संबंध है यह अनुरोध किया गया था कि जाँच पूर्व मतगणना अथवा सुनवाई कानूनी रूप से अपेक्षित नहीं है । किसी भी स्थिति में, चूंकि याचिका में यह दर्शाया गया था कि याचिकाकर्ता का हिस्सा लगभग 86% था जो 25% के न्यूनतम अधिदेशित हिस्से से बहुत अधिक था, अतः मतगणना पूर्णतः अनावश्यक थी ।

xvi गोपनीयता के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि स्वयं निर्यातक ने भारतीय बाजार में निर्यातक द्वारा बेचे गये उत्पाद के विभिन्न प्रकारों के संबंध में सूचना का प्रकटन नहीं किया है। इन पक्षकारों द्वारा सब-असेम्बलीज अथवा असेम्बलीज के आयातों के किसी भी ब्यौरे का सार्वजनिक अगोपनीय रूपांतरणों में प्रकटन नहीं किया गया है। जैसाकि निर्यातक के वकील का दावा है कि वॉयस एण्ड डाटा मैग्जीन की माँग किये जाने पर भी इस सूचना का प्रकटन नहीं किया गया था। उनके दावे के अनुसार वॉयस एण्ड डाटा मैग्जीन की पिछले पाँच वर्षों की प्रतियाँ उनके पास उपलब्ध थी और सार्वजनिक फाइल के जरिए घरेलू उद्योग को उनकी प्रति कभी उपलब्ध नहीं कराई गई। यह स्पष्ट नहीं है कि वॉयस एण्ड डाटा मैग्जीन की पिछले पाँच वर्षों की ये सभी प्रतियाँ उनके द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं अथवा नहीं।

xvii वॉयस एण्ड डाटा मैग्जीन की सटीकता के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि संबंधित नियम सूचना की सटीकता के संदर्भ में निर्दिष्ट प्राधिकारी की संतुष्टि तक सीमित है। इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी की इस बाध्यता के रूप में नहीं देखा जा सकता है कि वह उसके समक्ष प्रस्तुत की गई प्रत्येक सूचना की जाँच करे।

xviii प्रकटन विवरण अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन मात्र होता है। यह विवरण निर्धारणों का प्रकटन नहीं है। सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारण हैं जो अनिवार्य तथ्यों का परिणाम होते हैं। वस्तुतः सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का निर्धारण जाँच प्रक्रिया के दौरान एकत्रित तथ्यों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई टिप्पणियों के पश्चात किया जाना अपेक्षित है।

xix घरेलू उद्योग द्वारा किसी भी देश से संपूर्ण एसडीएच उपकरण का आयात नहीं किया गया है।

xx तेजस द्वारा भारत के बाहर से पॉप्युलेटेड पीसीबी का आयात नहीं किया जाता है। तेजस डिजाइन और ड्राइंग के अनुसार उन्हें अपने ईएमएस से पॉप्युलेटेड करवाता है।

xxi जहाँ तक सुनवाई की सूचना बहुत कम समय पहले दिये जाने का प्रश्न है, याचिकाकर्ता द्वारा यह सूचित किया गया है कि यह मौजूदा सुनवाई के लिए दी गई दूसरी तारीख थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 23 दिसम्बर 2011 को की जाने वाली सुनवाई के लिए पहले ही सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित कर दिया था। तथापि कुछ हितबद्ध पक्षकारों

द्वारा की गई आपत्ति के परिणामस्वरूप उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी थी। हितबद्ध पक्षकार इस बात से भली-भाँति परिचित हैं कि सीईएसटीएटी ने निर्णय उपरान्त इन सुनवाईयों का आयोजन करने और आवश्यक जाँच परिणाम जारी करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी को 6 माह का समय दिया है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मौजूदा सुनवाई की सूचना बहुत कम समय पहले दी गई थी।

xxii निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के स्पष्ट संकेत मिले हैं कि घरेलू उद्योग ने केवल (क) दोहरे उपयोग वाले पुर्जों और संघटकों, (ख) तेजस द्वारा प्रदत्त डिजाइन तथा ड्राइंग के आधार पर ईएमएस द्वारा पॉप्युलेटेड पीसीबी (अर्थात् तेजस द्वारा जॉब वर्क भारत के बाहर से करवाया गया) का आयात किया है।

xxiii याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। इसके स्थान पर याचिकाकर्ता ने दोहरे इस्तेमाल वाले पुर्जों और संघटकों का आयात किया है जो अब विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं और जिनका आयात किसी विनिर्माण कम्पनी द्वारा किए गए कच्ची सामग्री के आयात के सदृश है। याचिकाकर्ता ने संबद्ध देशों से पीयूरी का आयात नहीं किया है।

क. डी एक्स सी का उपयोग ट्रेफिक ग्रूमिंग के लिए किया जाता है।

ख. वैश्विक रूप से डी एक्स सी को भिन्न उत्पाद श्रेणी के रूप में माना जाता है।

ग. डी एक्स सी को कभी भी एस टी एम - एक्स एक्स मशीन में रूपांतरित नहीं किया जा सकता।

xxiv. किसी बात के होते हुए भी, याचिकाकर्ता निवेदन करते हैं कि नियम 2(ख) के प्रावधानानुसार प्राधिकारी को अपने विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए किन्हीं निश्चित परिस्थितियों में घरेलू उत्पादक को अयोग्य मानने का अधिकार है।

xxv. जहाँ तक माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष एसएलपी के निपटान तक अंतिम जाँच परिणाम जारी न करने हेतु कुछेक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी से अनुरोध किए जाने का प्रश्न है, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को ऐसा कोई आदेश अथवा निर्देश जारी नहीं किया है। वस्तुतः पिछली सुनवाई के समय उपस्थित पक्षकारों के पक्ष को विस्तारपूर्वक सुनने के पश्चात्, माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेस्टेट आदेश के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में बाधा डालने वाला कोई आदेश परित नहीं किया है। अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्राधिकारी से सेस्टेट के निर्देशों के अनुसार जाँच परिणाम जारी करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। सेस्टेट ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को छह महीने

की अवधि प्रदान की है और उस अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्कों को लागू रखा गया है । जांच परिणामों को समय सीमा के भीतर जारी करना महत्वपूर्ण है ताकि घरेलू उद्योग को 'शून्य शुल्क अवधि' जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े । तथ्यतः उच्चतम न्यायालय द्वारा न केवल इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है बल्कि न्यायालय ने दिनांक 20/09/2011 के अपने पूर्ववर्ती आदेश द्वारा प्राधिकारी के रिमांड संबंधी कार्रवाहियों को आगे बढ़ाने हेतु विशेष रूप से निर्दिष्ट किया है ।

- xxvi. जहाँ तक उत्पाद को शामिल न करने के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त होने का संबंध है, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी उत्पाद को विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से उसी स्थिति में बाहर रख सकता है यदि घरेलू उद्योग के पास समान उत्पाद न हो । यदि घरेलू उद्योग के पास समान उत्पाद है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे उत्पाद प्रकार को जांच के दायरे से बाहर नहीं रख सकता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस संबंध में पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है । उत्पाद का अपवर्जन मामले के तथ्यों और इस तथ्य से शासित होता है कि घरेलू उद्योग के पास समान उत्पाद है अथवा नहीं ।
- xxvii. जहाँ तक विचाराधीन उत्पाद के दायरे से पीटीएन को बाहर रखने का संबंध है, याचिकाकर्ता ने निवेदन किया है कि जेडई ने ऐसी कोई सूचना/ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया है जिससे यह निर्धारित किया जा सके कि पीटीएन विचाराधीन उत्पाद का एक प्रकार नहीं है । यिापी विशेष उत्पाद प्रकार को जांच के दायरे से बाहर रखने की मांग करने वाले किसी पक्ष को ऐसे अपवर्जन के लिए औचित्य प्रस्तुत करना होगा । उत्पाद को अपवर्जित करने की आवश्यकता के निर्धारण का उत्तरदायित्व निर्यातकों पर होता है । यदि निर्यातकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि कोई विशेष उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर है तो उन्हें इसका साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा । घरेलू उद्योग द्वारा इस तथ्य के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं कि पीटीएन विचाराधीन उत्पाद का ही एक प्रकार है ।
- xxviii. सॉफ्टवेयर विकास के अतिरिक्त महत्वपूर्ण कार्यकलाप तेजस द्वारा किए जाते हैं । पूर्व में किए गए निवेदनों पर विश्वास किया गया है । सॉफ्टवेयर विकास समग्र उत्पादन कार्यकलाप का एक भाग है । यह एक अविवादित तथ्य भी है कि सॉफ्टवेयर एक महत्वपूर्ण कार्यकलाप है ।
- xxix. धारा एकसवीआई की टिप्पणी 6 द्वारा, संयोजन का तात्पर्य उत्पाद शुल्क लागू करने के प्रयोजनार्थ विनिर्माण से है - इससे एक विचारित कल्पना का सृजन होता है, जिसे अन्य कानूनों पर लागू नहीं किया जा सकता है - यह आवश्यक नहीं है कि उत्पाद शुल्क कानून की परिभाषा को वर्तमान मामले पर भी लागू किया जा सके । विनिर्माण/उत्पादन की परिभाषा पर कानून और उस प्रयोजन, जिसके लिए ऐसे शब्द का उपयोग किया गया है, के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए । विस्तृत लिखित निवेदन का संदर्भ लिया गया है और उन पर विश्वास किया गया है ।

xxx. तेजस ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों द्वारा अपने दावों का उचित निर्वहन कर दिया है कि वह घरेलू उद्योग है। विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस दावे का खण्डन करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथ्यों संबंधी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के जांच परिणाम सही हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की समुक्तियों पर विचार किए बिना इस मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अतः उक्त निर्णय पर विश्वास नहीं किया जा सकता है।

xxxi. जहां तक विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पुर्जों एवं संघटकों को जांच के कार्य क्षेत्र से बाहर रखने के अनुरोध का संबंध है, यह निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे में पुर्जों और संघटकों को शामिल करने हेतु तर्क देना जारी रखा है। याचिकाकर्ता ने जांच के दायरे से पुर्जों और संघटकों को बाहर रखने की मांग नहीं की है। अब जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उनके तर्कों को स्वीकार किया है और याचिकाकर्ता के तर्कों को अस्वीकार किया है। अतः विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अपवर्जन के संबंध में प्राधिकारी के निर्णय का इस प्रकार विरोध करना अत्यधिक अनुचित है। किसी भी मामले में, ऐसे अपवर्जन के पीछे कारण निर्धारित करना सर्वथा अनुचित है।

xxxii. संबद्ध देशों से कच्ची सामग्री के आयात के आधार पर किसी विनिर्माता को पात्र घरेलू उद्योग माने जाने से वर्जित नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा ऐसी अनेक जांच की गई है जिनमें याचिकाकर्ता संबद्ध देशों से कच्ची सामग्री का आयात कर रहे हैं।

विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर लिखित निवेदन और दूसरी मौखिक सुनवाई के पश्चात् प्रत्युत्तर में दायर लिखित निवेदन

9. विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित निवेदन किए गए थे :-

- i. प्राधिकारी एवं वित्त मंत्रालय द्वारा "घरेलू उत्पादकों" की परिभाषा से कुछेक भारतीय सत्ताओं सत्तराओं (पृथ्वी और वीएमएलसी) के अपवर्जन के संबंध में कोई जांच किए बगैर आवेदकों (तेजस) द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर लिया गया था।
- ii. सीएमआई ने एक पत्र दिया है जिसमें यह इंगित किया गया है कि तेजस का उत्पादन, कुल उत्पादन के 50% से अधिक है, यद्यपि उन्होंने उत्पादन के संबंध में सटीक जानकारी नहीं दी है। इस पत्र को सूचना की पर्याप्तता और सटीकता की जांच किए बिना एक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था।
- iii. आवेदन में यह कहा गया था कि अन्य भारतीय उत्पादकों का उत्पादन वॉइस एण्ड ड्राइंग मैगजीन में प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित था, जिसके पास विचाराधीन उत्पाद तथा अन्य उत्पादों के संबंध में भी सूचना है और इसलिए इन तथ्यों को विचाराधीन उत्पाद संबंधी

- सूचना के निर्धारण के लिए समायोजित किया गया है। प्राधिकारी ने समायोजनों संबंधी व्यौरों की जांच नहीं की है।
- iv. प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस जैसे अन्य आधिकारिक आयात आंकड़ों के साथ मिलान द्वारा आवेदन में उपलब्ध कराई गई सूचना की सटीकता की जांच नहीं की है।
 - v. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अपने जांच परिणामों में इस बात का कोई औचित्य नहीं दिया गया था कि डाटा स्टॉफ मैनुफैक्चरर्स ऑफ इंडिया बनाम भारत सरकार के निर्णय को निर्दिष्ट प्राधिकारी पर क्यों लागू नहीं किया गया।
 - vi. आवेदकों द्वारा घरेलू उद्योग का प्रतिनिधि होने के उनके दावे का आकलन करने के लिए निर्णय लेने से पूर्व कोई कार्रवाई नहीं की गई।
 - vii. घरेलू उत्पादकों के लिए पोलिंग की कार्रवाई भी नहीं की गई है। इससे यह आकलन करने में सहायता मिलती है कि आवेदन का विरोध किया गया है अथवा नहीं।
 - viii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियम 6, 7, 8, 9 और 16 में दी गई अनिवार्य प्रक्रियागत अपेक्षाओं का अनुपालन किए बिना मनमाने ढंग से जांच की है।
 - ix. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपीलकर्ता और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सीमित सूचना और साक्ष्य प्रदान किए हैं। ऐसे और भी प्रक्रिया संबंधी उल्लंघन किए गए हैं जैसे, नियम 6(4) के तहत गैर जरूरी सूचना प्रस्तुत करने पर जोर दिया गया, अत्यधिक गोपनीयता बरतने की अनुमति दी गई, आयातों की मात्रा एवं मूल्य की सटीकता का कभी भी सत्यापन नहीं किया गया, सत्यापन संबंधी दौरे, मनमाने ढंग से किए गए, प्रतिवादी सं. 1 का प्रकटन विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया।
 - x. आयात आंकड़ों के स्रोत, अधिकांश बाजार हिस्से का आधार, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विभिन्न प्रकार के उत्पाद, सामान्य मूल्य अथवा निर्यात कीमत का आधार, निर्यात कीमत से की गई विभिन्न कटौतियों के दावों संबंधी साक्ष्य, के संबंध में अत्यधिक गोपनीयता बरती गई। लागत संबंधी सूचना को सूचीबद्ध नहीं किया गया। खरीद नीति, बिक्री संबंधी नीति, भण्डार संबंधी लेखों, वस्तुसूची/डब्ल्यूआईपी/स्टॉक आकलन, गुणवत्ता नियंत्रण नीति के संबंध में स्पष्ट सूचना नहीं दी गई।
 - xi. आवेदक को छोड़कर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए अगोपनीय रूपांतरों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया गया।
 - xii. प्रकटन विवरण में ऐसे सभी आवश्यक तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया जिनके आधार पर निर्णय लिया गया था।

उदाहरणतः शेष निर्यातकों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत; अपीलकर्ता द्वारा दी गई टिप्पणियां; यह तथ्य कि तेजस ने संपूर्ण एसडीएच का आयात किया है; घरेलू एवं निर्यात बाजार में लाभ का अलग-अलग आकलन।

- xiii. मूल प्रकटन विवरण में, पाटन मार्जिन 240-250% था तथा दूसरे संशोधित प्रकटन विवरण में यह 280-290% था । पाटन मार्जिन के संबंध में यह उद्घाटी वृद्धि भ्रामक है क्योंकि एनआईपी में परिवर्तन से पाटन मार्जिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है ।
- xiv. आवेदन घरेलू उद्योग एक डिजाइन हाउस था जो भारत में डिजाइन तथा विकास कार्यकलाप करता है परंतु वास्तविक उत्पादन कार्यकलाप भारत से बाहर किए जाते थे ।
- xv. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने आवेदक के बंगलौर स्थित प्रधान कार्यालय का दौरा किया और उन्हें पॉडिचेरी के नए संयंत्र का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया जिसे उनके दौरे के पश्चात स्थापित किया गया था ।
- xvi. अंतिम जाँच परिणामों में यह उल्लेख किया गया है कि तेजस ने थाईलैंड और सिंगापुर से पीसीबी का आयात किया है । भारत में पीसीबी के प्रवेश के पश्चात, अंतिम उत्पाद के विनिर्माण हेतु कोई विशेष प्रक्रिया अपेक्षित नहीं होती है ।
- xvii. भारतीय संबद्ध पक्ष ने संपूर्ण पतों के साथ भारत के 11 घरेलू उत्पादकों की सूची प्रस्तुत की है और उन उत्पादों का विवरण दिया है जिसके लिए उन्हें बीएसएनएल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है । इस सूची में उल्लिखित कुछ उत्पादक भारत में केवल पीसीबी मंगवाते हैं और यहां उन पर आगे कार्य किया जाता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इन कंपनियों की स्थिति की जांच नहीं की है ।
- xviii. ऐसे उत्पादक जो संयोजन संबंधी प्रचालन और अंतिम परीक्षण भारत में करते हैं उन्हें घरेलू उत्पादक नहीं माना जाएगा । अतः जबकि आवेदक (तेजस) विनिर्माण नहीं करते हैं तो उन्हें घरेलू उद्योग नहीं माना जाएगा ।
- xix. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने तेजस द्वारा उपलब्ध कराई गई उनकी कार्यों की सूची की जांच नहीं की है ।
- xx. असेम्बलीज और सब असेम्बलीज, कैपिसिटेटर्स, कनेक्टरों, इंडक्टरों, रेसिस्टर्स, स्टिकरों, ट्रांस-रिसीवरों, ट्रांसफॉर्मरों तथा पैच-कॉर्डों की खरीद तीसरे स्रोत से की गई थी जबकि तेजस द्वारा इन मदों की खरीद करने का वृद्धिकारी कार्यकलाप और असेम्बली और परीक्षण संबंधी प्रचालन किया जा रहा था । निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि तेजस द्वारा पर्याप्त प्रचालन किए गए थे ।
- xxi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने विवादित जांच परिणामों में यह कहा है कि अन्य देशों से किए गए आयातों में पाटित वस्तुएं शामिल नहीं हैं, ऐसा निर्धारण समुचित नहीं है क्योंकि यहां सवाल केवल आयात का नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति द्वारा आयात का है जो भारत में उत्पाद का विनिर्माण नहीं कर रहा है । यहां प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में किए जाने वाले आयात वास्तव में संबद्ध देशों से इतर देशों से किए गए थे ।
- xxii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसे तीसरे पक्ष के ईएमएस वेंडरों की क्षमता और उत्पादन सुविधाओं की जांच करने हेतु उनके परिसर में कोई सत्यापन नहीं किया था ।

- xxiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी कोई सटीक परिभाषा देने में असमर्थ रहे चूंकि परिभाषा में चार अलग-अलग मर्दों अर्थात: पुर्जे, उपकरण, असेम्बलीज/सब-असेम्बलीज और अन्य उपकरणों को शामिल किया गया है ।
- xxiv. एसटीएम 64 तथा एसटीएम 256 को शामिल नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि एसटीएम-64 को कभी भी वाणिज्यिक मात्रा में उत्पादित नहीं किया गया था और वे भारतीय घरेलू बाजार में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए थे । एसटीएम-256 का भारत को आयात नहीं किया गया था तथा सभी पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि भारत में एसटीएम-256 के उपयोग हेतु तकनीकी अनुमोदन सही नहीं हैं । इसके अलावा अन्य एसटीएम 1-64 की तुलना में एसटीएम-256 दूसरे उत्पाद वर्ग में आता है ।
- xxv. डीएक्ससी को निम्नलिखित कारणों से विचाराधीन उत्पाद के दायरे से नहीं रखा जाना चाहिए ।
- xxvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पी यू सी से में पोपुलेटेड पी सी बी को शामिल किया है और मामले के रिकॉर्ड इंगित करते हैं कि घरेलू उद्योग भारत के अंदर पोपुलेटेड पी सी बी उत्पादन नहीं करता है ।
- xxvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ब्राड बैंड अथवा सेलुलर उपकरण की प्रकृति की जांच नहीं की है और यह कि क्या यह संभव है कि एस डी एच उपकरण के मूल्य से अकेला एस डी एच उपकरण के मूल्य को अलग किया जा सकता है ।
- xxviii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने एस डी एच के लिए सॉफ्टवेयर का अर्थ शामिल किया है उसे या तो उपकरण के एक भाग के रूप में या अलग माना जाएगा । यह एक सेवा है और इस प्रकार इसे निकाल दिया जाना चाहिए ।
- xxix. अपने प्रकार के किसी फार्म में गैर एस डी एच होने के आधार पर कुछ उपकरणों को बाहर किया गया है । सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने उन उपकरणों पर शुल्क की मांग की है जिनमें कुछ एस डी एच अनुवर्ती हिस्सा/इंटरफेस हो, केवल वे मशीनें जो केवल गैर एस डी एच के रूप में हो, को छोड़ा जाना चाहिए । इस प्रकार अपने किसी भी फार्म में गैर एस डी एच के बदले किसी एस डी एस अनुवर्ती परि या इंटरफेस होने पर बदला जा सकता है ।
- xxx. पी यू सी समान उत्पाद नहीं था लेकिन भिन्न-भिन्न ग्रेडों में उपलब्ध है । पी सी बी और अंतिम उच्चता एस डी एच भिन्न-भिन्न ट्रिब्यूनल आदेशों के मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क के शर्तों के अधीन नहीं हो सकती है । उत्पाद परिभाषा सी ई एस टी ए टी के अनिवार्य आदेशों के उल्लंघन में है ।
- xxxi. अपीलकर्ता ने कंपनी के शेयरहोल्डिंग ढांचा के संबंध में अपनी किताब में सम्पूर्ण सूचना को प्रकट किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कर्मचारी संघ जो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा धारित शेयर के ट्रस्टी थी और यूनियन सूचना को साझा करने की इच्छुक नहीं थे, के सम्पूर्ण खातों का आग्रह किया है ।

- xxxii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कर्मचारी संघ को एक अलग विधिक सत्ता के रूप में माना है, अभी विपरीत निर्णय दिया है।
- xxxiii. एक भिन्न विधिक सत्ता द्वारा सूचना को प्रकट न करने के अपीलकर्ता के हित में निर्णयपूर्व पूर्व विचारित के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- xxxiv. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जब पी सी एन के विभिन्न उप क्षेत्रों के साथ निजी दस्तावेजों का सत्यापन किया तो कोई गलती नहीं पाई गई। निर्दिष्ट प्राधिकारी की ओर से उस अपील को निपटाना गलत था जिसमें उसने आंकड़ों में बार-बार संशोधन किया गया था।
- xxxv. सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार पी सी एन विवरण का प्रत्येक उप क्षेत्र के संबंध में सत्यापन किया गया था। अपीलकर्ता ने 15 डिजिट प्रणाली को बिना किसी संशोधन के अपनाया, अपीलकर्ता ने विवरण की एक पूरी सूची दी है जिसका अपनी जरूरतों के अनुसार पी सी एन के प्रत्येक उप क्षेत्र को डिनोटिंग करने के लिए उपयोग किया गया है। सूचित पी सी एन और उपर्युक्त दस्तावेजों के बीच विवरण में कोई अंतर नहीं है, अपीलकर्ता ने अपने पास उपलब्ध संभावित सूचना को उपलब्ध कराया है अभी निर्यात कीमत को इस आधार पर अस्वीकार किया गया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए सूचना आदर्श नहीं थी।
- xxxvi. अपीलकर्ता के लिए एक अलग पाटन मार्जिन था। पाटन मार्जिन के निर्धारण के लिए अपनाई गई प्रणाली के संदर्भ में किसी स्पष्टीकरण के अनुसार निर्धारण न करना अथवा नियम 17(2) और नियम 17(3) द्वारा लगाए गए सांविधिक अपेक्षाओं के प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
- xxxvii. क्षति निर्धारण परीक्षा मानक उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल रहा है (क) आवाज और आंकड़ा मैगजीन पर आधारित पाटित आयातों की मात्रा (ख) समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों का प्रभाव (ग) इन आयातों का अनुवर्ती प्रभाव।
- xxxviii. निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात का विश्लेषण करने में असफल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में क्षमता के साथ कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है और जब बाजार में नई वस्तु आती है तो कीमत उच्च होते हैं। तेजस एक नई कंपनी है जबकि अपीलकर्ता कई दशकों से स्थापित है।
- xxxix. क्षमता और क्षमता उपयोग की उचित तौर पर जांच भी नहीं की गई है चूंकि ई एम एस वेंडर भारत के अंदर स्थित हैं अथवा भारत से बाहर की जांच नहीं की गई है।
- xl. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों में उल्लेख किया है कि घरेलू उद्योग के घाटे में घरेलू प्रचालन में घाटा हुआ, उनका समग्र लाभ सकारात्मक बना हुआ है क्योंकि निर्यात ने घाटे का वित्त

पोषण किया जबकि अपीलकर्ता ने यह तर्क उजागर किया कि लाभ में वृद्धि दर्ज हुई है लेकिन निर्यातों में गिरावट हुई है।

- xli. निर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित कारकों के उद्देश्यपरक मूल्यांकन करने में असफल रहे हैं अपने विश्लेषण में आयात मात्रा, पाटित कीमतों पर नहीं बेची गई है, की जांच होने चाहिए, जबकि निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस संबंध में मानना है कि उसने अन्य देशों से आयातों की मात्रा का मूल्यांकन नहीं किया है।
- xlii. यद्यपि संबद्ध देश से औसत कीमत, किसी भी तरह कीमत कटौती को प्रदर्शित नहीं करते हैं प्रतिवादी सं० 1 ने निर्धारण किया है कि पी सी एन से पी सी एन आधार पर तुलना करने पर महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है।
- xliii. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उत्पादकों के बीच किसी तरह की प्रतिस्पर्धा की जांच नहीं की है।
- xliv. निर्दिष्ट प्राधिकारी के आवेदन में तेजस द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा के संबंध में सूचना की जांच करने में असफल रहे हैं।
- xlvi. निर्यात निष्पादन और उत्पादकता का भी विश्लेषण नहीं किया गया।
- xlvi. बिना किसी उचित कारण के कीमत कटौती को अस्वीकार करना अवांछनीय है।
- xlvi. डी जी ए डी से हुआवेई, चीन का दूसरा सत्यापन दौरा करने का अनुरोध किया है क्योंकि पहले का दौरा पूर्वाग्रहित था।
- xlvi. सुनवाई आयोजित करने और इसको बुलाने के ढंग के संबंध में 18 जनवरी, 2011 के पत्र द्वारा आपत्ति उठाई गई थी (असाधारण तौर पर अल्पकालीन सूचना दी गई थी)।
- xlix. डी जी ए डी से अनुरोध है कि वे सभी दस्तावेजों वाली विविध सूचिबद्ध सार्वजनिक फाइल उपलब्ध कराना है।
- 1. डी जी ए डी से अनुरोध है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस एल पी की निपटान अंतिम जांच परिणाम जारी न करे।
- ii. जहाँ तक "उद्गम" को परिभाषित करने की मुद्दे का संबंध है निम्नलिखित संगत है:-

क. भरोसेमंद दूरसंचार उपकरण विनिर्माण नीति (12 अप्रैल, 2011) मात्र नीति का मसौदा है।

ख. किसी पाटनरोधी जांच में उद्गम का पता लगाने के लिए दूर-संचार नीति का सहारा लेना अपेक्षित नहीं है।

ग. नीति को उल्लेखानुसार भौतिक संपदा में विनिर्माण कार्यकलाप शामिल नहीं है।
घ. निर्दिष्ट प्राधिकारी की शक्ति के दायरे में उद्गम नियम बनाना नहीं आता है। यह वित्त मंत्रालय सीमाशुल्क अधिसूचना के जरिए करता है।

ङ. इन सीमाशुल्क अधिसूचनाओं में उत्पाद का उद्गम निर्धारित करने के लिए "मूल्यवर्धन मानदंड" सीमाशुल्क वर्गीकरण में परिवर्तन और "उत्पाद" के स्वरूप में परिवर्तन का प्रावधान है। आवेदक का अनुरोध है कि उसकी इस भ्रामक दावे का संगठन करने के लिए इन कारकों की अनदेखी की जा जाये कि वह घरेलू उद्योग है न कि आयातक है।

च. दूरसंचार नीति के विपरीत पाटनरोधी कानून का उद्देश्य भौतिक संपदा की सुरक्षा करना नहीं है बल्कि उत्पाद की घरेलू विनिर्माता की रक्षा करना है।

lii. मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की निर्णयों को देखते हुए आवेदक को घरेलू उद्योग से बाहर रखना अपेक्षित है क्योंकि वह विचाराधीन उत्पाद का आयात करता है।

liii. पांडिचेरी फैक्ट्री ने जांच अवधि के बाद काफी समय तक प्रचालन नहीं किया। निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पांडिचेरी फैक्ट्री की सत्यापन की तारीखें घोषित नहीं की गयीं।

liv. डी जी ए डी से बंगलोर स्थित मुख्यालय के प्रथम दौरे और पांडिचेरी के कथित दूसरे दौरे की सत्यापन रिपोर्टों के अगोपनीय रूपांतरण का अनुरोध किया गया।

lv. याचिका भारत में आयातों से संबंधित है (i) चार्ट तारीख औरय अवधि, स्रोत से रहित है (ii) पृष्ठ 49-50 में बीजक एवं टाटा मैगजिन को पुनः उद्धृत किया गया/बनाया गया है। पहले ये अपठनीय में और आयात की कोई मात्रा, आधार नहीं दिया गया है (iii) पृष्ठ 51 में मात्रा के बिना अनुमान दर्शाया गया है (iv) पृष्ठ 52 में मूल्य, आधार या जोन के बिना आयात के आंकड़े दर्शाया गया है।

lvi. उत्पादों की संख्या, जांच शुरूआत से पूर्व (निर्दिष्ट प्राधिकारी और माननीय उच्चतम न्यायालय) अलग-अलग की गयी थी। घरेलू आयात आंकड़ों में परिवर्तन नहीं किया गया था।

lvii. जहाँ तक मौखिक अनुरोध का संबंध है, उन्होंने अनुरोध किया है कि जो प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं करते हैं उन्हें सूचना के अभाव में घरेलू उत्पादक/हितबद्ध पक्षकार/घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता।

lviii. जहाँ तक निर्यात कीमत की गलत अवधारणा का संबंध है, अनुरोध है कि मूल प्रश्नावली में दी गयी निर्यात कीमत अपरिवर्तित है जिसका इस स्पष्ट सत्यापन जांच दल (तीन अधिकारियों के नेतृत्व में)

किया था। ई सी आई ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट किया कि निर्यात सौदों के नमूने 13 अक्टूबर, 2010 को सही ढंग से सूचित किये गये थे। अंतिम जांच परिणाम के पैरा 169 में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उल्लेख किया। "..... ई सी आई ने भी इस आशय का साक्ष्य दिया कि आयात आंकड़ों में सूचित मात्रा नहीं है।"

- lix. जहाँ तक एम ई टी का संबंध है, अनुरोध है कि एच ई टी सी ने यह सिद्ध किया है कि वह ई सी आई इजराइल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और उसका प्रबंधन राज्य के हस्तक्षेप से पूर्णतः मुक्त ई सी आई जांच अवधि में सूचीकरण विनियमों से आबद्ध नासदाक में एक सूचीबद्ध कंपनी थी। जांच दल ने मौके पर सत्यापन के दौरान एम ई टी दर्जा प्रदान करने के लिए सभी संगत तथ्यों की जांच की। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कई अन्य पाटनरोधी मामलों में चीन की निजी स्वामित्व वाली कंपनियों को एम ई टी प्रदान किया।
- lx. निर्यातकों ने घरेलू उद्योग के सुझाव के अनुसार पी. सी. एन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) स्वीकार की और अपनी रिपोर्टों में तदनुसार परिवर्तन किया। तथापि निर्दिष्ट प्राधिकारियों ने अपनी अंतिम जांच परिणाम में सही ढंग से ये दर्ज किया कि निर्यातित वस्तु का विवरण और कीमत अपरिवर्तित है।
- lxi. सामान्य मूल्य की गणना में जहां पी. सी. एन प्रणाली नहीं अपनाई गयी वहाँ निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पाटन मार्जिन की गणना में त्रुटि की।
- lxii. प्राधिकारी ने पी. सी. एन प्रणाली के अनुसार निर्यात कीमत निकालने में अपनायी गयी पद्धति के प्रतिकूल घरेलू बाजार/तीसरे देशों में संयोजन/उप-संयोजन वार बिक्री कीमत ली है।
- lxiii. जहाँ तक शेष पी. सी. एन हेतु सामान्य मूल्य की निर्धारण का संबंध है, सामान्य मूल्य की घटना में अपनाई गई प्रणाली निर्यात कीमत के निर्धारण में असंगत है।
- lxiv. ऐसा प्रतीत होता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पी. सी. एन के लिए घरेलू भाड़े, करों आदि हेतु समायोजन किये बिना सकल बिक्री कीमत ली है जिनकी बिक्री घरेलू बाजार में की गयी थी।
- lxv. प्राधिकारी ने 5% के समुचित लाभ पर विचार न करके सहयोगी निर्यातकों को दंडित किया है, जिसे जिन सहयोगी निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार से वंचित किया गया है उन पर विचार किया गया था।
- lxvi. निर्यात कीमत में एलीमेंट/एम्बेडेड सॉफ्टवेयर कीमत पर विचार नहीं किया गया है। सॉफ्टवेयर एस डी एफ उपस्कर में एक निर्णायक निविष्टि होने के कारण निर्यात कीमत की गणना करते समय इसके पूरे प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए।
- lxvii. घरेलू उद्योग क्षति मानदंडों हेतु पी. सी. एन आधार पर आंकड़े उपलब्ध कराने में असफल रहा है।

- lxviii. हितबद्ध पक्षकारों से संबंधित पाटन मार्जिन के आंकड़ों की गणना का प्रकटन किया जाना चाहिए ।
चूंकि ये उनके स्वयं के आंकड़े हैं अतः इन्हें गोपनीय नहीं रखा जा सकता है ।
- lxix. घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।
- lxx. भारत में घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित न किए गए उत्पादों पर शुल्क लगाया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी का निष्कर्ष था कि भारत को 522 पी सी एन का निर्यात किया गया था और उत्पादों में से केवल 139 पी सी एन की तुलना घरेलू उद्योग के साथ की गई थी । आयातकों/अंतिम प्रयोक्ताओं से संबंधित आंकड़े दर्शाते हैं कि उनके द्वारा आयातित उत्पादों में से अनेक उत्पाद घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित नहीं हैं/उनकी आपूर्ति नहीं की जा सकती है ।
- lxxi. प्रतिवादी सं० 2 ने कहा है कि तुलना के आधार के रूप में घरेलू उद्योग द्वारा आवेदित तुलनात्मक रूप से निचले मॉडल को प्रयुक्त किया गया है और उसने आगे कहा है कि निर्यातकों के लिए पहुँच कीमत घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्तित इसी उपस्कर की बिक्री कीमत से पर्याप्ततः कम है ।
- lxxii. सेरागॉन द्वारा माइक्रोवेव रेडियो टर्मिनलों का निर्यात किया जाता है जिसके साथ एस डी एच ट्रांसमिशन उपस्कर से एस टी एम-1 इंटरफेस जुड़ा हो सकता है । यह इंटरफेस रेडियो और एस डी एफ उपस्कर के बीच संपर्क बनाने के लिए भौतिक माध्यम के रूप में कार्य करता है । इस बात पर जोर दिया गया है कि यह महज एक इंटरफेस है और एस डी एच ट्रांसमिशन उपस्कर की किसी अपेक्षा को पूरा नहीं करता है । इस प्रकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे में संशोधन करने और एस टी एम-1 इंटरफेस युक्त उत्पादों के साथ सेरागॉन के उत्पादों को इस दायरे से बाहर रखने का अनुरोध किया गया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी को इन उत्पादों को जांच के दायरे से बाहर रखने का पूरा विवेकाधिकार है ।
- lxxiii. एस टी एम-1 इंटरफेस युक्त आर ए डी उत्पादों/मॉड्यूलों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है क्योंकि वे एस डी एच वातावरण में कार्य नहीं करते हैं और इनका प्रयोग रक्षा, रेलवे तथा उनके संयंत्रों के निजी कैपस नेटवर्कों अथवा निजी नेटवर्कों में डार्क फाइबर के माध्यम से आंकड़ों और ध्वनि यातायात का संप्रेषण करने के लिए किया जाता है । इन उत्पादों में से अनेक एस डी एच वातावरण में आंकड़ों/ध्वनि यातायात का संचरण नहीं करते हैं क्योंकि उनका प्रयोग ट्रांसमिशन नेटवर्कों के "प्रचालन एवं अनुस्क्षण" हेतु केवल "मॉनीटरिंग/प्रोब" उपकरणों के रूप में किया जाता है । अतः इन उत्पादों/मॉड्यूलों का एस डी एच ट्रांसमिशन के समान अंतिम प्रयोग नहीं किया जाता और इन्हें तेजस द्वारा विनिर्मित उत्पादों के "समान उत्पाद" नहीं माना जा सकता है । इसी प्रकार एस टी एम-4 इंटरफेसों को भी दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए ।
- lxxiv. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस जांच का विरोध करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से खंडन करने की अपेक्षा करना गलत है । पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(1) के अनुसार जब आवेदक प्रारंभ में अपने दायित्व का निर्वहन कर देता है तभी इस मामले में खंडन करने का दायित्व प्रतिवादी पक्षकारों पर आता है ।

- lxxv. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणामों में पुर्जों और संघटकों को उत्पाद के दायरे से सुगमतापूर्वक बाहर कर दिया था ताकि तेजस को आयातक नहीं कहा जा सकता । याचिकाकर्ता 95% हिस्सों और संघटकों का आयातक है ।
- lxxvi. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने चीन जन गण से किए गए आयातों के प्रतिशत के रूप में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा भारत में किए गए कार्यकलापों का सारांश दिया है और यह कहा है कि तेजस संघटकों का आयात कर रहा है अर्थात् बोर्ड बनाता है, सॉफ्टवेयर विकसित करता है और सोल्वरिंग कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग करता है ।
- lxxvii. यदि विनिर्माण-पूर्व लागतों को छोड़ दिया जाता है तो तेजस की कुल लागतों में बहुत बड़ा अनुपात आयातों का होगा । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि तेजस स्वयं एक प्रमुख आयातक है ।
- lxxviii. तेजस चीन से अधिकांश कच्चे माल का आयात कर रहा है और इसे थाईलैंड के रास्ते ला रहा है । ऐसा वह "घरेलू उद्योग" शब्द के दायरे के भीतर रहने के लिए करता है ।
- lxxix. कानून ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को इतना विवेकाधिकार प्रदान नहीं किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी पक्षकार को घरेलू उद्योग घोषित करे, चाहे वह विनिर्माता होने के मूल मानदंडों को भी पूरा नहीं कर सकता हो । इसके अलावा "कतिपय परिस्थितियों" के साथ साक्ष्य दिया जाना जरूरी है और इसे निर्दिष्ट प्राधिकारी को दिया गया मनमाना अधिकार नहीं माना जा सकता है ।
- lxxx. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम में हिस्सों और संघटकों को इस आधार पर दायरे से बाहर रखा है कि इनके अनेक प्रयोग हैं और केवल एस डी एच उपस्कर में ही उनका एकमात्र उपयोग नहीं है । इस आधार पर अन्य एस डी एफ उपस्कर जैसे डिजिटल क्रॉस कनेक्ट, पोपुलेटेड पी सी बी, ब्रॉड बैंड अथवा सेल्युलर उपकरण के पुर्जों के रूप में लगा एस डी एच उपस्कर, सॉफ्टवेयर आदि भी दायरे से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इन सबके विविध उपयोग हैं और केवल एस डी एच उपस्कर में इन्हें प्रयुक्त नहीं किया जाता ।
- lxxxi. तेजस के लगभग 95% आयातों में पुर्जों और संघटकों शामिल हैं । इस प्रकार पुर्जों और संघटकों को संबद्ध वस्तुओं के दायरे से बाहर रखना असुविधाजनक प्रतीत होता है ।
- lxxxii. प्राधिकारी द्वारा चीन को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों का व्यवहार प्रदान करना मनमाने स्वरूप का है । किसी भी अर्थव्यवस्था को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करने के लिए प्रत्येक मामले में विशिष्ट निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाने चाहिए । विगत में प्रदान किया गया व्यवहार किसी भी अर्थव्यवस्था को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करने का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है । इसके अलावा, एक सामान्य नियम के तौर पर भी किसी देश के साथ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नत्थी नहीं किया जा सकता है । गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से संबंधित निष्कर्ष गलत है ।

lxxxiii. यू टी स्टारकॉम एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी है और इसे चीन सरकार द्वारा कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की गई है।

lxxxiv. यू टी स्टारकॉम के निर्णय (कीमतों, लागत एवं निविष्टि, प्रौद्योगिकी एवं मजदूरी, उत्पादन, बिक्री तथा निवेश से संबंधित) आपूर्ति एवं मांग दर्शाने वाले बाजार के संकेतों के अनुसार किए जाते हैं और इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है।

lxxxv. यू टी स्टारकॉम के पास आधारभूत लेखांकन रिकॉर्डों का पूरा संग्रह उपलब्ध है जिनकी लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार की जाती है।

lxxxvi. एक सामान्य नियम के तौर पर भी किसी देश के साथ गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नत्थी नहीं किया जा सकता है। डब्ल्यू टी ओ अथवा दिशानिर्देशों में कहीं भी चीन को हमेशा के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था नहीं बताया गया है।

lxxxvii. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी नए जांच परिणाम में पी टी एन का विवेचन नहीं किया जाना चाहिए।

lxxxviii. यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी कोई जांच परिणाम (अंतिम जांच परिणाम सहित) जारी करते हैं जिसमें पी टी एन का विवेचन किया गया है, तो ऐसे जांच परिणाम सीस्टेट के समक्ष की गई अपील के निर्णय के अधधीन होने चाहिए।

lxxxix. जहाँ तक सूचना को छिपाने (निर्यात सौदे) और असहयोग करने का संबंध है, निवेदन किया जाता है कि:

xc. यह झूठा, निराधार और स्वार्थप्रेरित है।

xci. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 2 से 5 जून, 2010 तक मौके पर जाकर सत्यापन किया था और आंकड़ों को सही स्वीकार किया था।

xcii. निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष संलग्न हैं।

xciii. दिनांक 29.10.2010 को किया गया अंतिम निर्धारण अंतिम और बाध्यकारी है (विचाराधीन उत्पाद के अर्थ के भीतर पी टी एन को शामिल करने को छोड़कर, जिसे सीस्टेट के समक्ष चुनौती दी गई है)।

xciv. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उत्पादन पर विचार करते समय अप्रासंगिक कार्यकलापों (अनुसंधान, उत्पाद अवधारणा, डिजाइन एवं ड्राइंग, प्रौद्योगिकी का विकास, कार्यात्मकता, सॉफ्टवेयर का विकास) का हवाला दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2006 (202) ई एल टी 23 (एस

सी)]: "घरेलू उद्योग" के निर्धारण के प्रयोजनार्थ विनिर्माण प्रक्रिया को शामिल करना प्रासंगिक नहीं है।

xcv. अंतिम जांच परिणाम में सार्वजनिक हित के तर्क को नजरअंदाज किया गया है। ए डी डी एक विशिष्ट सत्ता होगी और किसी प्रकार बी एस एन एल जैसे सार्वजनिक उपक्रम और बड़े टेलीकॉम सेवा प्रदाता की तुलना में भी थाईलैंड में भी सत्ताएं होंगी। तेजस ने एस टी एम 64, एस टी एम 256 और डी एक्स सी उपस्करों पर भी शुल्क का अनुरोध किया है जिसकी आपूर्ति वह घरेलू मांग को पूरा करने के लिए नहीं कर सकता है।

xcvi. विचाराधीन उत्पाद को अंतिम जांच परिणाम में पर्याप्ततः संशोधित कर दिया गया है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या क्षति, सामान्य कीमत और पाटन मार्जिन का परिकलन करते समय विचाराधीन उत्पाद के संशोधित दायरे पर विचार किया गया था।

xcvii. सिएना के उत्पाद - कोर डायरेक्टर एंड 5400 (ऑप्टिकल क्रॉस कनेक्ट होने के कारण) याचिकाकर्ता के उत्पादों से बिल्कुल भिन्न है और विचाराधीन उत्पाद के समान उत्पाद भी है। अतः सिएना के उत्पादों को उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना जरूरी है क्योंकि याचिकाकर्ता अथवा घरेलू उद्योग द्वारा इसके समान उत्पाद उत्पादित नहीं किया जाता है और कोर डायरेक्टर एंड 5400 के आयातों से किसी क्षति की संभावना नहीं हो सकती है।

xcviii. कोर डायरेक्टर/5400 ऑप्टिकल क्रॉस कनेक्ट के उत्पाद परिवार से संबंधित है और कंट्रोल प्लेन बेस्ड नेटवर्किंग इंटेलिजेंस के पैमाने, बहुप्रौद्योगिकी उपयोग में उल्लेखनीय भिन्नता होने के कारण अंतिम जांच परिणाम के पैरा 36 के अंतर्गत उल्लिखित उत्पाद नहीं है।

xcix. प्राधिकारी से कोर डायरेक्टर एंड 5400 को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखने और उन उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों को जिनका विनिर्माण याचिकाकर्ता द्वारा नहीं किया जाता है, बाहर रखने के लिए अंतिम जांच परिणामों से संबंधित टिप्पणियों में आवश्यक संशोधन करने का अनुरोध किया जाता है।

c. सिएना के उत्पादों को चीन जन गण (अथवा इजराइल) के मूल के उत्पादों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है क्योंकि चीन से बाहर पर्याप्ततः रूपांतरण एवं पर्याप्ततः मूल्यवर्धन किया जाता है।

ci. इस बात को मानकर कि वास्तविक विनिर्माण अमहत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं। याचिकाकर्ता वास्तव में भारत में सेवाओं के पाटन का आरोप लगा रहा है, जो कानून के अंतर्गत अनुमत्य नहीं है।

cii. निर्यातक प्रश्नावली में सूचना प्रस्तुत किए जाने के बावजूद सिएना की पाटन मार्जिन का आकलन नहीं किया गया है। सिएना में प्राधिकारी से यू एस ए में अपने संयंत्र का दौरा करने का अनुरोध

किया था परन्तु निर्दिष्ट प्राधिकारी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। यह सूचित नहीं किया गया कि उनके निवेदनों में कोई कमी पाई गई है। उन्होंने प्राधिकारी से सिएना हेतु पाटन मार्जिन एवं क्षति रहित मार्जिन के निर्धारण का अनुरोध किया है।

- ciii. सिएना के उत्पाद (कोर डायरेक्टर एंड 5400) "चीन के बाहर के मूल के" होने के तथ्य का खंडन घरेलू उद्योग द्वारा नहीं किया गया है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

10. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिकांश हितबद्ध पक्षकारों ने दिनांक 21.12.2009 को की गई पिछली मौखिक सुनवाई के बाद प्रस्तुत किए गए अपने तर्कों को दोहराया है। इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की जाँच की गई थी और अंतिम जांच परिणाम में उनका विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। तथापि प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पुनः प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। इनका ब्यौरा वर्तमान प्रकटन विवरण में आवश्यक समझी गई सीमा तक दिया गया है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

11. विचाराधीन उत्पाद के दायरे का विस्तृत विवरण विगत में जारी अंतिम जांच परिणाम और इसके शुद्धिपत्र में दिया गया है और यह इस प्रकार है:

" सिंक्रोनस डिजीटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण, अर्थात् एस टी एम-1, एस टी एम-4, एस टी एम-16, एस टी एम-64, एस टी एम-256 जो संयोजित रूप में, सी के डी, एस के डी रूप में हैं, उसके संयोजन और उप संयोजन अथवा जो आकस्मिक ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण से फिट किए गए हैं। विचाराधीन उत्पाद में एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, (ए डी एम), (केवल एस डी एच अनुप्रयोग हेतु), मल्टीपल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर (एम ए डीएम) तथा डिजीटल क्रॉस-कनेक्ट, (डी एक्स सी) (केवल एस डी एच अनुप्रयोग हेतु), पापुलेटेड सर्किट बोर्ड, (केवल एस डी एच अनुप्रयोग हेतु), और उपकरण अथवा उसके संयोजनों/उप संयोजनों के साथ आयात किए जाने पर उपकरण के भाग के रूप में आयातित पुर्जे/संघटक भी शामिल होंगे। विचाराधीन उत्पाद में इन उपकरणों के अभिन्न भाग और जिसकी खरीद उपकरण के भाग के रूप में या पृथक रूप में की जा सकती है, एस डी एच के लिए नियम साफ्टवेयर भी शामिल होगा। तथापि, एकल आधार पर आयातित संघटक/पुर्जे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं। "

****टिप्पणी-2** - एस डी एच उपकरण से अनिवार्यतः ऑप्टिकल फाइबर के जरिए संकेतों का प्रेषण होता है। ऐसा एस डी एच उपकरण से हो सकता है जो विद्युत कॉपर माध्यम या माइक्रोव रेडियो तरंगों के जरिए प्रेषण के लिए नियत हो। केवल ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही आंकड़े प्रेषित करने वाले एस डी एच उपकरण पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा।

****टिप्पणी-3** - जब एस डी एच का आयात अंतिम ब्रोड बैंड/सेलुलर उपकरण के भाग के रूप में किया जाएगा तो पाटनरोधी शुल्क आयातों के केवल एस डी एच भाग पर ही संदेय होगा । इसी प्रकार जब अंतिम ब्रोड बैंड/सेलुलर उपकरण का आयात एस डी एच उपकरण के भाग के रूप में किया जाएगा तो पाटनरोधी शुल्क आयातों के केवल एस डी एच भाग पर ही संदेय होगा ।

****टिप्पणी-4-** पी डी एच, सी उब्ल्यू डी एम, डी डब्ल्यू डी एम, माइक्रोवेव प्रणाली, जीपीओएन, डीएसएलएएम, एम एस ए एन, बी आई टी एस, रूटर, पी टी एन, पी डी एस एन, एसजीएसएन, एमजीडब्ल्यू, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, ओएनटी, एचएलआर, एचएसएस तथा एसडीएच न देने के कारण एम आर पी और उसका कोई स्वरूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं और इसलिए इन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा ।

****टिप्पणी-5-** ऐसे माइक्रोवेव रेडियो टर्मिनल पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बाहर हैं जिनमें एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए एस डी एम-1 इंटरफेस हो और जो रेडियो तथा एस डी एच उपकरण के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु वास्तविक माध्यम के रूप में कार्य करते हों ।

12. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद एस डी एच प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा निर्मित अनिवार्य ट्रांसमिशन उपकरण है । अंतिम ग्राहक की जरूरत को पूरा करने के लिए इसका उत्पादन कई विनिर्देशनों में किया जा सकता है । इसके अलावा, उच्चतर संस्करण/उच्च क्षमता के उपकरण तैयार करना इस उद्योग में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया/घटना है । जांच से यह पता चला है कि यद्यपि एस डी एम 64 उपकरण विकसित किए जा चुके हैं और ग्राहकों ने टेलीकॉम नेटवर्क (यद्यपि सीमित रूप में) में इन्हें लगाना शुरू कर दिया है तथापि, जहां तक भारतीय बाजार का संबंध है, एस डी एम 256 जांच अवधि के दौरान विकास के चरण में था ।

13. विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बारे में कई तर्क दिए गए हैं । विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद और मामले के तथ्यों तथा विधिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं :

- i. यह आवश्यक और उचित होगा कि मामला दर मामला आधार पर और कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के अर्थ पर विचार किया जाए । उत्पादन की सार्वभौमिक परिभाषा उचित नहीं होगी । वस्तुतः विभिन्न कानूनों और विनियमों में उत्पादन को अलग-अलग अर्थ में परिभाषित/मान्य किया गया है जैसा कि अलग-अलग कानूनों में उत्पादन के अलग-अलग अर्थ/व्याख्याओं से स्पष्ट होता है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि उत्पादन के अर्थ पर विशिष्ट कानून एवं नियमों, उनमें दी गई विशिष्ट परिभाषाओं और व्याख्याओं तथा जिस प्रयोजन के लिए कानून बनाया गया है, उस प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विचार करना अपेक्षित है । उदाहरणार्थ वर्तमान मामले में पाटनरोधी शुल्क के प्रयोजनार्थ यह मानना नितान्त अनुचित होगा कि कोई कंपनी मात्र इस वजह से घरेलू उत्पादक है कि वह कुछ वृद्धिकारी उत्पादन कार्यकलाप कर रही है । वस्तुतः ऐसी किसी व्याख्या से कानून अप्रचलित बन जाएगा । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि किसी कंपनी को घरेलू उत्पादक मात्र इस वजह से नहीं माना जा सकता कि उसने उत्पाद शुल्क का भुगतान किया है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत वस्तु को उस स्थिति में उत्पादित माना जाता है भले ही उत्पाद को पूरा करने के लिए प्रासंगिक या सहायक कार्यकलाप किए गए हों जिसमें उपभोक्ता के लिए उस उत्पाद को विपणनीय बनाने हेतु संबद्ध वस्तु की खुदरा बिक्री कीमत की घोषणा या परिवर्तन या उसके अनुकूलन या किसी अन्य अभिक्रिया सहित किसी यूनिट कंटेनर में पैकिंग या पुनः पैकिंग अथवा कंटेनरों की लेबलिंग या पुनः लेबलिंग शामिल है। तथापि, पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे कार्यकलाप उत्पादन के लिए पर्याप्त हैं। इससे भारी पुनरावृत्ति होगी और आयातों या घरेलू उत्पादन में दोहरी गणना होगी।

- ii. पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी यह मानते हैं कि वस्तु को उसी स्थिति में उत्पादित माना जाएगा यदि निविष्टि का उत्पादन की प्रक्रिया में "पर्याप्त रूपांतरण" हुआ हो। वस्तु की परिभाषा के बारे में जांचकर्ता प्राधिकारियों की सर्वाधिक स्वीकृत परंपरा यह है कि भौतिक एवं तकनीकी गुणधर्मों, उत्पादन प्रौद्योगिकी, विनिर्माण प्रक्रिया, संयंत्र एवं उपकरण, कार्य एवं उपयोग, कीमत, उपभोक्ता अवधारणा और सी. शु. वर्गीकरणों जैसे मापदंडों पर विचार किया जाए। इन मापदंडों का उपयोग इस बात पर विचार करने के लिए किया जाता है कि क्या दोनों वस्तुएं समान या अलग वस्तुएं हैं। इसके अलावा, कोई वस्तु उत्पादन की लघु या दीर्घ प्रक्रिया अपनाने के बाद अंततः उत्पादित की जा सकती है और उस चरण से अंततः रूपांतरित किए जाने से पूर्व जिससे वह निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए उत्पादित की जा सकती है से अंततः रूपांतरित किए जाने से पूर्व एक अथवा अधिक चरणों उत्पादित की जा सकती है। यदि कुछ निविष्टियों पर मध्यवर्ती चरणों में कार्रवाई की गई है जहां उसका कोई उपयोग नहीं है (और कोई कार्य नहीं कर सकती है) परंतु उसकी अंतिम उत्पाद में खपत होती है तो मध्यवर्ती उत्पाद को वस्तु माना जा सकता है भले ही वह उक्त चरण पर बिक्री योग्य हो। निविष्टि इन मापदंडों के अनुसार उत्पादन से विशेष तौर पर अलग हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि एस डी एच उपकरण या संयोजनों/उप संयोजनों, जिनका उत्पादन एस डी एच उपकरण बनाने की उत्पादन प्रक्रिया के दौरान होता है, के उत्पादन और बिक्री को वर्तमान प्रयोजनार्थ विशेष रूप से अलग उत्पाद माना जा सकता है।

- iii. प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता और विदेशी उत्पादकों द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलापों के स्वरूप की विस्तार से जांच की। मौके पर सत्यापन अन्य बातों के साथ-साथ विशेष रूप से इस पहलू पर केन्द्रित रहा। प्राधिकारी ने इस संबंध में विभिन्न हितबद्ध पार्टियों के तर्क पर विचार किया है। इस बारे में प्राधिकारी निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उत्पादन क्या है और एस डी एच उपकरण के विनिर्माण में किस प्रकार के उत्पादन कार्यकलापों को शामिल करना अपेक्षित है। एस डी एच उपकरण के निर्माण में शामिल विभिन्न चरण निम्नानुसार हैं।

अनुसंधान >>उत्पाद परिकल्पना >> डिजाइन एवं ड्राइंग>> प्रौद्योगिकी विकास >> कार्यचालनात्मकता की परिकल्पना और उसकी समझ >>उत्पाद का ब्लू प्रिंट तैयार करना >> संबद्ध साफ्टवेयर का विकास >>उत्पाद के प्रोटोटाइप का विकास-हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर

>> संघटक की खरीद >> डिजाइन के अनुसार बोर्ड/कार्ड की पापुलेटिंग >> सोल्डरिंग तथा ई एम एस कार्यकलाप >> एकीकरण >> टेस्ट जिग तैयार करना >> संयोजन >> परीक्षण >> उत्पाद सहायता एवं बग फिक्स ।

iv. प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उपर्युक्त उत्पादन कार्यकलाप एस डी' एच उपकरण के विनिर्माण में अपेक्षित होते हैं । हालांकि यह माना जाता है कि कंपनी को प्रत्येक कार्यकलाप नहीं करना होता है । यह संभव है कि इनमें से कुछ कदमों में ऐसी एक या अधिक उप प्रक्रिया शामिल हो, जो स्वतंत्र रूप से की जा सकती है अथवा इनमें से कुछ प्रक्रियाएं कुछ कंपनी द्वारा समेकित रूप से की जा सकती हैं अथवा इसके अलावा वर्तमान मामले में किसी कंपनी को तब तक विचाराधीन उत्पादक की उत्पादक नहीं माना जा सकता जब तक वह इन कार्यकलापों के अधिकांश भाग का निष्पादन न कर रही हो ।

14. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणाम में यथापरिभाषित और अंतिम जांच परिणाम में पूर्व में अधिसूचित तथा प्रकटन विवरण में विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा की है । प्राधिकारी ने भारत में याचिकाकर्ता और ऐसे अन्य पक्षकारों सहित विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए कार्यकलापों की स्थिति का भी विश्लेषण किया है जिन्होंने स्वयं को विचाराधीन का उत्पादक और विदेशी उत्पादक होने का दावा किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निर्णयोपरांत दूसरी मौखिक सुनवाई से संबंधित अनुरोधों में कोई नया पर्याप्त तथ्य सामने नहीं लाया गया है और इसलिए प्राधिकारी अंतिम जांच परिणाम में पूर्व में अधिसूचित और परिभाषित विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र के बारे में अपने पूर्ववर्ती जांच परिणाम को बरकरार रखते हैं ।

15. जहां तक तेजस द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलाप की प्रकृति का संबंध है, प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती अंतिम जांच परिणाम में यह माना था कि तेजस वर्तमान प्रयोजन के लिए घरेलू विनिर्माता हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में निर्णयोपरांत दूसरी मौखिक सुनवाई से संबंधित अनुरोधों में कोई नया पर्याप्त तथ्य सामने नहीं लाया गया है और इसलिए प्राधिकारी इस संबंध में पूर्ववर्ती जांच परिणाम को बरकरार रखते हैं ।

16. जहां तक पृथ्वी और वी एम सी एल का संबंध है, इन कंपनियों ने उनके द्वारा किए जा रहे उत्पादन कार्यकलापों का सत्यापनीय साक्ष्य प्रदान नहीं किया है । भारत में पृथ्वी और वी एम सी एल द्वारा प्राधिकारी को उपलब्ध सूचना के अनुसार किए गए उत्पादन कार्यकलाप संयोजन, जांच, उत्पाद सहायता और बगफिक्स हैं । इन कंपनियों ने सत्यापनीय साक्ष्य के साथ याचिकाकर्ता के इस दावे का खंडन नहीं किया है कि ये कंपनियां भारत में केवल संयोजन प्रचालन कर रही हैं और ऐसे कार्यकलाप वर्तमान उत्पाद में अति महत्वपूर्ण कार्यकलाप हैं । उन्होंने याचिकाकर्ता के इस दावे का खंडन नहीं किया है कि उनके मामले में निविष्टि का उत्पादन में "पर्याप्त" रूपांतरण नहीं होता है । कंपनी द्वारा खपत की गई निविष्टि विशिष्ट प्रकार, विशिष्ट कार्य/उपयोग की नहीं होती है और उनका उपयोग विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में किया जाता है ।

17. प्राधिकारी ने सियना द्वारा किए गए कार्यकलापों की भी जांच की है जिसने यह दावा किया है कि वह चीन से संघटकों की खरीद कर रही है और सियना के लिए विनिर्माण या संयोजन का कुछ भाग अमरीका के

उत्पादों से भी आउट सोर्स किया जाता है जिसका निष्पादन चीन में सनमाइना एस सी आई द्वारा किया जाता है और वह चीन में उदगम वाले उत्पादों के रूप में पात्र नहीं है । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि सिएना द्वारा उत्पादित वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क तब तक लागू रहेगा जब तक वह विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में आती है और जब तक भारत में ऐसी वस्तु के आयात जांचाधीन संबद्ध देशों के उदगम या वहां से निर्यातित नहीं होते हैं ।

18. जांच से यह पता चला है कि जांच अवधि के दौरान एस डी एच उपकरणों के निम्नलिखित प्रकारों का या तो उपयोग हो रहा था या उनका विकास किया जा रहा था । प्राधिकारी ने इनमें से कुछ प्रकारों को अलग रखने के बारे में हितबद्ध पार्टियों के तर्कों पर विचार किया और इस संबंध में निम्नानुसार मत व्यक्त किया :-

i. एस टी एम-1,4,16- इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि इन उत्पादों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सही ढंग से शामिल किया गया है ।

ii. एस टी एम-64- हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने वाणिज्यिक मात्रा में एस टी एम-64 को नहीं उतारा है । यह भी तर्क दिया गया है कि सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के प्रचालक (बी एस एन एल) ने याचिकाकर्ता से एस टी एम-64 की खरीद नहीं की है । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि एस टी एम-64 निम्नलिखित कारणों से विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सही ढंग से शामिल किया गया है ।

(अ) तेजस ने एस टी एम-64 का उत्पादन कर भारतीय एवं घरेलू बाजारों में उसकी बिक्री की है जैसा कि जांच दल के जरिए प्राधिकारी ने सत्यापन किया है ।

(ब) तेजस ने निर्यात बाजार में कुछ मात्रा की बिक्री की है तो उस उत्पाद प्रकार को अलग नहीं रखा जा सकता क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के तथ्य की पुष्टि होती है (कंप्राधिकारी नोट करते हैं कि नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2 (ख) का तात्पर्य यह है कि घरेलू उद्योग ने समान वस्तु का विनिर्माण किया है। इस बात की अपेक्षा करना अनावश्यक है कि घरेलू उद्योग को घरेलू बाजार में समान वस्तु की बिक्री करनी चाहिए थी ।) याचिकाकर्ता के परिसरों पर किए गए मौके पर सत्यापन के दौरान वस्तुतः वाणिज्यिक मात्रा में एस टी एम-64 के उत्पादन का पता चला अर्थात् क्विकटेल के लिए भी ।

iii. एस टी एम-256- जाहिर तौर पर जांच अवधि के दौरान एस टी एम-256 का न तो आयात किया गया है और न ही घरेलू उद्योग ने आपूर्ति की है । याचिकाकर्ता और विदेशी उत्पादकों की परिसरों पर की गई जांच से यह पता चला कि एस टी एम-256 का उल्लेख नए किस्म के एस डी

एच उपकरण के रूप में किया जा सकता है । जांच से यह पता नहीं चला कि यदि एस टी एम-256 का विदेशी उत्पादकों ने निर्यात किया है तो घरेलू उद्योग ने एस टी एम-256 को नहीं उतारा है । वस्तुतः हितबद्ध पार्टियां इस बात से सहमत हैं कि एस टी एम-256 का उपयोग करने हेतु तकनीकी अनुमोदन/अनुमति की प्रणाली देश में मौजूद ही नहीं है । प्राधिकारी ने यह पाया है कि किसी विशेष प्रकार को अलग रखने के दावे को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका संगत अवधि के दौरान भारत को निर्यात न किया गया हो क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु की आपूर्ति न किए जाने के तथ्य की पुष्टि तब तक नहीं की जा सकती जब तक उस प्रकार का भारत को निर्यात न किया गया हो । प्राधिकारी नोट करते हैं कि टी एम-256 के अपवर्जन को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई आधार नहीं दिया गया है । इसके अलावा, जांच दल को तेजस द्वारा विनिर्मित और बंगलौर स्थित उनके परिसरों में उपलब्ध टी एम-256 उपकरण को दिखाया गया था । तेजस ने यह प्रदर्शित किया कि उसने उत्पाद के विकास हेतु भारी निवेश (*** करोड़ रूपए) किया है और यह दावा किया कि इस उपकरण की बिक्री तभी की जा सकती है जब पार्टी उसके लिए ऑर्डर प्रस्तुत करे । भारत में किसी उपभोक्ता ने एस डी एच -256 की आपूर्ति हेतु घरेलू उद्योग कोई आर्डर नहीं दिया है ।

iv.. डिजिटल क्रॉस कनेक्ट - हितबद्ध पार्टियों ने बार-बार डिजिटल क्रॉस कनेक्ट को अलग रखने का तर्क दिया । जांच में यह पता चला है कि डिजिटल क्रॉस कनेक्ट वस्तुतः ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग दूर संचार नेटवर्क में किया जाता है जिससे उच्चस्तरीय संकेतों के बीच पुनः व्यवस्थित तथा अंतर-संबंधित करने के लिए निम्न स्तरीय संकेत प्राप्त होते हैं । डिजिटल क्रॉस कनेक्ट का उत्पादन एस डी एच प्रौद्योगिकी तथा अन्य प्रौद्योगिकियों में किया जा सकता है । एस डी एच प्रौद्योगिकी का डिजिटल क्रॉस कनेक्ट उपकरण स्पष्टतः एस डी एच उपकरण हैं । जांच दल द्वारा सत्यापित रिकॉर्ड से यह सिद्ध होता है कि एस डी एच प्रौद्योगिकी के डिजिटल क्रॉस कनेक्ट का उत्पादन किया गया है और याचिकाकर्ता ने जांच अवधि के दौरान उसकी आपूर्ति की है । क्षति संबंधी सूचना और क्षति मार्जिन के निर्धारण में शामिल लागत एवं कीमत सूचना में एस डी एच प्रौद्योगिकी के डिजिटल क्रॉस कनेक्ट का उत्पादन और बिक्री शामिल है । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि एस डी एच प्रौद्योगिकी का डिजिटल क्रॉस कनेक्ट सही ढंग से विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल है । तथापि, चूंकि डिजिटल क्रॉस कनेक्ट का उत्पादन अन्य प्रौद्योगिकी में भी होता है, इसलिए बेहद सावधानी के रूप में यह स्पष्ट किया जाता है कि अन्य प्रौद्योगिकियों का डिजिटल क्रॉस कनेक्ट विचाराधीन उत्पाद और वर्तमान जांच के दायरे में नहीं आता है ।

v. एस डी एच उपकरणों का एस के डी/सी के डी स्वरूप - हितबद्ध पार्टियों ने व्यापक रूप से यह स्वीकार किया है कि एस डी एच का एस के डी/सी के डी स्वरूप सही ढंग से विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आता है । ऊपर उल्लिखित उत्पादन प्रक्रिया से यह देखा जाएगा कि यह उत्पाद कई कारणों, संघटकों का संयोजन है, संयोजन एवं उप संयोजन है । इस बात की प्रबल संभावना है कि उत्पाद की ढुलाई एस के डी/सी के डी स्वरूप में की जाती है । वस्तुतः उत्पाद का बीजक सामान्यतः केवल एस के डी/सी के डी स्वरूप में किया जाता है । उत्पादक "पूर्णतः कार्यचालनात्मक तथा प्रचालनात्मक" एस डी एच उपकरण के लिए बीजक तैयार नहीं करते हैं । एस के डी/सी के डी स्वरूप से उत्पादन प्रक्रिया अत्यंत कम होती है, संयोजन प्रचालन हेतु केवल सक्रू ड्राइवर प्रौद्योगिकी की जरूरत होती है । वस्तुतः यह संभव है (और वस्तुतः यह परंपरा व्यापक रूप से अपनाई जाती है)

कि सर्वप्रथम आवश्यक जांच आदि सहित पूर्ण उपकरण का उत्पादन किया जाए और तैयार रूप में भेजने के बजाए इसे एस के डी/सी के डी स्वरूप में खंडित करने के बाद भेजा जाए । इस प्रकार ऐसे एस के डी/सी के डी के निर्यात विचाराधीन उत्पाद के ही निर्यात माने जाते हैं । वस्तुतः उत्पाद का पोत परिवहन चीन जन.गण. से इस एस के डी/सी के डी स्वरूप में किया गया है । अतः प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि उत्पाद के क्षेत्र में उत्पाद का एस के डी/सी के डी स्वरूप शामिल है ।

vi. संयोजन और उप संयोजन - चीन जन.गण. और इजराइल के विभिन्न निर्यातकों के रिकॉर्डों के सत्यापन से यह पता चला कि उपकरण का पोत परिवहन संयोजनों और उप-संयोजनों के रूप में किया जाता है और इनमें से प्रत्येक संयोजनों/ उप संयोजनों की कीमत अलग-अलग निर्धारित की जाती है किसी इकाई के रूप में संयोजनों/ उप संयोजनों के रूप में आयाजित उपकरण विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में आता है ।

vii. पापुलेटिड सर्किट बोर्ड/कार्ड - कार्ड/पीसीबी को विनिर्माता द्वारा तैयार की गई डिजाइन के अनुसार पापुलेटिड किया जाता है और तत्पश्चात् साफ्टवेयर डालने के अलावा, उन्हें केवल रोलफ में व्यवस्थित करने और एक सर्किट में समायोजित करने की जरूरत होती है । चूंकि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर विनिर्माता का स्वामित्व होता है, इसलिए ये विचाराधीन उत्पाद के दायरे में आते हैं । तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि पीसीबी या कार्ड एस डी एच उपकरण से इतर किसी उत्पाद के उत्पादन/संयोजन हेतु नियत होने की स्थिति में वे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं । पी सी बी और कार्ड विचाराधीन उत्पाद के दायरे में तभी आते हैं जब ऐसे पीसीबी या कार्ड एस डी एच उपकरण के उत्पादन के लिए हों ।

viii. पुर्जे एवं संघटक - हितबद्ध पार्टियों ने पुर्जों और संघटकों को विचाराधीन उत्पाद में शामिल करने का भारी विरोध किया है । हितबद्ध पार्टियों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि (क) पुर्जे/संघटक अलग उत्पाद हैं (2) घरेलू उद्योग ने पुर्जों तथा संघटकों की पेशकश नहीं की है । (3) पुर्जे/संघटकों के चरण से उत्पादन काफी अधिक होता है और वस्तुतः यही उत्पादन है । (4) पुर्जे/संघटकों पर पाटनरोधी शुल्क लगाना उचित नहीं है अथवा इससे कार्यान्वयन के चरण पर उत्पीड़न हो सकता है और न्यायोचित न होने पर भी शुल्क वसूली की मांग उठ सकती है । इसके विपरीत घरेलू उद्योग ने इस आधार पर पुर्जों और संघटकों को शामिल करने की मांग की है कि उन्हें अलग रखे जाने से उल्लंघन की बड़ी गुंजाइश बन जाएगी । उन्होंने यह दलील दी है कि "कच्ची सामग्री" अथवा "निविष्टि" के रूप में संघटकों के आयात को संघटक रूप में एस डी एच के आयातों से अलग तथा विशिष्ट रूप में रखा जाना चाहिए (सीमाशुल्क जांच/नियंत्रण/निकासी के बिना आपूर्त आई पी आर सहित) । उन्होंने आगे यह नोट किया है कि घरेलू उद्योग निविष्टि के रूप में संघटकों के आयात के विरुद्ध नहीं है । घरेलू उद्योग चीन के उन्हीं आई पी आर का उपयोग करते हुए संघटकों के रूप में उत्पाद का आयात करने और तत्पश्चात् भारत में उत्पाद का संयोजन करने के खिलाफ है क्योंकि इसे अलग रूप में सतत पाटन माना जाता है । प्राधिकारी ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि घरेलू उद्योग द्वारा पुर्जों और संघटकों का विनिर्माण नहीं किया जाता है क्योंकि पुर्जों और संघटकों का घरेलू उद्योग से प्राधिकारी का सरोकार नहीं है । प्राधिकारी आगे यह नोट करते हैं कि एस डी एच उपकरण में प्रयुक्त पुर्जों और संघटकों का विविध उपयोग होता है और इनका केवल एस डी एच में

ही उपयोग नहीं होता है। पुर्जों और संघटकों के उपयोग के ब्यौरों की जानकारी लेने के बाद प्राधिकारी का यह मत है कि अकेले आयात किए जाने की स्थिति में पुर्जों और संघटकों को शामिल किए जाने से समूचा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु उद्योग कठिनाई में पड़ सकता है।

ix. अन्य उपकरण के भाग के रूप में एस डी एच उपकरण - प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अंततः ब्राड बैंड या सेल्युलर उपकरण का भाग है। ऐसे ब्राड बैंड या सेल्युलर उपकरण के भाग के रूप में एस डी एच उपकरण का आयात किए जाने की प्रबल संभावना है। यदि विचाराधीन उत्पाद के दायरे में ऐसे ब्राड बैंड या सेल्युलर उपकरण के भाग स्वरूप एस डी एच उपकरण के आयात को शामिल नहीं किया जाता है तो वर्तमान जांच करने की समूची प्रक्रिया और प्रस्तावित उपाय नाकाम हो जाएंगे। इसके अलावा, किसी हितबद्ध पार्टी ने इस आशय का कोई स्वयंसेवित आधार नहीं दिया है कि ऐसे आयात पर शुल्क क्यों नहीं लिया जाना चाहिए। हितबद्ध पार्टी की एकमात्र चिंता यह हो सकती है कि सीमाशुल्क पतन प्राधिकारियों को समूचे ब्राड बैंड या सेल्युलर उपकरण पर पाटनरोधी शुल्क की मांग नहीं करनी चाहिए। अतः यह स्पष्ट दिया जाता है कि शुल्क का क्षेत्र केवल ऐसे ब्राड बैंड/सेल्युलर उपकरण में शामिल एस डी एच उपकरण के मूल्य तक सीमित होगा। शुल्क की सभी समूचे उपकरण तक विस्तारित नहीं होगी। आयातकों से आशा है कि वे इस आशय की घोषणा करें और सीमाशुल्क पतन प्राधिकारियों से आशा की जाती है कि वे एस डी एच उपकरण के मूल्य का पता लगाने/विभाजन करने में पूर्ण सावधानी बरतें।

x. सॉफ्टवेयर - सॉफ्टवेयर विचाराधीन उत्पाद का एक अभिन्न भाग है क्योंकि उपकरण ऐसे सॉफ्टवेयर के बिना कार्य कर ही नहीं सकता। ऐसे सॉफ्टवेयर को स्वयं उत्पादक द्वारा तैयार किया जा सकता है अथवा उत्पादक इसे अन्य एजेंसियों से तैयार करवा सकता है। यह संभावना है कि ऐसे सॉफ्टवेयर का बीजक उपकरण के भाग के रूप में अथवा अलग से तैयार किया जाए। विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर को शामिल करना उचित है और प्राधिकारी इसकी पुष्टि करते हैं।

xi. बी डब्ल्यू डी एम - कई हितबद्ध पार्टियों ने बी डब्ल्यू डी एम को अलग रखने की मांग की है। बी डब्ल्यू डी एम एक अलग प्रौद्योगिकी वाला ट्रांसमिशन उपकरण है। यह एस डी एच प्रौद्योगिकी उपकरण नहीं है। चूंकि बी डब्ल्यू डी एम एस डी एच प्रौद्योगिकी उपकरण नहीं है, इसलिए यह वर्तमान जांच और प्रस्तावित उपायों में नहीं आता है। तथापि, हितबद्ध पार्टियों के बार-बार तर्कों और सीमाशुल्क पतन प्राधिकारियों द्वारा भविष्य में पाटनरोधी शुल्क की संभावित मांग के दावे को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि बी डब्ल्यू डी एम ट्रांसमिशन उपकरण विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं और उन पर कोई पाटनरोधी शुल्क देय नहीं है।

19. याचिका, जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना, पूर्व में अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणामों, अंतिम जांच परिणामों, वर्तमान निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई के समय घरेलू उद्योग और विरोधी हितबद्ध पार्टियों के तर्कों तथा निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई के बाद हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र निम्नानुसार है:

" सिंक्रोनस डिजीटल हाइआर्की ट्रांसमिशन उपकरण, अर्थात् एस टी एम-1, एस टी एम-4, एस टी एम-16, एस टी एम-64, एस टी एम-256 जो संयोजित रूप में, सी के डी, एस के डी रूप में हैं, उसके संयोजन और उप संयोजन अथवा जो आकस्मिक ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण से फिट किए गए हैं । विचाराधीन उत्पाद में एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर, (ए डी एम), (केवल एस डी एच अनुप्रयोग हेतु), मल्टीपल एड ड्रॉप मल्टीप्लेक्सर (एम ए डीएम) तथा डिजीटल क्रॉस-कनेक्ट, (डी एक्स सी) (केवल एस डी एच अनुप्रयोग हेतु), पापुलेटेड सर्किट बोर्ड, (केवल एस डी एच अनुप्रयोग हेतु), और उपकरण अथवा उसके संयोजनों/उप संयोजनों के साथ आयात किए जाने पर उपकरण के भाग के रूप में आयातित पुर्जें/संघटक भी शामिल होंगे। विचाराधीन उत्पाद में इन उपकरणों के अभिन्न भाग और जिसकी खरीद उपकरण के भाग के रूप में या पृथक रूप में की जा सकती है, एस डी एच के लिए नियम साफ्टवेयर भी शामिल होगा । तथापि, एकल आधार पर आयातित संघटक/पुर्जे विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं । "

****टिप्पणी-2** - एस डी एच उपकरण से अनिवार्यतः ऑप्टिकल फाइबर के जरिए संकेतों का प्रेषण होता है । ऐसा एस डी एच उपकरण से हो सकता है जो विद्युत कॉपर माध्यम या माइक्रोव रेडियो तरंगों के जरिए प्रेषण के लिए नियत हो । केवल ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही आंकड़े प्रेषित करने वाले एस डी एच उपकरण पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाएगा ।

****टिप्पणी-3** - जब एस डी एच का आयात अंतिम ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण के भाग के रूप में किया जाएगा तो पाटनरोधी शुल्क आयातों के केवल एस डी एच भाग पर ही संदेय होगा । इसी प्रकार जब अंतिम ब्रॉड बैंड/सेल्युलर उपकरण का आयात एस डी एच उपकरण के भाग के रूप में किया जाएगा तो पाटनरोधी शुल्क आयातों के केवल एस डी एच भाग पर ही संदेय होगा ।

****टिप्पणी-4-** पी डी एच, सी डब्ल्यू डी एम, डी डब्ल्यू डी एम, माइक्रोवेव प्रणाली, जीपीओएन, डीएसएलएएम, एम एस ए एन, बी आई टी एस, रूटर, पी टी एन, पी डी एस एन, एसजीएसएन, एमजीडब्ल्यू, बीटीएस, बीएससी, एमएससी, ओएनटी, एचएलआर, एचएसएस तथा एसडीएच न देने के कारण एम आर पी और उसका कोई स्वरूप विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं और इसलिए इन पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होगा ।

****टिप्पणी-5-** ऐसे माइक्रोवेव रेडियो टर्मिनल पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बाहर हैं जिनमें एस डी एच ट्रांसमिशन उपकरण के लिए एस डी एम-1 इंटरफेस हो और जो रेडियो तथा एस डी एच उपकरण के बीच संपर्क स्थापित करने हेतु वास्तविक माध्यम के रूप में कार्य करते हों ।

पी सी एन प्रणाली

20. विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री अलग-अलग कई प्रकारों में की जाती है । अलग-अलग प्रकारों का उत्पादन विशिष्ट ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है । सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना करने के लिए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद को ट्रांसमिशन क्षमता, क्रॉस कनेक्ट क्षमता, ई 1 इंटरफेस, इलेक्ट्रिकल इंटरफेस, ऑप्टिकल इंटरफेस,

आप्टिक टाइप आदि जैसे मापदंडों के आधार पर अलग-अलग प्रकारों में विभाजित किया है । प्राधिकारी ने 15 अंकों वाली एक उत्पाद नियंत्रण प्रणाली (पी सी एन) तैयार की है । सभी हितबद्ध पार्टियों को प्रत्येक पी सी एन के लिए अलग से लागत तथा कीमत संबंधी सूचना देने का निर्देश दिया गया था । तथापि, हितबद्ध पक्षकारों को उचित औचित्य के बाद सुझाई गई पी सी एन प्रणाली से हटने की स्वतंत्रता दी गई थी ।

21. कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने प्रस्तावित पी सी एन प्रणाली का विरोध किया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद अनिवार्यतः कई इलेक्ट्रॉनिक कार्डों का संयोजन और उप संयोजन है । वस्तुतः उत्पादक उत्पाद के एस के डी/सी के डी/कार्ड/उप संयोजन के रूप में बिक्री बीजक तैयार करना चाहते हैं । जांच से यह पता चला है कि समस्त कंपनियां उत्पाद की डिजाइन और विकास हेतु समान प्रणाली अपनाती हैं जिसके लिए समान उत्पाद कोडिंग प्रणाली का पालन किया जाता है । विचाराधीन उत्पाद के इस पहलू पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को देखते हुए पी सी एन प्रणाली निर्धारित की है और उसकी मंशा विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अभिज्ञान योग्य तथा तुलनीय बनाने की थी । ऐसा करते समय प्राधिकारी ने समस्त प्रतिवादी निर्यातकों को यह स्वतंत्रता प्रदान की कि वे पी सी एन प्रणाली को तैयार करने के बारे में कोई अन्य सुझाव दें जो प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित प्रणाली से इतर प्रणाली को न्यायोचित ठहराते हों । इस संबंध में सभी हितबद्ध पार्टियों को अलग-अलग पत्र भेजा गया था । तथापि, जांच में भाग लेने वाले सभी निर्यातकों ने प्राधिकारी द्वारा सुझाई गई पी सी एन पद्धति को स्वीकार कर लिया और उन्होंने उक्त पी सी एन पद्धति के अनुसार आंकड़े प्रस्तुत किए । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच के लिए अपनाई गई पी सी एन प्रौद्योगिकी सही सिद्ध हुई है और वह समस्त हितबद्ध पार्टियों, खासकर उन प्रतिवादी निर्यातकों के लिए स्वीकार्य बन गई है, जिन्होंने इस पद्धति पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की है और इस पी सी एन पद्धति के आधार पर अपने आंकड़ों का सत्यापन कराया है । प्राधिकारी हितबद्ध पार्टियों के इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ है कि प्रस्तावित पी सी एन प्रणाली अत्यधिक जटिल है और निर्यातक पी सी एन प्रणाली के मददेनजर सही ढंग से आंकड़े नहीं दे सकता । प्राधिकारी यह मानते हैं कि निर्यातक को जांच की शुरुआत के चरण पर प्रश्नावली का उत्तर देते समय ऐसी प्रचालनात्मक कठिनाइयों का संकेत देना चाहिए था । मौके पर सत्यापन के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी सत्यापन रिपोर्ट का उत्तर देते समय ऐसा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

घरेलू उद्योग का आधार तथा क्षेत्र

22. विभिन्न हितबद्ध पार्टियों ने निम्नानुसार तर्क दिए हैं :-

- i. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का स्वयं एक उत्पादक है ।
- ii. याचिकाकर्ता विचाराधीन उत्पाद का स्वयं एक आयातक है ।
- iii. नियम 2(ख) के अंतर्गत विवेकाधिकार का उपयोग अलग-अलग पार्टियों के लिए अलग-अलग ढंग से नहीं किया जा सकता ।

- iv. नियमों में संबद्ध देशों और असंबद्ध देशों से हुए आयातों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है।
- v. नियमों में आयातों की मात्रा के बारे में कोई संख्यात्मक फार्मूला नहीं दिया गया है।
- vi. याचिकाकर्ता द्वारा थाइलैंड से आयातित वस्तु में ऐसे पुर्जे/संघटक शामिल हो सकते हैं जिन्हें अंततः चीन जन.गण. से प्राप्त किया गया हो और विचाराधीन उत्पाद में पुर्जे/संघटक शामिल होने के कारण याचिकाकर्ता को अपात्र घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए।

23. रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी ने अनंतिम रूप से यह निर्धारित किया कि (क) वर्तमान जांच के प्रयोजनाथ याचिकाकर्ता के उत्पादन कार्यकलाप उत्पादन हैं (ख) याचिकाकर्ता के आयात ऐसी मात्रा में नहीं हैं जिससे याचिकाकर्ता नियम 2(ख) के दायरे से बाहर हो जाए। (ग) पृथ्वी और वी एम सी एल जैसे अन्य घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के आयात ऐसे हैं जिससे नियम 2(ख) के अंतर्गत वे अपात्र घरेलू उत्पादक बन जाते हैं। (घ) याचिकाकर्ता का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है। इस आधार पर प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि याचिका में आधार की पूर्ति होती है और याचिकाकर्ता नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

24. मै. तेजस नेटवर्किंग लि. को घरेलू उद्योग मानने के दावे का विरोध करते समय विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया कि मै. तेजस नेटवर्किंग लि. को इन तथ्यों के मद्देनजर घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने की अयोग्य माना जाना चाहिए कि (1) तेजस ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद के भाग स्वरूप कुछेक संघटकों का आयात किया है (ख) "घरेलू उद्योग के रूप में पात्रता रखने के लिए घरेलू उत्पादक को "प्रमुख अनुपात" की सीमा तक उत्पाद के विनिर्माण में संलग्न होना चाहिए अर्थात् उत्पादक को यह प्रदर्शित करना चाहिए कि वह समस्त आवश्यक पुर्जों, विचाराधीन उत्पाद की सहायक सामग्री और संघटकों का विनिर्माण करता है" (ग) डी जी ए डी ने पृथ्वी और वी एम सी एल को पात्र विनिर्माता नहीं माना है क्योंकि वे निविष्टियों का "पर्याप्त रूपांतरण" नहीं करते हैं (घ) पाटनरोधी नियमावली में "पर्याप्त रूपांतरण" की कोई अवधारणा नहीं है। (ङ) तेजस भी संघटक का आयात करती है फिर भी उसे पात्र घरेलू उद्योग माना जाता है जबकि पृथ्वी और वी एम सी एल को घरेलू उद्योग नहीं माना गया है (च) डी जी ए डी ने यह कहते हुए तेजस के लिए नियमों में ढील दी है कि तेजस ने दोहरे उपयोग के संघटकों का आयात किया है और इस बात पर विचार नहीं किया गया है कि तेजस संघटकों का अनन्य उपयोग करती है अर्थात् एस डी एच टेलीकॉम उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है। (छ) चीन जन.गण./इजरायल से भिन्न तीसरे देशों से हुए आयात भी आयातक के रूप में माने जाते हैं क्योंकि नियम 2(ख) के अंतर्गत आयात का देश विशिष्ट नहीं होता है और यदि तेजस चीन जन.गण. और इजरायल से भिन्न देशों से आयात करती है तो तेजस घरेलू विनिर्माता कहलाने की पात्र नहीं है। (ज) तेजस ने थाइलैंड और मलेशिया से आयात किया है।

25. घरेलू उद्योग के आधार और क्षेत्र के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों की प्राधिकारी ने विस्तार से जांच अंतिम जांच परिणाम के पैरा 41 से 66 में की है। प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि तेजस पाटनराधी नियमों के अर्थ के भीतर "घरेलू उद्योग" है।

26. जहां तक तेजस का संबंध है, प्राधिकारी ने कंपनी द्वारा किए गए उत्पादन कार्यकलापों का विश्लेषण किया है। जहां तक तेजस के आयातों का संबंध है, प्राधिकारी ने इससे संबंधित विस्तृत वास्तविक स्थिति का उल्लेख अंतिम जांच परिणाम के पैरा 50 में उल्लेख किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि तेजस द्वारा चीन से किए गए आयात, जो कंपनी द्वारा किए गए कुल आयातों के ***% हैं (कंपनी के कारोबार का ***%) वे एकल दोहरे उपयोग के संघटक हैं। प्राधिकारी ने एकल दोहरे उपयोग के संघटकों को विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में शामिल नहीं किया है। प्रातिवादी निर्यातकों के रिकॉर्डों के सत्यापन के दौरान प्राधिकारी को पृथ्वी और वी एन सी एल, दोनों द्वारा चीन से पूर्ण उपकरण के आयात के बारे में सूचना का पता चला।

27. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि जांच अवधि के दौरान तेजस की पांडिचेरी में उत्पादन सुविधाएं नहीं थीं। तेजस ने ऐसे बीजक प्रदान किए हैं जिनसे जांच अवधि के दौरान पांडिचेरी में उसकी सुविधा से उत्पाद का बीजक दर्शाया गया है। कंपनी की इस फैक्टरी का जांच अधिकारियों के दल ने दौरा किया था। इस बात की पुष्टि की जाती है कि उत्पाद के लिए अभिज्ञात उत्पादन कार्यकलाप कंपनी द्वारा देश के भीतर किए जा रहे हैं। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि तेजस जांच अवधि के दौरान पांडिचेरी में उत्पादन कार्यकलाप कर रही थी।

28. जहां तक जांच के अधीन न आने वाले तीसरे देशों से आयातों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि तीसरे देश के ऐसे आयात "आरोपित पाटित वस्तु" के आयात नहीं हैं। अतः ऐसे आयात से ऐसा घरेलू उत्पादक घरेलू उद्योग के रूप में आवेदन लाने से वंचित नहीं होना चाहिए। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यदि घरेलू उत्पादक तीसरे देश से पर्याप्त मात्रा में आयात कर रहा है तो वह कारणात्मक संबंध की मौजूदगी अथवा अन्यथा की पुष्टि के लिए प्रासंगिक हो सकता है। यदि तीसरी देशों से आयात की मात्रा नगण्य है तो वह अप्रासंगिक बन जाती है।

29. हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि असंबद्ध देशों से किए गए आयात नियम 2 (ख) के अंतर्गत अप्रासंगिक हैं और "आरोपित पाटित वस्तु" उस वस्तु से संबंधित होती है और उसे उक्त देश से संबद्ध नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी ने इस संबंध में विभिन्न विधिक उपबंधों की सावधानीपूर्वक जांच की और वे यह मानते हैं कि नियमों के अंतर्गत विभिन्न उपबंधों में प्रौद्योगिकी तथा नियम 2 (ख) में प्रदत्त अपवर्जन के उद्देश्य से यह सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि नियम 2(ख) के अंतर्गत किसी पार्टी को बाहर रखने का प्रश्न तभी उठता है जब ऐसे आयात जांचाधीन तीसरे देशों से किए गए हों। तीसरे देशों से हुए आयातों को आरोपित पाटित वस्तु के आयात नहीं माना जा सकता। इस संबंध में प्राधिकारी नियम 2 (ख) के अंतर्गत ऐसा विवरण प्रदान करने की मंशा/उद्देश्य और नियमों के अंतर्गत विभिन्न अन्य उपबंधों पर पर भरोसा करते हैं। नियम 2 और 6 के अंतर्गत पाटित वस्तु या आरोपित वस्तु का संदर्भ संबद्ध देशों के संदर्भ में ऐसे संबद्ध देशों के उत्पादक और ऐसे संबद्ध देशों से उत्पाद के आयातकों के बारे में स्पष्ट है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से जांचाधीन वस्तु के आयात ही नियम 2(ख) के अंतर्गत किसी घरेलू विनिर्माता को शामिल करने या अलग रखने के लिए प्रासंगिक हैं।

30. यह तर्क दिया गया है कि नियम 2(ख) अलग-अलग पार्टियों पर अलग ढंग से लागू नहीं किया जा सकता। आगे यह आरोप लगाया गया है कि प्राधिकारी ने तेजस को घरेलू उत्पादक की पात्रता रखने वाला और पृथ्वी तथा वी एम सी एल को घरेलू विनिर्माता की पात्रता न रखने वाला माना है। हितबद्ध विरोधी पार्टियों ने प्रारम्भिक निर्धारण का खंडन किया है और यह तर्क दिया है कि जब तेजस और पृथ्वी/वी एम सी एल दोनों ने आयात किया है तो प्राधिकारी ने भेदभावपूर्ण ढंग से नियम 2(ख) में उपलब्ध विवेकाधिकार का उपयोग किया है। विचाराधीन उत्पाद, चीन, भारतीय, तीसरे देशों के अर्थ के बारे में निर्धारण के होते हुए भी भारत, चीन जन.गण. अथवा तीसरे देशों में विनिर्मित वस्तु से यह अर्थ निकाला जाएगा की पृथ्वी और वी एम सी एल भारत में विचाराधीन उत्पाद की घरेलू विनिर्माता नहीं है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियम 2(ख) में किसी भी हालत में स्वयं आयात करने वाले घरेलू उत्पादकों को शामिल करने या अलग रखने के बारे में किसी एकीकृत निर्णय लेने का प्रावधान नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि ऐसे विवेकाधिकार का उपयोग मामला दर मामला आधार पर करना अपेक्षित है। अलग-अलग पार्टियाँ, अलग-अलग कारणों से उत्पाद का आयात कर सकती हैं। अलग-अलग पार्टियों द्वारा आयात की मात्रा/सीमा अलग-अलग हो सकती है। नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू विनिर्माता को शामिल करने या न करने की बात कुछेक कारणों पर आधारित होती है। चूंकि स्वयं कारण पार्टी दर पार्टी अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए विवेकाधिकार के सार्वभौमिक उपयोग को न तो कानून में स्वीकार किया जाता है और न ही ऐसा करना उचित होगा। इस संबंध में प्राधिकारी तथा अन्य जांच प्राधिकारियों की परंपरा से भी प्राधिकारी के विचारों को समर्थन मिलता है।

31. हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि तेजस ने निर्विवाद रूप से ई एम एस की सेवाओं का उपयोग किया है। ऐसी ई एम एस कंपनियाँ चीन जन.गण. से पुर्जों/संघटकों की खरीद कर सकती हैं, जिनका मूल्य विवेकाधिकार का उपयोग करने में प्राधिकारी द्वारा भरोसेमंद आयात की मात्रा में शामिल नहीं किया गया हो सकता है। प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के पैरा 56 में इससे संबंधित वास्तविक स्थिति का उल्लेख किया है। इसके अलावा, ये आयात दोहरे उपयोग के पुर्जे और संघटक अथवा एकल संघटक हैं, जो "विचाराधीन उत्पाद" के दायरे से बाहर हैं। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि विरोध करने वाली विरोधी हितबद्ध पार्टियों का यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।

32. यह आरोप लगाया गया है कि यद्यपि, कई अन्य विनिर्माता हैं, तथापि तेजस को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के क्षेत्र के भीतर कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा रखने वाली कंपनी के रूप में आवश्यक आधार रखने वाला माना गया है। इस संदर्भ में प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि जांच की शुरुआत के बाद आरंभ में पृथ्वी और वी एम सी एल के अलावा, अपने अनुरोधों में पृथ्वी तथा वी एम सी एल दोनों द्वारा रेखांकित तथाकथित कोई अन्य विनिर्माता घरेलू विनिर्माता की हैसियत का दावा करने के लिए आगे नहीं आया है। तथापि, कथनात्मक रूप में इस आशय का दावा करने के अलावा वे अपने विनिर्माण कार्यकलापों के बारे में कोई सूचना देने के लिए आगे नहीं आए। पृथ्वी/वी एम सी एल ने घरेलू उत्पादक अथवा विचाराधीन उत्पाद के आयातक के रूप में निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रश्नावली का उत्तर नहीं दायर किया है। प्राधिकारी द्वारा इन कंपनियों को निर्धारित ढंग से और प्रपत्र में सूचना प्रदान करने की सलाह देने के बाद भी इन हितबद्ध पार्टियों ने संगत सूचना प्रदान नहीं है। इन्होंने अन्यथा यह दावा करने के अलावा, अपनी संरचना के बारे में

कोई ब्यौरा/आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया कि वे विनिर्माता हैं क्योंकि वे उत्पाद शुल्क का भुगतान भी करते हैं । पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार इस प्रयोजनार्थ महज उत्पाद शुल्क के भुगतान से "विनिर्माता" का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन दोनों कंपनियों ने नियम 6(8) के अर्थ के भीतर सहयोग नहीं किया है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि यद्यपि, कोई हितबद्ध पार्टी अपना तर्क दे सकती है, तथापि ऐसी हितबद्ध पार्टी के लिए यह अनिवार्य है कि वह प्राधिकारी के अनुरोधानुसार ऐसी सूचना प्रदान करे और सत्यापन हेतु स्वयं को उपस्थित रखे । इन कंपनियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के इस मामले में की गई समूची प्रक्रिया काफी आसान रही होती, यदि हितबद्ध पार्टियों ने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई संगत सूचना प्रदान कर दी होती और उन्होंने मौके पर सत्यापन के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर दिया होता । इन हितबद्ध पार्टियों के सुविचारित असहयोग को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने इस संबंध में उपलब्ध सामग्री पर भरोसा किया है । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना से निम्नानुसार पता चलता है ।

- i. हितबद्ध पार्टियों ने जांच अवधि की समाप्ति तक एस डी एच उपकरण की बिक्री नहीं है ।
- ii. प्राधिकारी ने अनुसंधान, उत्पाद परिकल्पना, डिजाइन व ड्राइंग, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद परिकल्पना, डिजाइन एवं ड्राइंग, प्रौद्योगिकी विकास, कार्यचालनात्मकता की परिकल्पना एवं समझ, उत्पाद का ब्लू प्रिंट तैयार करने, संबद्ध साफ्टवेयर के विकास, उत्पाद के प्रोटोटाइप के विकास-हार्डवेयर व साफ्टवेयर, संघटक खरीद, सोल्डरिंग तथा ई एम एस कार्यकलाप, एकीकरण, टेस्ट जिग की तैयारी, संयोजन, परीक्षण तथा उत्पाद सहायता एवं बग फिक्सेज जैसे कार्यकलापों को अनिवार्य उत्पादन कार्यकलाप के रूप में अभिज्ञात किया । ये हितबद्ध पार्टियां प्राधिकारी द्वारा सूचीबद्ध ये उत्पादन कार्यकलाप नहीं करती हैं, जिनमें वर्तमान मामले में उत्पादन में शामिल कार्यकलाप शामिल हैं । यह सिद्ध नहीं किया गया है कि ये पार्टियां संयोजन प्रचालन भी करती हैं । रिकॉर्ड में इन कंपनियों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन और बिक्री करने का कोई साक्ष्य नहीं है । उत्पाद शुल्क के भुगतान के बार-बार तर्क के बाद भी इन हितबद्ध पार्टियों ने यह सिद्ध नहीं किया है कि उक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान एस डी एच उपकरण के बारे में किया गया था । याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि उक्त उत्पाद शुल्क का भुगतान विभिन्न उत्पादों पर किया गया हो सकता है । इन हितबद्ध पार्टियों ने यह प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि उत्पाद शुल्क का भुगतान वस्तुतः विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और निकासी के लिए किया गया है ।
- iii. ये हितबद्ध पार्टियां यह सिद्ध करने में विफल रही हैं कि उन्होंने विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन के लिए अपेक्षित अनुसंधान एवं विकास, संयंत्र एवं उपकरण तथा अन्य सुविधाओं में निवेश किया है । इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि केवल विचाराधीन उत्पाद से संबंधित कार्यकलाप प्राधिकारी के लिए संगत हैं । इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अन्य कार्यकलाप, यदि कोई हों, नितांत अप्रासंगिक हैं । इस संबंध में यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि उनके खुद के रिकॉर्ड के अनुसार वी एम पी एल व पृथ्वी सहित कुछेक हितबद्ध पार्टियों ने डी डब्ल्यू डी एम को "विचाराधीन उत्पाद" माना है । अतः यह सिद्ध नहीं किया गया है कि क्या विनिर्माता की आरोपित स्थिति डी डब्ल्यू डी एम अथवा एस डी एच उपकरण के संभावित उत्पादन व बिक्री की वजह से बनी है । प्राधिकारी नोट करते हैं

कि ऐसे मामले में इन कंपनियों ने उत्पादन सुविधाएं स्थापित की हैं और तत्पश्चात् डी डब्ल्यू डी एम उपकरण का उत्पादन कर उसकी बिक्री की है। इसलिए वे वर्तमान के प्रयोजनार्थ और वर्तमान विचाराधीन उत्पाद हेतु उत्पादक की हैसियत का दावा करने की पात्र नहीं है।

- iv. प्रारंभिक जांच परिणाम जारी होने के बाद फिब्रॉकॉम विचाराधीन उत्पाद का विनिर्माता होने का दावा करते हुए उसने यह दावा किया कि वह विचाराधीन उत्पाद के दायरे में न रखे जाने की स्थिति में संघटकों से संबंधित याचिका का समर्थन करती है। तथापि, उसने विनिर्माता होने के दावे के बारे में प्राधिकारी को कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं कराया है। याचिकाकर्ता ने जांच शुरुआत के पूर्व चरण में याचिका के साथ सी एम ए आई (एसो.), का एक पत्र दायर किया था। सी एम ए आई ने यह उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा बनता है। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ इसे प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य माना गया था।

33. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह नोट किया कि हितबद्ध पार्टियों द्वारा नार्वे से फेंड सालोमन से संबंधित मामले में पैनल की रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों में यह नोट करते हैं कि इस मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। संदर्भाधीन मामले में ई सी ने इस बात की जांच नहीं की थी कि क्या संबद्ध उत्पाद का उत्पादक न माने गए उत्पादकों द्वारा किए गए कार्यकलाप ऐसे कार्यकलाप हैं जिनमें उत्पादन माना जा सकता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि डब्ल्यू टी ओ पैनल द्वारा पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 4.1 की दी गई व्याख्या का दायरा इस कार्यवाही में सीमित है। इस संबंध में रिपोर्ट का पैरा 7.115 प्रासंगिक है:

7.115 इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि फ्लेटिड सलमोन इस मामले में ई सी द्वारा अभिज्ञात समान उत्पाद के दायरे में आता है। इस प्रकार अनुच्छेद 4.1 की साधारण भाषा की हमारी व्याख्या के आधार पर हम यह मानते हैं कि ऐसे किसी उद्यम को समान उत्पाद का "उत्पादक" और इस प्रकार घरेलू उद्योग का भाग माना जाना चाहिए जिसने कम से कम पहली बार समान उत्पाद या उसके किसी रूप का उत्पादन किया है।

पाद टिप्पणी 289 में निम्नानुसार उल्लेख है:

289. ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें ऐसा कोई उद्यम जिसका उत्पाद समान उत्पाद के दायरे में आता है, इतने कम स्तर पर कार्यकलाप में संलग्न पाया जा सकता है ताकि इस निष्कर्ष को औचित्यपूर्ण ठहराया जा सके कि वह वस्तुतः समान उत्पाद का "उत्पादन" नहीं करता है तथापि, जांच के दौरान घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय केवल फ्लेटिंग कार्यकलाप की मात्रा पर विचार नहीं किया गया था। अतः हमारे समक्ष इस मामले के तथ्यों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं है। (जोड़ दिया गया)

34. अतः पैनल ने ऐसी कुछेक परिस्थितियों (पाद टिप्पणी 289 में उल्लिखित) की परिकल्पना की जिसके बारे में पैनल ने यह सहमति व्यक्त की कि वे उत्पाद के "उत्पादक" के रूप में किसी कंपनी पर विचार करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता । तथापि, पैनल ने इस आशय का निर्णय नहीं लिया कि किसी कंपनी को कब घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता है और कब उसे विचाराधीन उत्पाद का मात्र आयातक माना जा सकता है । पैनल ने इस बात पर भरोसा नहीं किया कि किसी कंपनी का उत्पादक के रूप में उल्लेख करने के लिए पर्याप्त कार्यकलाप क्या हैं और न ही पैनल ने "उत्पादन" के अर्थ का उल्लेख किया । वर्तमान मामले में विचाराधीन सुस्पष्ट मुद्दा यह है कि उत्पादन किसे कहते हैं और घरेलू उत्पादक किसे माना जा सकता है ।

35. उपर्युक्त के मद्देनजर नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग की परिभाषा और रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि वी एम सी एल और पृथ्वी वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ स्वयं को विचाराधीन उत्पाद का घरेलू उत्पादक सिद्ध करने में विफल रही हैं । उसके अलावा ये कंपनियां ये सिद्ध करने में भी विफल रही हैं कि उन्हें नियम 2(ख) के अर्थ के अंतर्गत घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए ।

36. जहां तक तेजस का संबंध है, प्राधिकारी ने तेजस द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के स्वरूप की विस्तार से जांच अंतिम जांच परिणाम के पैरा 31 में की है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि केवल तीसरे देशों से हुए उत्पाद के आयात वर्तमान प्रयोजनार्थ संगत हैं । तेजस द्वारा थाइलैंड से किए गए आयात की वजह से वह घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने से वंचित नहीं हो जाती है । प्राधिकारी यह मानते हैं कि कंपनी का प्रमुख कार्यकलाप भारत में विनिर्माण है, जिसमें उत्पादन कार्यकलाप में अनिवार्य अनुसंधान एवं डिजाइन तथा विकास शामिल है । याचिकाकर्ता ने अपने उत्पादन कार्यकलाप में कमी नहीं की है और न ही उसने व्यापार शुरू किया है । याचिकाकर्ता को अलग रखने के बारे में इन हितबद्ध पार्टियों ने कोई न्यायोचित तर्क नहीं दिया है ।

37. विधिक प्रावधानों और मामले के तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद प्राधिकारी नोट करते हैं कि रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मै. तेजस नेटवर्किंग लि. को वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के रूप में विचार करने से अलग रखने का औचित्य नहीं बनता है । विरोधी पार्टियों का यह तर्क इस तथ्य के मद्देनजर सही नहीं है कि किसी कंपनी को उसके द्वारा आयात किए जाने की स्थिति में सामान्यतः अलग रखा जाए कि संबद्ध देशों से तेजस द्वारा किए गए आयात एकल संघटकों के हैं जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे से अलग नहीं हैं और इस प्रकार इस संबंध में पूर्ववर्ती जांच परिणाम को बरकरार रखा जाता है ।

38. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी कानून के प्रयोजनार्थ "विनिर्माण" को आवश्यक मापदंड माने जाने की स्थिति में उत्पाद शुल्क के भुगतान के महत तथ्य से पाटन एवं क्षति के निर्धारण के बारे में कई गलत व्याख्याएं उत्पन्न होंगी क्योंकि : इसका तात्पर्य यह होगा कि रिटेगिंग, रिपैकिंग, रिलेबलिंग, माइक्रोनाइजेशन, मैटेलाइजेशन, पुलवराइजेशन आदि जैसे वृद्धिकारी कार्यकलाप भी उत्पादन बन जाएंगे । अर्थ निरूपण से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जिसमें एक उत्पाद का उत्पादन कई

बार किया जा सकता है । उदाहरणार्थ वर्तमान मामले में ई एम एस कंपनियों के रूप में ज्ञात ऐसी कंपनियां हैं जो विशिष्टीकृत इलैक्ट्रॉनिक संघटक सोल्विडरिंग कंपनियां हैं जो उनके द्वारा उत्पादित कार्ड की डिजाइनिंग या कार्यचालन के बारे में कोई भी जानकारी रखे बिना कई उद्योगों के लिए ऐसे कार्यकलाप कर रही हैं कि कंपनियां भी उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रही हैं । इस व्याख्या का अभिप्राय यह है कि इन कंपनियों को भी एस डी एच विनिर्माता माना जाना चाहिए । अतः तेजस नेटवर्क्स के लिए कार्ड का उत्पादन और आपूर्ति करने वाली ये ई एम एस कंपनियां एस डी एच उपकरण (सी के डी/एस के डी स्थिति में) की विनिर्माता बन जाएंगी । उत्पादन की गणना दो बार होगी । इसी प्रकार उत्पाद के आयातों की गणना विदेशी उत्पादक के उत्पादन और भारत में आयात के रूप में की जाएगी और तत्पश्चात् उसी उत्पाद की गणना केवल इस वजह से आयातक के उत्पादन और घरेलू बिक्री के रूप में की जाएगी क्योंकि आयातक ने सी के डी/एस के डी स्थिति में उत्पाद का आयात किया है, उत्पाद का संयोजन किया है और उत्पाद शुल्क के भुगतान के बाद उसकी बिक्री की है । विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र में कुछ स्थितियों में पुर्जे व संघटक शामिल होते हैं । इनमें से कुछ पुर्जे व संघटकों का उत्पादन भारत में कुछ अन्य विशिष्टीकृत संघटक विनिर्माताओं द्वारा किया गया हो सकता है । अतः ये संघटक विनिर्माता भी एस डी एच विनिर्माता बन जाएंगे । अतः ऐसी कंपनियों को पाटनरोधी कानून के अंतर्गत एस डी एच विनिर्माता नहीं माना जा सकता ।

39. इसके अलावा, उत्पाद की बिक्री करने वाली प्रत्येक कंपनी को घरेलू उत्पादक नहीं माना जा सकता । उत्पाद की बाजार में बिक्री करने वाली पार्टी के लिए उत्पादक बनने से पूर्व पूर्ण की जाने वाली/निष्पादित की जाने वाली न्यूनतम आधारभूत प्रक्रिया/मानदंड अपेक्षित होने चाहिए और ऐसे कार्यकलाप/मानदंड उत्पाद शुल्क का भुगतान नहीं हो सकते । ऐसे कार्यकलाप/मानदंड पर उत्पाद के स्वरूप तथा उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर विचार करना होगा । उदाहरणार्थ आयातित उत्पाद का व्यापार करने वाला कोई व्यक्ति उत्पाद से जुड़े कुछ कार्यकलाप भी करता है । तथापि, ऐसे व्यापारी को पाटनरोधी कानून के अंतर्गत उत्पादक नहीं माना जा सकता भले ही ऐसा व्यापारी उत्पाद शुल्क कानून के अंतर्गत कुछ कारणों से उत्पाद शुल्क का भुगतान कर रहा हो ।

40. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सी एम ए आई के अलावा, एक अन्य उद्योग एसोसिएशन टी ई एम ए ने 3 दिसंबर, 09 के अपने पत्र द्वारा याचिकाकर्ता की इस स्थिति कि घरेलू उद्योग कौन है, का समर्थन किया है और उसने प्राधिकारी के अंतर्गत निर्णय का समर्थन किया है । स्पष्ट तौर पर व्यापारियों/संयोजकों को घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता । मात्र यह तथ्य कि किसी अन्य तथाकथित विनिर्माता ने जांच में सहयोग नहीं किया है या भाग लेने वालों ने घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित प्रपत्र में अपने विनिर्माण कार्यकलापों के बारे में कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है एवं उपर्युक्त विस्तार से विचार-विमर्शित अन्य व्यौरे प्राधिकारी द्वारा लिए गए इस निर्णय का समर्थन करते हैं कि तेजस पाटनरोधी नियमावली के अर्थ क भीतर "घरेलू उद्योग" है ।

41. भारतीय उत्पादन के निर्धारण से संबंधित याचिकाकर्ता के दावों की प्राधिकारी ने विस्तार से जांच की थी । प्राधिकारी ने विशेष रूप से बीजक तथा डाटा मैगजीन के आधार पर याचिकाकर्ता के दावे की जांच की । यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित भारतीय उत्पादन नियमों के अर्थ के भीतर याचिकाकर्ता का आधार की पुष्टि करने के लिए उचित और पर्याप्त हैं । जांच से यह सिद्ध हुआ है कि याचिकाकर्ता का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा (भारतीय उत्पादन के 50 प्रतिशत से काफ़ अधिक) है । इस

संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता से केवल वही सूचना प्रदान करने की आशा की जाती है जो उसे उसके पास उपलब्ध हो । कोई भी हितबद्ध पार्टी यह दर्शाने में असमर्थ रही है । याचिकाकर्ता ने ऐसी सूचना उपलब्ध नहीं की जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सूचना थी जिससे अधिक उचित सूचना हासिल की जा सके ।

42. वर्तमान मामले में डाई स्टाफ मैनु एसो. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में सेस्टेट का तर्क लागू नहीं होता है । डाई स्टाफ मैनु एसो. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में मैगजीन एनीलिन की कीमत का नियमित समयांतराल पर प्रकाशन नहीं कर रही थी । इसके बजाए मैगजीन ने एनीलिन पर एक लेख निकाला और बाजार में एनीलिन की कीमत का उल्लेख किया । वर्तमान मामले में हितबद्ध पार्टी इस बात से सहमत है कि बीजक और डाटा मैगजीन संगत सूचना का नियमित उल्लेख करती है । इसके अलावा, बीजक और डाटा मैगजीन की विश्वसनीयता तब स्थापित होती है जब तेजस के प्रचालनों से संबंधित पत्रिका में निहित सूचना का मिलान तेजस के वास्तविक प्रचालनों से किया जाए ।

43. नियम 5 के अंतर्गत याचिकाकर्ता के आधार का निर्धारण करने के लिए निर्णय पूर्व सुनवाई या मतदान कराने की कोई विधिक अपेक्षा नहीं है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिका में आधार के बारे में पर्याप्त सूचना निहित है और वह पर्याप्त सकारात्मक साक्ष्य है । इसके अलावा, प्राधिकारी की जांच से यह सिद्ध होता है कि याचिका में निहित तथ्य इस संबंध में पर्याप्त और सही हैं ।

44. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि आवेदक को घरेलू उद्योग के घटक से अलग रखना अपेक्षित है क्योंकि वह विचाराधीन उत्पाद का आयात करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने ऐसे पुर्जों और संघटकों का आयात किया है जो विचाराधीन उत्पाद के दायरे में नहीं आते हैं । इसके अलावा, प्राधिकारी यह मानते हैं कि नियम 2 (ख) की परिभाषा में प्राधिकारी को विवेकाधिकार उपलब्ध है ।

गोपनीयता

45. गोपनीयता से संबंधित मुद्दों की प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के पैरा 75 में जांच की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने निर्णयोपरांत दूसरी मौखिक सुनवाई संबंधी अनुरोधों में कोई नया पर्याप्त तथ्य जानकारी में नहीं लाया है और इस प्रकार प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बरकरार रखते हैं ।

46. जहां तक अन्य हितबद्ध पार्टियों के अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतरण का संबंध है, इसे प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा था ।

सार्वजनिक हित

47. प्राधिकारी ने अंतिम जांच परिणाम के पैरा 76 और 77 में सार्वजनिक हित से संबंधित मुद्दों की जांच की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने निर्णयोपरांत दूसरी मौखिक सुनवाई संबंधी अनुरोधों में कोई नया पर्याप्त तथ्य जानकारी में नहीं लाया है और इस प्रकार प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बरकरार रखते हैं ।

पाटन मार्जिन का निर्धारण

48. प्राधिकारी ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार तथा पाटन मार्जिन के निर्धारण से संबंधित मुद्दों की जांच अंतिम जांच परिणाम के पैरा 78 से 118 में की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने निर्णयोपरांत दूसरी मौखिक सुनवाई संबंधी अनुरोधों में कोई नया पर्याप्त तथ्य जानकारी में नहीं लाया है और इस प्रकार प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बरकरार रखते हैं।

क्षति तथा कारणात्मक संबंध

49. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति और क्षति मार्जिन के निर्धारण से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई अंतिम जांच परिणाम के पैरा 121 से 167 में की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों ने निर्णयोपरांत दूसरी मौखिक सुनवाई संबंधी अनुरोधों में कोई नया पर्याप्त तथ्य जानकारी में नहीं लाया है और इस प्रकार प्राधिकारी अपने पूर्ववर्ती निर्णय को बरकरार रखते हैं।

50. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि पूर्ववर्ती प्रकटन विवरण में निर्णय के आधार स्वरूप सभी आवश्यक तथ्यों का प्रकटन नहीं किया गया, यह नोट किया जाता है कि प्राधिकारी ने ऐसे सभी आवश्यक तथ्यों का प्रकटन किया था जिन्हें हितबद्ध पक्षकारों को प्रकटित करना अपेक्षित था और जो प्राधिकारी के निर्णय के आधार थे।

51. जहां तक याचिकाकर्ता के परिसर के सत्यापन से जुड़े तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा गठित जांच दल ने बंगलौर और पांडिचेरी स्थित याचिकाकर्ता के परिसरों का दौरा किया था।

52. जहां तक ऐसे तीसरे पक्षकार ई एम एस वैंडरों के परिसरों के सत्यापन की जरूरत से जुड़े तर्कों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझी गई सीमा तक ऐसा सत्यापन किया गया है।

53. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से यह अनुरोध किया है कि वह भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस एल पी के निपटान तक अंतिम जांच परिणाम जारी न करें। प्राधिकारी का यह मत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मानते हुए कोई निर्णय नहीं दिया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को अंतिम जांच परिणाम जारी नहीं करने चाहिए। जांच परिणाम अधिसूचित करने से निर्दिष्ट प्राधिकारी को रोकने वाले किसी विशिष्ट निर्देश के अभाव में और सेस्टेट के आदेशों पर विचार करते हुए प्राधिकारी वर्तमान मामले में जांच परिणाम जारी करना उचित समझते हैं।

54. जहां तक घरेलू उद्योग की सत्यापन रिपोर्ट के अगोपनीय रूपांतरण के प्रकटन का संबंध है, प्राधिकारी ने विदेशी उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट का प्रकटन अन्य हितबद्ध पार्टियों को नहीं किया है (घरेलू उद्योग ने भी विदेशी उत्पादकों की सत्यापन रिपोर्ट की प्रति की मांग की थी) इसके अलावा, घरेलू उद्योग के परिसर में किए गए सत्यापन के बारे में सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने हेतु कोई अधिदेशित विधिक अपेक्षा नहीं है। अतः घरेलू उद्योग के परिसरों में मौके पर की गई जांच के बारे में सत्यापन रिपोर्ट हितबद्ध पार्टियों को उपलब्ध कराना अपेक्षित नहीं है।

6 फरवरी, 2012 के निर्णयोपरांत प्रकटन विवरण के बाद घरेलू उद्योग तथा विरोधी हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की प्राधिकारी द्वारा जांच

55. कई हितबद्ध पार्टियों ने प्राधिकारी द्वारा 6 फरवरी, 2012 को जारी प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां दी हैं जिनकी प्राधिकारी ने सावधानीपूर्वक जांच की है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये टिप्पणियां माननीय सेस्टेट के आदेशों के अनुसरण में प्राधिकारी द्वारा आयोजित निर्णयोपरांत मौखिक सुनवाई के बाद दायर लिखित/प्रत्युत्तर अनुरोधों अथवा कार्रवाई के दौरान पूर्व में इन हितबद्ध पार्टियों द्वारा किए गए अनुरोधों की अधिकांशतः पुनरावृत्ति है। घरेलू उद्योग के तर्क प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित विचाराधीन उत्पाद की यथातथ्यता और प्राधिकारी द्वारा किए गए आधार संबंधी निर्धारण के बारे में है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने ई सी आई को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान करने पर आपत्ति करते हुए और आरोपित असूचित निर्यात सौदों के मददेनजर कुछ प्रतिवादी निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत स्वीकार करने के बारे में अपने अनुरोधों को दोहराया है। विरोधी हितबद्ध पार्टियों ने विचाराधीन उत्पाद के गलत क्षेत्र (खासकर एस डी एच-64, एस डी एच-256, डिजिटल कास कनेक्ट, अन्य उत्पाद के भाग के रूप में आयातित विचाराधीन उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने आदि के बारे में) का तर्क देते हुए अपने पूर्ववर्ती अनुरोधों को दोहराया है। हितबद्ध पार्टियों ने वर्तमान याचिका दायर करने के लिए तेजस के आधार के बारे में प्रस्तावित निर्धारण का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि तेजस घरेलू उद्योग नहीं हो सकता। साथ ही साथ इन हितबद्ध पार्टियों ने यह तर्क दिया है कि अन्य घरेलू कंपनियों (अर्थात् पृथ्वी, दी एम सी एल आदि) को घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए।

56. हितबद्ध पार्टियों द्वारा मौखिक सुनवाई के समय किए गए विभिन्न अनुरोधों और उसके बाद लिखित तथा प्रत्युत्तर अनुरोधों, प्राधिकारी द्वारा जारी प्रकटन विवरण पर किए गए अनुरोधों एवं विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण पर दी गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और पुनश्च पाटनरोधी अधिनियम एवं नियम, जांच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दायर सूचना तथा विधिक तथा वास्तविक स्थिति के मददेनजर हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्कों के गुणदोष पर विचार करते हुए प्राधिकारी यह मानते हैं कि विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा दी गई टिप्पणियों पर प्रकटन विवरण में पूर्व में सूचित वास्तविक एवं विधिक स्थितियों पर पुनर्विचार अपेक्षित नहीं है।

भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

57. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से भारत में विचाराधीन उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपायों के कारण कम नहीं होगी। इसके विपरीत पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से पाटन व्यवहारों से प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग का हास रुकेगा और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर असर नहीं पड़ेगा।

58. प्राधिकारी यह मानते हैं कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य सामान्यतः पाटन दान अनुचित व्यापार पद्धतियों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को बहाल किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है।

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

59. प्राधिकारी नोट करते हैं कि माननीय रीगा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट), प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 11.8.2011 के आदेश के तहत प्राधिकारी को ऐसी निर्णयोपरांत सुनवाई के परिणामस्वरूप अंतिम जाँच परिणाम में यथावश्यक ऐसे संशोधन करने का निर्देश दिया था।

60. प्राधिकारी द्वारा पूर्व में अधिसूचित अंतिम जाँच परिणाम, दूरारी मौखिक सुनवाई के समय हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों और उसके बाद लिखित एवं उत्तर संबंधी अनुरोधों तथा विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रकटन विवरणों पर टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए और पाटनरोधी अधिनियम तथा नियमों, जाँच के दौरान विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना को भी ध्यान में रखते हुए और विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के मद्देनजर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के गुणदोष पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि प्राधिकारी द्वारा पूर्व में अधिसूचित अंतिम जाँच परिणाम में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है। याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने और उसकी पैरवी करने का आधार है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा लिए गए अनुरोधों में पूर्व में निर्धारित पाटनमार्जिन में कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी के बारे में प्राधिकारी द्वारा पूर्व में अधिसूचित जाँच परिणाम में भी कोई संशोधन अपेक्षित नहीं है। प्राधिकारी यह मानते हैं कि संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद का निर्यात सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुआ है जिससे उत्पाद का पाटन हुआ है जिसकी वजह से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकारी मानते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना अपेक्षित है। प्राधिकारी मानते हैं कि प्राधिकारी द्वारा की गई निर्णयोपरांत सुनवाई तथा उक्त सुनवाई के बाद विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के परिणामस्वरूप 19 अक्टूबर, 2010 के अंतिम जाँच परिणाम संबंधी अधिसूचना संख्या 14/2/2009-डीजीएडी के किराी भाग में संशोधन अपेक्षित नहीं है। प्राधिकारी एतद्वारा द्वारा 19 अक्टूबर, 2010 की अधिसूचना संख्या 14/2/2009-डीजीएडी के तहत पूर्व में अधिसूचित अंतिम जाँच परिणाम की पुष्टि करते हुए अपने निर्णयोपरांत अंतिम जाँच परिणाम जारी करते हैं।

61. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th February, 2012

(FINAL FINDINGS)

Subject : Anti-Dumping Duty investigation in respect of import of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment (SDH Equipment), originating in or exported from the People's Republic of China and Israel.

No. 14/2/2009-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules thereof, as amended from time to time (hereinafter referred as the AD Rules);

BACKGROUND

1. Whereas the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the Rules or the AD Rules), received an application filed by M/s Tejas Networks Limited (hereinafter referred to as the applicant) on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment (hereinafter referred to as the SDH equipment or the subject goods), originating in or exported from the People's Republic of China PR and Israel (hereinafter referred to as the subject countries) and requesting the Authority for initiation of anti dumping investigations for levy of anti dumping duties on the subject goods.
2. And whereas the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, and after examination of the same with regard to the adequacy and accuracy, issued a Public Notice dated 21st April 2009, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the anti-dumping duty investigations concerning imports of the subject goods originating in or exported from the subject countries in accordance with the Rule 6 (1) of the Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
3. And whereas the Designated Authority having regard to the Act and the Rules, investigated and then recommended imposition of provisional Anti Dumping Duty on imports of the

3. And whereas the Designated Authority having regard to the Act and the Rules, investigated and then recommended imposition of provisional Anti Dumping Duty on imports of the subject goods originating in or exported from China PR and Israel vide Notification dated 7th September 2009, and provisional anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 132/2009-Customs dated 8th December, 2009.
4. And whereas the Designated Authority issued Final Findings on 19th October, 2010 recommending imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods from subject countries and definite Anti-dumping duties were imposed by the Ministry of Finance vide Notification No.125/2010-Customs dated 16th December, 2010.
5. And whereas some interested parties filed appeals before the Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Principal Bench, New Delhi challenging the Final Findings dated 19th October 2010 and the Customs Notification issued by the Ministry of Finance.
6. And whereas the Hon'ble CESTAT after extensively hearing the interested parties as well as the domestic industry issued an order dated 11th August, 2011 wherein the Tribunal allowed the appeals of three appellant interested parties, namely, M/s Huawei Technologies Co Ltd, China; M/s Vuppalamritha Magnetic Components, Hyderabad, India and M/s Prithvi Information Solutions Ltd, Secundrabad, India, by remanding the matter back to Designated Authority for affording post-decisional hearing to the appellants and other interested parties, if any, and for making such modifications to the Final Findings as might be necessary as a result of such post decisional hearing. The order of the Hon'ble Tribunal stated as follows:

"Accordingly we allow these appeals by remand to the DA for affording post-decisional hearing to the appellants and for making such modifications to the Final Findings as may be necessary as a result of such post decisional hearing. The respondent-domestic industry and other interested parties, if any, shall also be allowed to participate in such post decisional hearing. Any modifications made in the final findings would be considered by giving effect to the same by the government by carrying out the necessary amendment to the impugned notification imposing anti-dumping Duty. This process shall be completed within 6 months from the date of this order and status quo shall be maintained meanwhile. Since we are allowing the main appeals by remand, the MA (EH) and SPs stand disposed off."

PROCEDURE

7. The procedure described below has been followed
 - i. Pursuant to the order of the Hon'ble CESTAT, the Authority provided an opportunity to the interested parties to present their views orally in a Oral Hearing held on 23rd January, 2012. The interested parties who presented their views orally at the time of Oral Hearing were requested to file written submissions of the views expressed by them orally and were allowed to file rejoinders to the submissions made by opposing parties. The following interested parties have filed submissions subsequent to the oral hearing:
 - a) Tejas Networks Ltd, India
 - b) Coral Telecom, India
 - c) Huawei Technologies Co. Ltd., China PR
 - d) ECI Telecom Limited, Israel

- e) Hangzhou ECI Telecommunications Co. Ltd., China PR
 - f) ECI Telecom India Pvt. Limited, India
 - g) Ceragon Networks Limited, Israel
 - h) RAD Data Communications Ltd, Israel
 - i) Vuppalamritha Magnetic Components Ltd., India
 - j) Prithvi Information's Solutions Ltd., India
 - k) UT Starcom, China
 - l) Ciena Corporation, USA
 - m) ZTE Corporation, China
 - n) Aircel India Limited, and
 - o) Vodafone India Limited.
- ii. Submissions made by various interested parties pursuant to the post decisional oral hearing held by the Authority were examined in detail in the light of the facts and the legal provisions and the same have been considered in the present Final Findings by the Authority to the extent considered relevant in the context of the present investigation.
- iii. In view of a large number of participating interested parties and a number of issues raised by these interested parties, the Authority has summarized the submissions made by these interested parties collectively in the present Final Findings.
- iv. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts under consideration before the Authority in the instant investigation were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 6.2.2012. The comments received on the said Disclosure Statement, to the extent considered relevant, have been considered by the Authority in its Final Findings.
- v. *** in the Final Findings represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority on merits under the Rules.
- vi. Some of the abbreviations used in this Final Findings represent as follows:

SN	Abbreviation	Explanation/meaning
1.	Authority	Designated Authority
2.	DA	Designated Authority
3.	Act	Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995
4.	Rules	Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995
5.	PUC	Product under consideration, i.e., SDH Transmission Equipment as defined in the relevant para in this Disclosure Statement
6.	SDH	Synchronous Digital Hierarchy Transmission Equipment

7.	CKD	Completely knocked down condition
8.	SKD	Semi knocked down condition
9.	DI	Domestic industry
10.	ADA	WTO Agreement on Anti Dumping
11.	Tejas	Tejas Networks Ltd.
12.	VMCL	Vuppalamritha Magnetic Components Ltd
13.	Prithvi	Prithvi Information Solutions Ltd.
14.	BSNL	Bharat Sanchar Nigam Limited
15.	MET	Market Economy Treatment
16.	POI	Period of Investigation

Submissions by the petitioner domestic industry in written submissions and rejoinders after the post decisional second oral hearing held on 23rd January, 2012

8. The following submissions were made by the domestic industry:

- i. The domestic industry requested that all the facts, contentions, averments and statements presented in the earlier submissions be deemed to be incorporated whether or not repeated in their submissions filed subsequent to post decisional second oral hearing.
- ii. The petitioner requested the Authority to consider and define the meaning of origin in view of very peculiar facts and circumstances of the present case. Meaning of production/manufacture changes from product to product and has to take into account the production activities carried out in manufacturing such product. Further, the meaning of "originating in" has to be linked to the place where the product has indeed been produced. Such place cannot be restricted to the place where the product has been assembled using screw driver technology.
- iii. "Indian product" is different from "product manufactured in India". The petitioner refers to and relies on the Recommendations on Telecom Equipment Manufacturing Policy by Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) dated 12th April, 2011. It is most vital to ensure that (a) the domestic industry does not face continued dumping even after imposition of anti dumping duties, (b) producers outside China and Israel are not made to pay anti dumping duties merely because of some small operations carried out in China, and (c) Chinese and Israeli producers should not be allowed to continue dumping by importing the product in any of its form and doing the remaining part in India.
- iv. Tejas' factory at Pondicherry was visited on behalf of the Designated Authority after the preliminary findings. The visit prior to the preliminary findings was to Bangalore, where the company maintains all relevant financial information. Since the purpose of the visit prior to preliminary findings was to verify the financial information, the visit

was restricted to Bangalore. Further, the company has a research & development wing at Bangalore. Research and development is at the core of production in this industry.

- v. Verification was conducted at Pondicherry after the preliminary findings. The domestic industry never stated at the time of the first hearing that Pondicherry factory did not exist during the investigation period and that the factory had started production only recently. On the contrary, the Pondicherry factory was operational during the investigation period.
- vi. The petitioner submitted that the Authority, while considering whether M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co. Ltd is entitled to market economy treatment or not, only looked into the ownership criterion and ignored the other six criteria and most importantly that market economy status cannot be granted unless the responding Chinese exporters pass the test in respect of each and every parameter laid down under the Rules. Further, petitioner submits that no sufficient reasoning has been provided by the Authority to establish that M/s Hangzhou ECI Telecommunication Co fulfils all the above mentioned parameters of the market economy treatment.
- vii. There are strong reasons to believe that certain responding exporters (in particular ECI and ZTE) have deliberately suppressed information from the Authority and not reported all their export transactions with regard to the domestic sales and exports to India during the POI. This suppression of critical information seems to have been done deliberately to reduce their Injury and Dumping Margins. It is thus evident that ECI has not established how it is entitled for market economy treatment.
- viii. ECI has not only given wrong information but also they have already started duty circumvention by adopting wrong practices. ECI has re-routed their exports from China to India via Israel to claim misleading "Country of Origin" as "Israel", even when goods are of Chinese origin
- ix. At the outset, it may be noted that Huawei did not press any arguments on the merits of the dispute before the CESTAT, and confined their arguments on the issue of hearing. A written note was also given on this point, which is available in their petition filed before the Hon'ble Supreme Court.
- x. The petitioner requests the Authority to kindly note the fact of non submission of written submissions by the parties who attended the hearing and those who did not attend the hearing and did not file any submissions.
- xi. Huawei has not raised any new grounds beyond those which were argued in the previous hearing before the Authority and which were adequately considered by the Authority in the previous findings.
- xii. Huawei's counsel argued for more than two hours at the time of oral hearing and they have now filed very brief (two page) written submissions. Domestic industry requests the Authority to consider and record this fact. In fact, under the Rules, the Designated Authority is not required to consider any argument raised by an interested party orally if such oral argument is not subsequently reproduced in writing.
- xiii. As regards the accuracy and adequacy of the evidence, the petitioner submitted that petitioner in its petition clearly provided information with regard to Indian production. Petitioner provided information with regard to its own production and Indian production, which clearly established that the share of petitioner in Indian production was about 85%.
- xiv. As regards credibility of CMAI letter, it was stated that CMAI made four statements in its letter. Till date, it has not been established that any of these statements is factually incorrect. This itself establishes credibility of the letter issued by CMAI. As

regards the qualification in the CMAI letter, it has been mentioned only to convey that these figures should not be considered as 100% accurate figures. It is relevant to point out in this regard that the certificate that the Authority requires from petitioner, foreign producers and importers in their respective questionnaires also contains a qualification.

- xv. As regards pre-decisional hearing and polling of domestic producers, it was submitted that there was no legally mandated requirement for holding pre-initiation polling or hearing. In any case, since the petition showed that the share of petitioner was in the region of 86%, significantly above the minimum mandated share of 25%, polling was wholly unnecessary.
- xvi. As regards confidentiality, it is submitted that the exporter itself has not disclosed information with regard to different types of product sold by the exporter in Indian market. No details of imports of sub-assemblies or assemblies made by these parties have been disclosed in their non confidential public versions. Even when a copy of Voice and Data magazine has been demanded as the exporter's counsel claimed to have in possession five years copies of Voice and Data with them, and copy of which was never made available to the domestic industry through public file. It is not clear whether at all these five years copies of voice & data have been filed by them before the Authority.
- xvii. As regards accuracy of Voice and Data magazine, it is submitted that rule is limited to satisfaction of the Designated Authority with regard to accuracy of information. This cannot be read as an obligation on the Authority to verify each and every information filed before the Authority.
- xviii. Disclosure Statement is only a disclosure of essential facts. Disclosure Statement is not a disclosure of determinations. Normal value and export price constitute determinations- an outcome of the essential facts. Normal value and export price are in fact required to be determined after the interested parties have offered their comments on the facts gathered during the course of the proceedings.
- xix. The domestic industry has not imported complete SDH equipments from any country.
- xx. Tejas does not import populated PCB from outside India. Tejas merely gets PCBs populated from its EMS as per its design and drawing.
- xxi. As regards unusually short notice for hearing, the petitioner submitted that this was a second date for the present hearing. The Designated Authority had earlier notified all interested parties for the hearing which was scheduled on 23rd Dec., 2011. The hearing however did not take place that day because of some objection raised by some interested party. The interested parties are well aware that the CESTAT has granted six months time to the Designated Authority to conduct these post decisional hearings and issue necessary findings. Given these circumstances, it cannot be said that unusually short notice was given for the present hearing.
- xxii. Designated Authority has clearly found that the domestic industry has imported only (a) dual use parts and components, (b) PCBs populated by its EMS on the basis of design & drawings given by Tejas (i.e., job work got done by Tejas from outside India).
- xxiii. Petitioner has not imported the product under consideration. Instead, the petitioner has imported dual use parts and components, which are now beyond the scope of the product under consideration and imports of which is similar to imports of raw materials by a manufacturing company. Petitioner has not imported PUC from the subject countries.

448 G2/12 - 1

- xxiv. Notwithstanding, petitioner submits that the Rule 2(b) provides a discretion to the Authority to treat a domestic producer as ineligible in certain situations.
- xxv. As regards the request to the Authority by some interested party not to issue Final Findings till disposal of the SLP before the Hon'ble Supreme Court of India, the petitioner submitted that the Hon'ble Supreme Court has issued no such orders or direction to the Designated Authority. Infact after extensively hearing the parties present at the time of last hearing, the Hon'ble Supreme Court did not pass any order preventing the Designated Authority from proceeding in compliance of the CESTAT order. Therefore, the petitioner requests the Authority to proceed with the issuance of findings as per the directions of the CESTAT. The CESTAT has granted six months to the Designated Authority and the anti dumping duties have been protected for the same period. It is vital that the findings are issued within time limits so that the domestic industry does not face a "no duty period". In fact, not only no stay has been granted by the Supreme Court, the Court by its earlier order dated 20.09.2011 has specifically directed the Authority to proceed with the remand proceedings.
- xxvi. As regards the Designated Authority having absolute discretion to exclude the product, the petitioner submitted that the Designated Authority can exclude a product from the scope of the product under consideration only if the domestic industry does not have like article. If the domestic industry has like article, the Designated Authority cannot exclude such product type. The Designated Authority does not have absolute discretion in this regard. The exclusion is governed by the facts of the case and whether the domestic industry is having like article.
- xxvii. As regards the exclusion of PTN from the PUC, the petitioner submitted that ZTE provided no information/material whatsoever to establish that PTN is not a type of product under consideration. A party seeking exclusion of a particular product type must establish justification for such exclusion. The onus to establish need for exclusion is onto the exporters. If the exporters contend that particular product is beyond the scope of the product under consideration, then such exporter must establish the same. The domestic industry has provided sufficient evidence to establish that PTN is indeed a type of product under consideration.
- xxviii. Significant activities other than software development are done by Tejas. Submissions made earlier are relied upon. Software development is a part of the total production activity. It is also undisputed position that software is a critical activity.
- xxix. By virtue of Note 6 to Section XVI, assembly amounts to manufacture for the purpose of levy of excise duty – creates a deemed fiction, which can not be extended to other laws – definition in excise law may not have applicability in present case. Definition of manufacture / production is to be considered in the context of the law and purpose for which such word is used. Detailed written submissions are referred to and relied upon.
- xxx. Burden of proof on Tejas to prove that it constitutes the Domestic Industry has been adequately discharged. No material has been given by opposing interested parties to rebut the claim. The finding of the Designated Authority on such pertinent questions of facts is correct. The Supreme Court has directed DA to decide the case without regard to observations of Andhra Pradesh High Court. Therefore, no reliance can be placed on the said decision.
- xxxi. As regards request of the opposing interested parties for exclusion of parts and components, it is submitted that Petitioner continued to argue inclusion of part and components within the scope of product under consideration. Petitioner has not sought exclusion of parts and components from the scope of product under consideration. Now that the Designated Authority has accepted their contentions and rejected

petitioner's contentions, it is highly improper for the opposing interested parties to now dispute such exclusion by the Authority. In any case, attaching motives behind such exclusion is highly improper.

- xxxii. Imports of raw material from the subject countries do not bar a manufacturer from being considered as eligible domestic industry. There are number of investigations conducted by the Authority, wherein the petitioner is importing the raw material from amongst the subject countries.

Submissions by opposing interested parties in written submissions and rejoinder submissions after the second oral hearing

9. The following submissions were made by the opposing interested parties:
- i. The Authority and the Ministry of Finance simply accepted what was presented by the applicants (Tejas) in the application without conducting an examination w.r.t. exclusion of certain Indian entities (Prithvi and VMLC) from the definition of 'domestic producers'.
 - ii. CMAI has produced a letter indicating that Tejas's production accounts for more than 50% of the production, though they did not maintain accurate information about the production. This letter was considered as an evidence in accepting the application without looking into the adequacy and accuracy of the information.
 - iii. The application stated that the production of other Indian producers was based on the data published in Voice & Data magazine, which had information on the PUC as well as other products and, therefore, the same has been adjusted in order to determine information about the PUC. The Authority has not examined the details about the adjustments.
 - iv. The Authority has not examined the accuracy of the information furnished in the application by cross checking it with other official import statistics such as DGCI&S
 - v. No reasoning was given by the Designated Authority in its findings as to why the binding decisions of Dye Stuff Manufacturers Association of India vs Government of India were not applicable to the DA.
 - vi. No pre-decisional hearing took place to evaluate the claim of the applicants that they represent the domestic industry.
 - vii. Even a polling exercise among the domestic producers has not been conducted. This would have helped to evaluate whether there is any opposition to the application or not.
 - viii. Designated Authority has conducted the investigation in an arbitrary manner without complying with the mandatory procedural requirements contained in Rules 6,7,8,9 and 16.
 - ix. The Designated Authority has released limited information and evidence to the appellant and other interested parties. There are other procedural violations committed, such as, information not called for under Rule 6(4) were insisted upon, excessive confidentiality was granted, accuracy of volume and value of imports was never verified, verification visit was made in an arbitrary manner, disclosure statement by respondent no I was not made available.
 - x. Excessive confidentiality with regard to source of the import data, basis of majority market share, different types of product produced by domestic industry, basis of normal value or the export price, evidence of various deductions claimed from export

- price, no indexed costing information. Purchase policy, sales policy, store accounting, inventory/ WIP/stock valuation, quality control policy
- xi. Non confidential versions furnished by the interested parties other than the applicant were not made available public.
- xii. Disclosure Statement did not disclose all essential facts that formed the basis of the decision. For example, Normal Value and Export Price determined for residual category of exporters; comments offered by appellant; Tejas has imported complete SDH; segregation of profit in domestic and export market.
- xiii. In the original Disclosure Statement, the margin of dumping was 240-250% and in the revised second Disclosure Statement, it was 280-290%. Such an upward enhancement with respect to margin of dumping was perverse as any alteration of the NIP could not alter the margin of dumping.
- xiv. The applicant domestic industry was a design house engaged in design and development activities in India but the actual production activities were carried outside India.
- xv. Designated Authority visited applicant's head office at Bangalore and extended the invitation to visit the new plant at Pondicherry that had been established subsequent to the visit.
- xvi. It has been admitted in the Final Findings that Tejas had imported PCBs from Thailand and Singapore. Once PCBs enter India, no substantial transformation is required to make the finished product.
- xvii. The Indian related party has submitted a list of 11 domestic producers in India with their complete contact details and the products for which they have been approved by BSNL. Few of them out of this list import bare PCBs into India and populate those PCBs in India. Designated Authority has not examined the status of these companies.
- xviii. Those who undertake assembly operations and final testing in India are not to be treated as domestic producers. Thus, when the applicant (Tejas) is not involved in manufacture, the applicant shall not be treated as a domestic industry.
- xix. The Designated Authority has not examined the activities carried by Tejas from the list of activities carried by them.
- xx. Assemblies and sub assemblies, capacitors, connectors, inductors, resistors, stickers, trans-receivers, transformers and patch cords were procured from such third sources, while Tejas were engaged in the incremental activity of procuring these items and carrying out assembly and testing operations. Designated Authority concluded that substantial operations were carried out by Tejas.
- xxi. Designated Authority held in impugned findings that imports from other countries do not constitute alleged dumped articles, such determination is not properly based as the question is not merely importation but importation by a person who does not manufacture the product in India. And the question is whether the imports were really from countries other than the subject countries in this case.
- xxii. Designated Authority did not carry out any verification at the premises of such third party EMS vendors to examine their capacity and other production facilities.
- xxiii. Designated Authority failed to provide a precise definition as the definition covers four distinct items, i.e., parts, equipment, assemblies/sub assemblies and other equipments
- xxiv. STM 64 and STM 256 should not have been included because STM-64 was never produced in commercial quantities and had never entered the Indian domestic market.

- STM-256 was not imported into India and all the parties have agreed that technical approvals for deployment of STM-256 are not in place in India. Further, STM-256 belongs to a different class of product compared to other STM 1- 64.
- xxv. DXC shall be excluded because :
- a. DXC is used for traffic grooming and switching functions.
 - b. Globally, DXC is treated as a separate product category.
 - c. DXC can never substitute a STM –XX machine
- xxvi. Designated Authority has included Populated PCBs in the PUC and the records of the case indicate that domestic industry did not produce populated PCBs within India.
- xxvii. Designated Authority has not examined the nature of the broadband or cellular equipment and whether it is possible to segregate the value of SDH equipment alone from the value of SDH equipment.
- xxviii. Designated Authority has included software meant for SDH that may be brought either as a part of the equipment or separately. It's a service and, thus, should be excluded.
- xxix. Few equipments have been excluded on the basis of 'being non-SDH in any of its form'. The custom authorities are demanding duty on those equipments any of whom are having some SDH compliant parts/interfaces as only those machines that are non SDH in any of its form alone have been excluded. Therefore, in place of 'being non-SDH in any of its form', even if they contain any SDH compliant parts or interfaces be substituted.
- xxx. The PUC was not homogenous product but available in number of variants and grades. The PCBs and height end SDH could not be subject to anti dumping duty in light of various Tribunal orders. The product definition is in violation of the binding orders of the CESTAT.
- xxxi. The appellant had disclosed all information in its books with respect to the shareholding structure of the company. The Designated Authority insisted of the complete accounts of Employees Union, who were the trustee of the shares held by the employees of the company and the Union was not willing to share the information.
- xxxii. Designated Authority acknowledged the Employees Union as a separate legal entity, yet diverse findings were given.
- xxxiii. Non disclosure of information by a separate legal entity could not have been used as a pretext to prejudice the interest of the appellant.
- xxxiv. When Designated Authority verified individual documents with various sub fields of the PCNs, no mistakes were found. It was wrong on the part of the Designated Authority to conclude that appellant had made repeated modifications to the data.
- xxxv. As per verification report, the PCN details had been verified in respect of every sub field. The appellant had followed the 15 digit system with the same feature without any modifications. The appellants had given a complete list of description that they had used for denoting every sub field of the PCN as suited to their needs. There was no difference in the description between PCNs reported and the underlying documents. The appellant has provided all the possible information available with them, still the export price was rejected on the ground that the information was not ideal for the Designated Authority.
- xxxvi. Non determination of a separate dumping margin for the appellant or according an explanation with respect to the methodology adopted for determination of margin of

dumping is a direct violation of the statutory requirements imposed by rule 17(2) and rule 17(3).

- xxxvii. The injury determination has failed to meet the objective examination standard with respect to (a) the volume of dumped imports based on voice and data magazine, (b) effect of dumped imports on the prices in the domestic market for the like article, (c) consequent impact of these imports
- xxxviii. DA failed to analyze that in electronics products, the price does not increase with increase in capacity and when a new article is introduced in market, the price will be higher. Tejas is new company whereas appellant is established since decade.
- xxxix. Capacity and capacity utilisation has also not been examined properly as the EMS vendors were located in India or outside India has not been examined.
- xl. Designated Authority mentioned in the preliminary findings that domestic industry's losses increased in domestic operation, their overall profit position remained positive due to exports financed the losses, whereas the appellant had brought into light the fact that the profits have increased but the exports had gone down.
- xli. Designated Authority failed to make objective assessment of the factors concerned. In the course of analysis, 'volume and prices of imports not sold at dumping prices had to be examined' whereas the Designated Authority made a cursory observation in this regard as it had not evaluated the volume of imports from other countries.
- xlii. Though the average price from the subject countries did not show any price undercutting at all, Respondent No. 1 has determined that there was significant price undercutting when compared on a PCN to PCN basis.
- xliii. Designated Authority had not examined the competition between domestic producers at all.
- xliv. Designated Authority had failed to examine the information relating to competition presented by Tejas in the application.
- xlvi. Export performance and productivity also has not been analysed.
- xlvi. Refusal to accept a price undercutting without according proper reasoning for the same is unwarranted.
- xlvi. DGAD is requested to undertake another verification visit to Huawei, China since earlier visit was biased.
- xlviii. Objections are raised vide letter dated January 18, 2011 regarding conduct of the hearing and its manner of calling (unusually short notice was given).
- xlix. DGAD is requested to make available a properly indexed public file containing all the documents.
- I. DGAD is requested not to issue Final Findings till disposal of SLP pending in the Hon'ble Supreme Court. Alternatively, DGAD may terminate investigation without imposing any measures.
- ii. As regards issue of defining "originating in", following are relevant:
 - a. Telecom Equipment Manufacturing Policy (12 April 2011) relied upon is merely a draft policy.
 - b. Resorting to the Telecom Policy is not warranted in an AD investigation for ascertaining origin.
 - c. Intellectual property, as mentioned in the Policy, does not encompass manufacturing activity.

- d. It is beyond the scope of the powers of the DA to design rules of origin. This is done by the Ministry of Finance through Customs Notifications.
- e. These Customs Notifications provide that 'value addition norms', 'change in customs classification' and 'transformation in the nature of the product' help determine the origin of a product. The Applicant is requesting that these factors be disregarded to protect its dubious claim that it constitutes DI and is not an importer.
- f. Unlike Telecom Policy, the purpose of AD law is not to protect intellectual property, but domestic manufacturers of the product.
- lii. In view of judgments by Madras and Calcutta High Courts, applicant is required to be excluded from the constituents of DI as they import PUC.
- liii. Pondicherry factory did not come into operation for a long time after POI. Dates of verification of Pondicherry factory by DA not disclosed.
- liv. Requested the DGAD for non-confidential versions of verification reports of first visit to head office at Bangalore and alleged second visit at Pondicherry.
- lv. Petition deals with imports into India: (i) Chart given without date/period, source, (ii) Pgs 49-50 said to be reproduction of Voice and Data Magazine, but are illegible and no import volume, no basis given, (iii) Pg 51 shows a forecast without quantity, (iv) Pg 52 shows figures for import, without value, basis or source.
- lvi. Number of products were excluded before initiation of investigation (by DA and Hon'ble Supreme Court), but import statistics were not altered.
- lvii. As regards coral submissions, they have submitted that those who do not file questionnaire response cannot be termed domestic producers/interested parties/domestic industry in the absence of information.
- lviii. As regards mis-declaration of export prices, it is submitted that export price provided in initial questionnaire remains unchanged and information was clearly verified by the Investigating Team (led by 3 officers). ECI satisfied the DA that the sample export transactions were correctly reported on 13 Oct 2010. The DA in para 169 of the Final Findings stated, "...ECI also provided evidence that the volumes reported in the import data were not correct."
- lix. As regards the MET, it is submitted that HETC has established that it is a wholly owned subsidiary of ECI Israel and its management is completely free from State interference. ECI was, during that period, a listed company at Nasdaq, bound by listing regulations. Investigating Team examined all the relevant facts for grant of MET Status during the on-site verification. DA has in many other AD cases accorded MET to privately owned Chinese companies.
- lx. Exporters accepted PCN (Product Control Number) system suggested by DI, and varied their reports accordingly. However, DA correctly recorded in its Final Findings that the description and price of the goods exported remained unchanged.
- lxi. PCN methodology not followed in calculating the Normal Value; DA erred in calculating the Dumping Margin.
- lxii. The Authority has taken assembly/sub-assembly wise selling price in the domestic market / third countries contrary to the method followed in arriving at the export price as per the PCN methodology.
- lxiii. With regard to the determination of the normal value for the remaining PCNs, the methodology adopted in calculating the normal value is inconsistent with the determination of the export price.

- lxiv. It appears that the Designated Authority has taken the gross selling price without making adjustments for domestic freight, taxes etc. for PCNs which were sold in the Domestic Market.
- lxv. Authority has penalized the cooperating exporters by not considering a reasonable profit of 5% which has otherwise been considered for the cooperating exporters who have been denied market economy treatment.
- lxvi. Element / Embedded Software Price not considered in the Export Price. Software being one of the crucial inputs in SDH equipment should be given full effect while calculating export price.
- lxvii. The Domestic industry failed to provide data on PCN basis for injury parameters.
- lxviii. The calculation of dumping margin pertaining to the data of the Interested Parties is to be disclosed. It cannot be kept confidential as it pertains to their own data.
- lxix. No injury to the domestic industry.
- lxx. The duties were imposed on products not manufactured by the DI in India. DA concluded 522 PCNs were exported to India and only 139 PCNs of products were matched with the DI. The importers / end-users data shows that several of the products imported by them are not manufactured / cannot be supplied by DI.
- lxxi. Respondent No.2 states that a comparable lower model applied by DI has been used as a basis for comparison and goes on to observe that the landed prices for the exporters are significantly lower than the selling price of the same equipment supplied by DI.
- lxxii. Ceragon exports some Microwave Radio Terminals which could have an STM-1 interface to the SDH transmission equipment. This interface acts as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment. It has been emphasized that this is merely an interface, and does not perform any of the SDH transmission equipment requirements. Thus, it is sought to amend scope of the PUC to exclude Ceragon's products, including those with STM-1 interface. DA has absolute discretion to exclude products from purview of the investigation.
- lxxiii. RAD products/modules having STM-1 interface be excluded from PUC as they don't work in SDH environment, because they are used to carry data and voice traffic over dark fiber, in private campus networks or private networks of Defense, Railways, and Utilities. Many of these products are stated not to transmit data/voice traffic in SDH environment, because they are used only as 'monitoring/probe' devices for 'Operations and Maintenance' of Transmission Networks. Therefore, these products/modules do not have the same end use of SDH Transmissions and cannot be considered as "like products" to those manufactured by Tejas. Similar STM-4 interfaces be excluded too.
- lxxiv. It is wrong on part of the Designated Authority to expect the interested parties opposing such investigation to prove otherwise. It is only when the applicant discharges the initial burden in terms of Rule 5(1) of the Anti Dumping Rules, onus would then shift to the responding parties to prove their case.
- lxxv. The DA conveniently excluded parts and components from the scope of product in the Final Findings so that Tejas was kept out of being termed as an importer. The Petitioner is an importer of 95% of parts and components used by it.
- lxxvi. DA provided no data/figures as to the percentage of imports from China PR. DA summarized activities conducted by the Petitioner in India and has added that Tejas is importing components, i.e., development board, developing software and outsourcing soldering activity.

- lxxvii. If pre-manufacture costs are excluded, the imports by Tejas would constitute a very high proportion in its total costs. Thus, it is clear that Tejas itself is a major importer.
- lxxviii. Tejas is importing majority of raw material from China and routing the same through Thailand. This is a device to remain within the ambit of the term 'domestic industry'.
- lxxix. The legislature did not give such discretionary powers to DA whereby the DA can hold a party to be DI if such party cannot even satisfy the basic criteria of being a manufacturer. Further, reference to "certain situations" needs to be corroborated with evidence and cannot be taken as an arbitrary right given to DA.
- lxxx. DA in the Final Findings has excluded parts and components on the ground that they have multiple-usage and do not have a dedicated usage in SDH Equipment alone. On that basis, even the other SDH Equipments such as Digital Cross Connects, populated PCBs, SDH Equipment as part of broadband or cellular equipment, software, etc. are liable to be excluded as they all have multiple usage and do not have a dedicated usage for SDH Equipment only.
- lxxxi. Almost 95% of Tejas' imports are of parts and components. Thus, exclusion of parts and components from the subject goods seems to be highly convenient.
- lxxxii. Treatment of China as a non market economy country by the Designated Authority is rather arbitrary in nature. To treat any economy as non market economy, specific findings have to be given in each case. Past treatment cannot be the sole reason for treating any economy as non market economy. Further, non market economy status cannot be fastened to any country as a general rule. Findings on non-market economy status is incorrect.
- lxxxiii. UT Starcom is a multinational company and has not been given any subsidy by the Chinese government.
- lxxxiv. Decisions of UT Starcom (regarding prices, costs and inputs, technology and labour, output, sales and investment) are made in response to market signals reflecting supply and demand, and without significant State interference.
- lxxxv. UT Starcom has complete set of basic accounting records which are independently audited in line with international accounting standards.
- lxxxvi. Non-market economy status cannot be fastened to any country as a general rule. The WTO Agreement or guidelines nowhere specifically termed China as a perpetual non-market economy.
- lxxxvii. Any fresh finding by DA should not address PTN.
- lxxxviii. If the DA proceeds to issue findings (including Final Findings) which address PTN, such findings should be made subject to the decision of the CESTAT in the appeal.
- lxxxix. As regards suppression of the information (export transactions) and being uncooperative, it is submitted that:
- It is false, baseless and motivated.
 - DA conducted site verification between 2nd and 5th June 2010 and accepted the data as true.
 - Findings of the Designated Authority are referred.
- xc. Final determination dated 19.10.2010 is final and binding (save and except the inclusion of PTN within the meaning of the PUC that is under challenge before the CESTAT).

- xc. DA referred to irrelevant activities (research, product conceptualization, design and drawing, development of technology, understanding of functionality, development of software) when looking at the production. *Reliance Industries v. DA* [2006 (202) ELT 23 (SC)]: backward integration of manufacturing process is not relevant for the purpose of determining 'DI'.
- xcii. The Final Findings have ignored the plea of public interest. ADD would serve a single entity, and more so, entities in Thailand, over PSUs like BSNL, and large telecom service providers. Tejas seeks duty on STM 64, STM 256 and DXC equipments which it cannot supply to meet domestic demand.
- xciii. PUC has been substantially revised and in the Final Findings, it is not clear whether this revised scope of PUC has been taken into account when calculating injury, normal price and margin of dumping.
- xciv. Ciena's products Core director and 5400 (being optical cross connects) are materially different from the petitioner's products and are not the like product to the PUC. Therefore, Ciena's products need to be excluded from the product scope as equivalent product is not produced by petitioner or domestic industry and no injury can possibly be caused by imports of Core director and 5400.
- xcv. Core director/5400 belong to the product family of optical cross connects and are not the products identified under para 36 of Final Findings due to significant difference in scale, multi technology support and support of control plane based networking intelligence.
- xcvi. The Authority is requested to exclude Core director and 5400 from product under consideration and make necessary amendments to the Notes of the Final Findings to exclude product and technologies which are not manufactured by the petitioner.
- xcvii. Ciena products cannot be classified as originating from China PR (or Israel) as substantial transformation and substantial value addition takes place outside of China.
- xcviii. By acknowledging that actual manufacturing is an inconsequential activity, petitioner is actually alleging dumping of services in India which is not permissible in the law.
- xcix. No assessment of dumping margin of Ciena, notwithstanding submission of information in exporter's questionnaire. Ciena requested the Authority to visit its facilities in USA but no response received from the Designated Authority. They were not informed that their submissions were deficient. They requested the Authority to determine dumping margin and non injurious margin for Ciena.
- c. The fact of Ciena's products (CoreDirector and 5400) "originating outside China", has not been disputed by DI.

Examination by the Authority

10. The Authority notes that most of the interested parties have repeated their arguments filed after the previous oral hearing dated 21.12.2009. The arguments advanced by these interested parties were already examined and addressed in detail in the previous Final Findings. The Authority has, however, carefully considered all the submissions made by the interested parties afresh. The same have been dealt with in the present Final Findings to the extent considered necessary.

PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIBRA ARTICLE.

11. The scope of the product under consideration was described in detail in the previous Final Findings and its corrigendum earlier notified and is as under:

"Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, viz. STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 in assembled, CKD, SKD form, its assemblies and sub-assemblies or fitted with eventual broadband / cellular equipment. Product under consideration will also include Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only), and Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only), Populated Circuit Boards (For SDH Application Only) and parts / components imported as a part of equipment, so long they are imported along with the equipment or its assemblies / sub-assemblies. The Product under consideration will also include Software meant for SDH, which is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. However components/ parts imported on a standalone basis are outside the purview of Product under Consideration.

***Note 2. SDH Equipment essentially transmits signals through the medium of Optical Fibre. There may be SDH equipment meant for transmission through electrical Copper Medium or Microwave Radio Medium. The SDH Equipment transmitting the data through optical fibre alone shall be subject to levy of antidumping duty.*

***Note 3. When SDH is imported as a part of eventual broadband / cellular equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports. Similarly when eventual Broadband / Cellular equipment is imported as a part of the SDH equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports.*

***Note 4. PDH, CWDM, DWDM, Microwave systems, GPON, DSLAM, MSAN, BITS, Routers, PDSN, SGSN, MGW, BTS, BSC, MSC, ONT, HLR, HSS and MRP being non-SDH in any of its form are outside the scope of PUC and therefore not subject to levy of AD Duty".*

***Note 5. Microwave Radio Terminals which could have an STM-1 interface to the SDH transmission equipment and act as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment are outside the purview of payment of AD Duty".*

12. The Authority notes that the product under consideration is essentially transmission equipment using SDH technology. It can be produced in a variety of specifications to meet the eventual customer requirements. Further, evolution of higher version/higher capacity equipment is an ongoing continuous process/ phenomena in this industry. The investigation has shown that while STM-64 equipments are already developed and the customers have already started deploying the same in the telecom networks (even though in a limited way), STM-256 was at the development stage during the investigation period as far as Indian market is concerned.
13. A number of arguments have been raised with regard to the scope of the product under consideration. After careful examination of arguments raised by various interested parties,

and having regard to the facts of the case and legal provisions, the Authority comes to the following conclusion:

- i. It would be necessary and appropriate to consider the meaning of production on case to case basis and having regard to the objective of the law. A universal definition of production would not be appropriate. In fact, different laws and regulations have defined/treated different meaning of production, as is evident from different meanings/interpretations of production under different laws. The Authority holds that the meaning of production is required to be considered having regard to the specific law and regulation, the specific definitions and interpretation given therein and the objective and purpose for which the law has been created. For the purpose of anti-dumping duties, in the present case, for example, it would be grossly inappropriate to hold that a company is a domestic producer merely because it is undertaking certain incremental production activities. In fact, any such interpretation would result in the law becoming inoperable. The Authority, therefore, holds that a company cannot be considered as a domestic producer merely because it has paid excise duty. The Authority notes that under excise law, goods are considered to have been produced even if incidental or ancillary activity for the completion of article is conducted, including packing or repacking in a unit container or labeling or re-labeling of containers including the declaration or alteration of retail sale price on it or adoption of any other treatment on the goods to render the product marketable to the consumer. However, for the purpose of anti dumping law, it cannot be said that such production activities are sufficient to constitute production. It will lead to significant multiplicities and double accounting either in imports or in domestic production.
- ii. For the purpose of anti-dumping law, the Authority holds that goods must be considered to have been produced only if the inputs undergo a "substantial transformation" into output. Widely acknowledged practice of the investigating Authorities with regard to definition of article is to consider parameters such as physical and technical properties, production technology, manufacturing process, plant & equipment, function & uses, pricing, consumer perception and customs classifications. These parameters are employed in order to consider whether the two articles are the same article or different articles. Further, the article may eventually be produced after following a small or long process of production and might be produced in one or more stages before it is eventually transformed into a form where it can constitute an article produced for the intended purpose. Merely if some inputs have been processed at the intermediate stages, where they have no use (and can perform no functions) but for consumption in the eventual product, the intermediate may not be considered as an article, even if it is saleable at that stage. The input must be distinctly different from output in terms of these parameters. From this point of view, the Authority holds that production and sale of SDH equipment or assemblies, sub-assemblies which are produced during the production process of making SDH equipment cannot be considered as a distinctly different product for the present purpose.
- iii. The Authority extensively examined the nature of production activities carried out by the petitioner and foreign producers. On the spot verification was specifically focused, inter-alia, on this aspect and the verification reports issued to the exporters have also been examined. The Authority has carefully considered the arguments of various interested parties in this regard. The Authority considers that a producer must undertake various activities before it can be considered as a producer. Various steps involved in making SDH equipment are as follows:

Research>> Product Conceptualization>> Design & Drawing>> Development of the technology>> Conceptualization and understanding of functionality>> Product blue print preparation>> Development of associated software>> Product proto type development – Hardware and Software>> Component Procurement>>Populating the Board / Card as per the design>>Soldering and EMS activities>> Integration>> Preparation of Test Jigs>> Assembly>> Testing>> Product Support and Bug fixes.

- iv. The Authority came to the conclusion the above mentioned production activities are required to be undertaken in manufacturing of SDH equipment. While it is appreciated that the company need not undertake each of the above activities. It is possible that some of these steps might involve one or more sub-processes which might be carried out independently, or some of these processes may be integrated by some company. Nevertheless, a company cannot be considered a producer of the product under consideration in the present case unless it is undertaking a substantial part of these activities.
14. Having regard to the above, the Authority reviewed the scope of the product under consideration as defined in the preliminary findings and the disclosure statement and earlier notified in the final findings. The Authority also analyzed the status of activities carried out by various interested parties, including the petitioner, other parties in India who claimed themselves as a producer of the product under consideration and foreign producers. The Authority notes that no new substantial fact has been brought about by the interested parties in their post decisional second oral hearing submissions in this regard, and, thus, the Authority maintains its earlier findings with respect to the scope of the product under consideration as defined in the earlier notified in the final findings.
15. Regarding the nature of production activity undertaken by Tejas, the Authority had held in the previous final findings that Tejas constituted a domestic manufacturer for the present purpose. The Authority notes that no new substantial fact has been brought about by the interested parties in their post decisional second oral hearing and post decisional Disclosure Statement submissions in this regard, and, thus, the Authority maintains its earlier findings in this regard.
16. As regards Prithvi & VMCL, these companies have not provided verifiable evidence of production activities being undertaken by them. Production activities carried out by Prithvi & VMCL in India, as per information available to the Authority, are assembly, testing, product support and bug fixes. These companies have not rebutted, with verifiable evidence, the claim of the petitioner that these companies are undertaking only assembly operations in India and such activities constitute very insignificant activity in the present product. They have not rebutted the claim of the petitioner that in their case, the input does not undergo a "substantial" transformation into the output. The inputs consumed by the company do not have distinguished character, function/use and are employed for production of the product under consideration.
17. The Authority also examined the activities carried out by Ciena, who has submitted that they are procuring components from China as also some portion of manufacturing or assembly for Ciena USA's products is outsourced and carried out in China by Sanmina SCI and the same does not qualify as products originating from China. Considering the information on record, the Authority holds that goods produced by Ciena shall be subject to AD duty so long they are covered within the scope of definition of product under

consideration and so long the imports of such goods into India either originate in or are exported from the subject countries under investigation.

18. The investigation has shown that following types of SDH equipments were either in use or in development during the investigation period. The Authority considered the arguments of the interested parties on exclusion of some of these types and holds as follows in this regard:

- i. STM-1, 4, 16 -- There is no dispute that these products are rightly included within the scope of the product under consideration;
- ii. STM-64 -- The interested parties argued that the petitioner has not offered STM-64 in commercial volumes. It has also been argued that largest Public Sector Company operator (BSNL) has not bought STM-64 from the petitioner. The Authority, however, holds that STM-64 is rightly within the scope of the product under consideration for the following reasons --
 - (a) Tejas has produced and sold STM-64 in Indian and overseas markets as was verified by the Authority through its investigating team;
 - (b) Even if Tejas has sold some volumes in the export markets, the product type cannot be excluded, as the fact of like article produced by the domestic industry gets established (the Authority notes that rule 2(b) read with 2(d) implies that the domestic industry should have manufactured like article. It is unnecessary to require that the domestic industry should have sold like article in domestic market). On the spot verification conducted at the premises of the petitioner, in fact, showed production of STM-64 in commercial volumes, i.e., also for Quiktel.
- iii. STM-256 -- Admittedly, STM-256 was neither imported during the investigation period nor supplied by the domestic industry. The responding exporter from China claimed that STM-256 was not deployed in China also (which means that this was not sold in China as well). The responding exporter also claimed that deployment of STM-256 in India is not even feasible so far, as necessary permission for its deployment have not been given by the competent Govt. of India authority. Investigation conducted at the premises of the petitioner and foreign producers clearly showed that STM-256 can be described as the new generation SDH equipment. The investigation has not shown that if STM-256 was exported by foreign producers, the domestic industry did not offer STM-256. In fact, the interested parties agreed that technical approvals/ permissions to deploy SDH-256 are not even in place in the country. The Authority observes that a claim for exclusion of a particular type can not be entertained unless the same has been exported to India during the relevant period, as the fact of non supply of like article by the domestic industry cannot be established unless the type is exported to India and is permitted to be used in India. The Authority holds that no grounds have been made out justifying exclusion of STM-256. Moreover, the investigating team was given access to STM-256 equipment, manufactured by Tejas and available in their premises in Bangalore. Tejas showed that it has made significant investment (Rs. ***** crores) so far in development of this product and claimed that the equipment could be sold only if some party placed an order for the same. No consumer in India has given any order to the domestic industry for supply of SDH-256.
- iv. Digital Cross Connects -- The interested parties repeatedly argued for exclusion of digital cross connect. The investigation has shown that digital cross connect are actually the equipment used in telecommunications networks, that allows lower-

level signals to be rearranged and interconnected amongst higher-level signals. Digital cross connect can be produced in SDH technology and other technologies. Digital cross connect equipment of SDH technology is clearly SDH equipment. Record verified by the investigating team establishes that Digital Cross Connect of SDH technology has been produced and supplied by the petitioner during the investigation period. The cost and price information included in the injury information and injury margin assessment includes the production and sale of digital cross connect of SDH technology. The Authority, therefore, holds that digital cross connect of SDH technology are rightly within the scope of the product under consideration. However, since digital cross connects are produced in other technology as well, it is clarified as a matter of abundant precaution that digital cross connect of other technologies are beyond the purview of the product under consideration and present investigations.

- v. SKD/CKD form of SDH equipments – Interested parties largely concede that SKD/CKD form of SDH is rightly within the scope of the product under consideration. As is seen from the production process, the product is an assembly of a number of cards, components, assemblies and sub-assemblies. It is quite possible that the product is transported in its SKD/CKD form. In fact, the product is in general invoiced in SKD/CKD form only. The producers do not raise invoice for ‘fully functional and operational’ SDH equipment. The production process from SKD/CKD form is a very insignificant assembly line operation requiring only screw driver technology. In fact, it is possible (and in fact is a practice largely adopted) to first produce the complete equipment, including necessary testing etc. and instead of transporting in a finished form, it is dispatched after dismantling in a SKD/CKD form. Exports of such SKD/CKD, thus, tantamount to exports of the product under consideration itself. In fact, the product has been shipped from China in SKD/CKD form as well. The Authority, therefore, confirms that the scope of the product under consideration includes SKD/CKD form of the product.
- vi. Assemblies and Sub-assemblies – The verification of the records of various exporters from China PR and Israel revealed that the Equipment is shipped in the form of assemblies and sub-assemblies and each of these assemblies and sub-assemblies are priced individually. Therefore, the equipment imported as a unit or in the form of assemblies / sub-assemblies is within the scope of the product under consideration.
- vii. Populated Circuit Boards / Cards – The cards/PCB’s are populated as per the design developed by the manufacturer and thereafter, apart from loading of software, there is only a need to arrange them in a shelf and adjust them to a circuit. Since Printed Circuit Boards are propriety of the manufacturer, the same are within the scope of the product under consideration. It is, however, clarified that in case PCBs or cards are meant for production/assembly of a product other than SDH equipment, the same is beyond the scope of the product under consideration. PCB and cards are within the scope of the product under consideration only if such PCBs or cards are meant for production of SDH equipment.
- viii. Parts and Components – Interested parties have heavily opposed inclusion of parts and components within the scope of the product under consideration. The interested parties have argued, inter-alia, that (i) parts/components are different products, (ii) parts & components have not been offered by domestic industry, (iii) production from the stage of parts/components is quite significant and, in fact, constitutes production, (iv) imposition of anti-dumping duties on parts/components is inoperable or may even lead to harassment at the stage of implementation or might lead to demand for collection of duty even when the same may not be justified. The domestic industry on the contrary has sought inclusion of parts and components on

the premise that their exclusion will leave a big scope for circumvention. They have pleaded that imports of components as “raw material” or “inputs” must be distinguished and differentiated with imports of SDH in component form (with IPR being supplied without customs check/control/clearance). They have further submitted that the domestic industry is not against imports of components as inputs. Domestic industry is against import of product in the form of components, using the same Chinese IPR and then assembling the product in India as this tantamounts to continued dumping in different form. The Authority has taken note of the fact that parts and components are not manufactured by the Domestic Industry, and the domestic industry for parts and components is not before the Authority. The Authority further notes that parts and components used in SDH equipment have multiple usages and do not have a dedicated usage in SDH equipment alone. The Authority, after going into the details of usage of parts and components, is of the view that including parts and components, when imported on a standalone basis is going to put the whole consumer durable industry to hardship.

- ix. SDH equipment as part of another equipment - The Authority notes that the product under consideration eventually forms part of Broadband or Cellular equipment. It is quite possible to import SDH equipment as part of such Broadband or Cellular equipment. If the scope of the product under consideration is not kept to include imports of SDH equipment forming part of such Broadband or Cellular equipment, the entire process of undertaking present investigations and proposed measures can be defeated. Further, no justified grounds have been brought out by any interested party as to why such import should not be chargeable to duty. The only concern of the interested party may be that the Customs Port Authorities should not demand anti-dumping duties on the entire Broadband or Cellular equipment. It is, therefore, clarified that the scope of the duty shall only be to the extent of the value of SDH equipment included in such Broadband/Cellular equipment. The scope of the duty shall not extend to the entire equipment. The importers are expected to declare and the Customs Port Authorities are expected to apply due diligence in ascertain/bifurcating the value of SDH equipment.
- x. Software - Software is an essential part of the product under consideration in as much as the equipment is totally non-functional without such software. Such software can be developed by the producer itself or producer may get the same developed from other agencies. It is possible to invoice such software either as part of the equipment or separately. The scope of the product under consideration rightly includes the software and the Authority confirms the same.
- xi. DWDM - Lot of interested parties have sought exclusion of DWDM. DWDM is different technology transmission equipment. It is not SDH technology equipment. Since DWDM is not an SDH technology equipment, the same was beyond the scope of present investigation and proposed measures. However, in view of the repeated arguments of the interested parties and their claim of possible demands of anti-dumping duties in future by Customs Port Authorities, it is clarified that DWDM transmission equipment are beyond the scope of the product under consideration.

19. Having regard to the petition, initiation notification, preliminary findings, final findings earlier notified, arguments raised by the domestic industry and opposing interested parties at the time of present post decisional oral hearing and submissions made by the interested parties pursuant to the post decisional oral hearing and post decisional Disclosure Statement, the Authority holds that the scope of the product under consideration is as follows:

"Synchronous Digital Hierarchy transmission equipment, viz., STM-1, STM-4, STM-16, STM-64, STM-256 in assembled, CKD, SKD form, its assemblies and sub-assemblies or fitted with eventual broadband / cellular equipment. Product under consideration will also include Add Drop Multiplexers (ADM) (For SDH Application only), Multiple Add Drop Multiplexers (MADM) (For SDH Application only), and Digital Cross Connect (DXC) (For SDH Application only), Populated Circuit Boards (For SDH Application Only) and parts / components imported as a part of equipment, so long they are imported along with the equipment or its assemblies / sub-assemblies. The Product under consideration will also include Software meant for SDH, which is an integral part of these equipments, which may be bought either as a part of the equipment or separately. However components/ parts imported on a standalone basis are outside the purview of product under consideration.

***Note 2. SDH Equipment essentially transmits signals through the medium of Optical Fibre. There may be SDH equipment meant for transmission through electrical Copper Medium or Microwave Radio Medium. The SDH Equipment transmitting the data through optical fibre alone shall be subject to levy of antidumping duty.*

***Note 3. When SDH is imported as a part of eventual broadband / cellular equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports. Similarly when eventual Broadband / Cellular equipment is imported as a part of the SDH equipment, the AD Duty shall be payable only on the SDH portion of the imports.*

***Note 4. PDH, CWDM, DWDM, Microwave systems, GPON, DSLAM, MSAN, BITS, Routers, PDSN, SGSN, MGW, BTS, BSC, MSC, ONT, HLR, HSS and MRP being non-SDH in any of its form are outside the scope of PUC and therefore not subject to levy of AD Duty".*

***Note 5. Microwave Radio Terminals which could have an STM-1 interface to the SDH Transmission Equipment and act as a physical media to enable the connectivity between the radio and the SDH equipment are outside the purview of payment of AD Duty*

PCN SYSTEM

20. The product under consideration is produced and sold in a number of different types. Different types are produced to meet specific customer requirements. In order to ensure fair comparison between normal value and export price, the Authority classified the product under consideration into different types based on parameters such as transmission capacity, cross connect capacity, E1 interfaces, electrical interfaces, optical interfaces, optics types, etc. The Authority evolved a product control system (PCN) running into 15 digits. All interested parties were directed to provide information on cost & price separately for each PCN. The interested parties were, however, given liberty to deviate from the suggested PCN system after due justification.

448 G1/12-9

21. Some interested parties have disputed the proposed PCN system. The Authority notes that the product under consideration is essentially an assembly of a number of electronic cards and sub-assemblies. In fact, the producers tend to invoice the sales in terms of SKD/CKD/cards/sub-assemblies of the product. Investigation has shown that all the companies follow some system for production and sale of the product, for which some product coding system is followed. Considering this aspect of the product, the Authority had prescribed a PCN system, considering the scope of PUC and the intent has been to bring the scope of the PUC identifiable and comparable. While doing so, the Authority gave liberty to all the responding exporters to come up with any other suggestion on devising the PCN methodology, duly justifying the system, other than the one proposed by the Authority. A communication was individually sent to all the interested parties in this regard. However, all the exporters, who participated in the investigation, chose to accept the PCN methodology suggested by the Authority and submitted data as per the said PCN methodology. Therefore, the Authority holds that the PCN methodology adopted for the present investigation has proved to be correct and reasonably acceptable to all the interested parties, particularly the responding exporters, who in principle agreed to this methodology and got their data verified based upon this PCN methodology. The Authority is unable to accept the argument of the interested parties that the PCN system proposed was too complicated and the exporter could not give data in accurate manner in view of the PCN system. The Authority considers that the exporter should have pointed out such operational difficulties while responding to the questionnaire at the stage of initiation of investigations. Any such submission while responding to the verification report issued by the Designated Authority after on the spot verification cannot be accepted.

STANDING & SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY

22. Arguments have been made by various interested parties that –

- i) Petitioner itself is not a producer of the product under consideration;
- ii) Petitioner itself is an importer of the product under consideration;
- iii) The discretion under rule 2(b) cannot be applied differently for different parties;
- iv) The rules do not distinguish between imports from subject countries and other countries;
- v) The rules do not prescribe any numerical formula with regard to volume of imports;
- vi) The goods imported by the petitioner from Thailand might include parts/components which were eventually sourced from China PR and because the scope of the product under consideration includes parts/components, the petitioner should be considered ineligible domestic industry.

23. Based on the information available on record, the Authority provisionally determined that (a) production activities by the petitioner constitute production for the purpose of the present investigations; (b) imports by the petitioner are not such as to disqualify the petitioner from the scope of Rule 2(b); (c) imports by other domestic suppliers such as Prithvi and VMCL are such as to render them ineligible domestic producers under Rule 2(b); and (d) production of the petitioner accounts for a major proportion of the total Indian production. On this basis, the Authority provisionally concluded that the petition

satisfies the standing and the petitioner constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.

24. While disputing the claim of M/s Tejas to treat it as the domestic industry, the opposing interested parties have contended that Tejas should be treated as ineligible for consideration as the domestic industry in view of the facts that (a) Tejas had imported certain components forming part of the product under consideration (PUC) as defined in the Initiation Notification, (b) to qualify as a "domestic industry", the domestic producer must be engaged in the manufacture of the product to the extent of a "major proportion", i.e., the producer must show that he manufactures all the necessary parts, accessories and components of the PUC, (c) DGAD has not considered Prithvi and VMCL as eligible manufacturers because they don't do any "substantial transformation" of inputs, (d) no concept of "substantial transformation" exists in anti dumping rules, (e) Tejas also imports component but is considered as eligible domestic industry while Prithvi and VMCL were not considered as domestic industry, (f) DGAD has relaxed rules for Tejas saying that Tejas has imported dual usage components without considering that Tejas has a dedicated use of components, i.e., for manufacturing of SDH Telecom equipments, (g) imports from third countries other than China PR and Israel also amount to one being considered as importer because under rule 2(b) country of imports is not specified and so even if Tejas imports from countries other than China PR and Israel even then Tejas is not eligible to be called as domestic manufacturer, and (h) Tejas imported from Thailand and Malaysia.
25. The issues raised by the interested parties with regard to standing & scope of the domestic industry have been mentioned and analyzed in detail by the Authority at paras 41 to 66 of the Final Findings. The Authority concluded that Tejas constitutes "Domestic Industry" within the meaning of the AD Rules.
26. As far as Tejas is concerned, the Authority has analysed the production activities undertaken by the company. As regards imports made by Tejas, detailed factual position in this regard was stated by the Authority at para 50 of the final findings. The Authority notes that Tejas' imports from China, which are ***% of the total imports made by the company (***% of the turnover of the company), are the stand alone dual use components. The Authority has not included stand alone dual use components within the scope of the product under consideration. During verification of records of responding exporters, the Authority has come across information with regard to import of complete equipment from China, both by Prithvi and VMCL.
27. It has been argued by the interested parties that Tejas did not have production facilities at Pondicherry during the POI. Tejas has provided invoice which shows invoicing of the product from its Pondicherry facility during the POI. The factory of the company was visited by a team of investigating officers. It is established that production activities identified for the product were being carried out by the company within the country. The Authority thus holds that Tejas was carrying out production activities at Pondicherry during the POI.
28. As regards imports from third countries not under investigation, the Authority notes that such third country imports do not constitute imports of "alleged dumped article". Such

import, therefore, should not prevent such domestic producer from bringing an application as a domestic industry. It is relevant to point out that in case such domestic producer is importing significant volumes from third countries, the same might be relevant in establishing existence or otherwise of casual link. If the imports from third countries are insignificant in volume, the same becomes irrelevant.

29. Interested parties have argued that the fact that imports were made from non subject countries is irrelevant under Rule 2(b) and “alleged dumped article” relates to article and cannot be linked to the country. The Authority has carefully examined various legal provisions in this regard and holds that terminology in various provisions under rules and the objective of exclusion provided under 2(b) makes it abundantly clear that the question of excluding a party under rule 2(b) should arise only if such imports are from the subject countries under investigation. Imports from third countries cannot be considered as imports of alleged dumped article. The Authority relies upon in this regard on the objective/intent of providing such a description under 2(b) and various other provisions under the rules. Reference to dumped article or alleged dumped article under rule 2 and 6 is clearly with reference to subject country(ies), the producer in such subject countries and importers of the product from such subject countries. The Authority thus holds that imports of the article under investigation from subject countries alone are relevant for the purpose of inclusion or exclusion of a domestic manufacturer under rule 2(b).
30. It has been argued that Rule 2(b) cannot be applied differently on different parties. It has further been alleged that the Authority has considered Tejas as eligible domestic producer and Prithvi and VMCL as ineligible domestic manufactures. Interested opposing parties have disputed the Authority’s determination in this regard and have argued that even when both Tejas and Prithvi/VMCL have resorted to imports, the Authority has discriminately applied discretion available in Rule 2(b). Notwithstanding the determination with regard to product under consideration, the meaning of Chinese, Indian and third countries, the meaning of goods manufactured in India, China PR or third countries which leads to a conclusion that Prithvi and VMCL are not domestic manufacturer of the product under consideration in India, the Authority holds that in any case, rule 2(b) does not provide a uniform decision on inclusion or exclusion of domestic producers who are themselves importing the product. The Authority holds that such discretion is required to be exercised on a case by case basis. Different parties might import the product for different reasons. Volume/extent of imports by different parties might be different. Inclusion or exclusion of domestic manufacturer under rule 2(b) is based on certain reasons. Since the reasons themselves might vary from party to party, a universal application of the discretion is neither conceived under the law nor would be appropriate. The practice of the Authority and other Investigating Authorities in this regard also supports this view of the Authority.
31. Interested parties have argued that Tejas has undisputedly used services of EMS. Such EMS companies might have procured parts/components from China PR, value of which might not be included in the volume of imports relied upon by the Authority in applying the discretion. The Authority stated the factual position in this regard at para 56 of the final findings. Further, these imports are of dual use parts and components or stand alone components which are beyond the scope of the “product under consideration”. The Authority, therefore, holds that this argument of the opposing interested parties is not sustainable.
32. It has been alleged that although there are a number of other manufacturers, Tejas has been considered to have the necessary standing of constituting a major proportion of the total domestic production within the scope of Rule 2(b) of the AD Rules. In this context, the Authority notes that initially, after the initiation of investigation, apart from Prithvi

and VMCL, no other so called manufacturer, as highlighted by both Prithvi and VMCL in their submissions, has come forward to claim the status of being a domestic manufacturer. Even Prithvi and VMCL, barring a claim to this effect in a narrative form, never provided any verifiable information about their manufacturing activities. Prithvi / VMCL have not filed questionnaire response in the form and manner prescribed, either as a domestic producer or an importer of the product under consideration. Even when the Authority specifically advised these companies to provide information in the form and manner prescribed, these interested parties have preferred not to provide relevant information. Even otherwise they never furnished any details / data about their set up except the claim that they are manufacturers as they also pay excise duty. Mere payment of excise duty cannot amount to give the status of a "manufacturer" for the present purpose, as already stated herein before. The Authority notes that these two companies have preferred non cooperation within the meaning of Rule 6(8). The Authority holds that while it is open for an interested party to advance its argument, it is obligatory on the part of such interested party to provide such information as is requested by the Authority and offer itself for verification, if desired by the Authority. The entire exercise undertaken in the instant case in ascertaining actual status of these entities would have been significantly smoothened, had these interested parties provided relevant information demanded by the Authority and offered themselves to spot verification. In view of conscious non cooperation preferred by these interested parties, the Authority has been constrained to rely upon available material in this regard. The information on record has shown as follows –

- i. These interested parties have not sold SDH equipment till the end of the investigation period.
- ii. The Authority identified activities such as research, product conceptualization, design & drawing, development of technology, conceptualization and understanding of functionality, product blue print preparation, development of associated software, product prototype development-hardware and software, component procurement, soldering and EMS activities, integration, preparation of test jigs, assembly, testing and product support and bug fixes as essential production activities. These interested parties do not carry out substantial part of these production activities listed by the Authority as the activities comprising production in the present case. It is not established that these parties even carried out assembly operation. There is no evidence on record showing production or sale of the product under consideration by these parties. Even on the repeated argument of payment of excise duty, these interested parties have not established that the said excise duty was paid in respect of SDH equipment. Petitioner argued that the said excise duty might have been paid on different products. These interested parties have not provided evidence to show that the excise duty was indeed paid for production & clearance of the product under consideration.
- iii. These interested parties have failed to establish that they have made investments in research & development, plant & equipment and other facilities required for production of the product under consideration. The Authority notes in this regard that only activities relating to product under consideration alone are relevant to the Authority. Other activities carried out by these interested parties in respect of other products, if any, are entirely irrelevant in this regard. It is also relevant to point out in this regard that on their own accord, some of the interested parties, including VMPL & Prithvi considered DWDM as "product under consideration". It is, therefore, not established whether the alleged status of a manufacturer is because of possible production and sale of DWDM or SDH equipment. The Authority notes that in case these companies have set up production facilities and have thereafter produced and sold DWDM equipment, the same cannot entitle

them to claim a status of producer for the present purpose and present product under consideration.

- iv. Subsequent to issue of Preliminary Findings, FIBCOM came up with a claim of being manufacturers of PUC and claimed to support the petition so long as components are placed outside the purview of PUC. They also, however, did not provide any data on their claim to be a manufacturer to the Authority. Petitioner, at pre-initiation stage, had filed a letter from CMAI (Association) along with the petition. CMAI stated that the petitioner accounts for a major proportion of Indian production. This was considered prima facie sufficient evidence for the purpose of initiation of the investigation.

33. The Authority noted in the preliminary findings that the reference was made by the interested parties to panel report in the matter concerning Farmed Salmon from Norway. The Authority noted in the preliminary findings that the facts of that case are different than those of the present case. In the case under reference, EC had not examined whether or not activity conducted by those producers who were not considered as producers of product concerned was an activity which could constitute production. The Authority notes that the interpretation of Article 4.1 of ADA given by the WTO Panel has a limited scope in the present proceedings. Para 7.115 of the Report is relevant in this regard:

7.115 There is no dispute that filleted salmon is within the scope of the like product identified by the EC in this case. Thus, based on our interpretation of the plain language of Article 4.1, we consider that any enterprise that produced any form of the like product should be considered, at least in the first instance, a "producer" of the like product, and as such, part of the domestic industry.

Footnote 289 reads as follows:

289. There may be circumstances in which an enterprise whose product is within the scope of the like product may be found to have engaged in a level of activity so low as to justify the conclusion that it did not, in fact, "produce" the like product. However, there was no consideration of the degree of activity of filleting-only undertakings in defining the domestic industry during the investigation. Therefore, the question is not before us on the facts of this case.

34. Panel, therefore, envisaged some circumstances (as stated in footnote 289), which Panel agreed may not be sufficient to consider an entity as a "producer" of the product. The panel, however, did not decide when a company may be considered as a domestic producer and when it can be considered as a mere importer of the product under consideration. The Panel did not dwell on what constitutes sufficient activity in order to describe an entity as a producer. Nor did the Panel describe the meaning of "production". The precise issue under consideration in the present case is what constitutes production and who can be regarded as a domestic producer.
35. In view of the above, having regard to the definition of the domestic industry under Rule 2(b) and information on record, the Authority holds that VMCL and Prithivi have failed to establish themselves as domestic producers of the product under consideration for the purpose of present investigations. Further, in any case, these parties have failed to establish that they should be considered as "eligible domestic industry" within the meaning of Rule 2(b).
36. As regards Tejas, the Authority has examined at length the nature of activities being carried out by Tejas at para 31 of the final findings. The Authority holds that imports of

the product from subject countries alone are relevant for the present purpose. Imports made by Tejas from Thailand do not disentitle the company from being considered domestic industry. Imports from China are not of the product under consideration as considered by the Authority. The Authority holds that principal activity of the company is manufacturing in India. The petitioner has not reduced its own production activity, and has not turned to trading. No justifiable reasons have been advanced by the interested parties warranting exclusion of the petitioner.

37. After careful examination of the legal provisions and facts of the case, and the fact that no new substantial fact has been brought about by the opposing interested parties in their post decisional second oral hearing submissions in this regard, and, thus, the Authority notes that facts on record do not justify exclusion of Tejas from considering it as the domestic industry in the present case. The contention of the opposing parties that a company is ordinarily to be excluded in case it has imported does not hold good in view of the fact that imports made by Tejas are essentially standalone components which are now outside the scope of PUC and thus maintains its earlier findings in this regard.
38. The Authority notes that mere fact of payment of excise duty, if considered a barometer of "manufacturing" for the purpose of anti dumping law, would lead to several incorrect interpretations with regard to determination of dumping & injury as it would imply that even incremental activities such as retagging, repacking, relabeling, micronisation, metallization, pulverization, etc. will also become production. The interpretation will lead to a situation where one product could have been produced several times. For instance, in the instance case, there are companies known as EMS companies, who are specialized electronic component soldering companies, doing such activities for a variety of industries, without any knowledge whatsoever with regard to designing or functioning of the card they produce. These companies are also paying excise duty. The interpretation will imply that even these companies should be recognized as SDH manufacturers. Thus, these EMS companies who have produced and supplied the card to Tejas would also be deemed to become the manufacturer of SDH equipment (in CKD/SKD condition). The production will be counted twice. Similarly, imports of the product will be counted as production of the foreign producer & import into India and thereafter, the very same product will be counted as production & domestic sale of the importer, only because the importer has imported the product in CKD/SKD condition, assembled the product and sold it after payment of excise duty. The scope of the product under consideration includes parts & components in some situations. Some of these parts & components have been produced by some other specialized component manufacturers in India. Thus, even these component manufacturers would also become SDH manufacturer. Such companies, therefore, cannot be recognized as SDH manufacturers under the anti dumping laws.
39. Further, every company selling the product cannot be regarded as a domestic producer. There should be certain minimum threshold activity/criteria to be completed/ crossed by a party selling a product in the market before it can be regarded as a producer. And such activity/criteria cannot be payment of excise duty. Such activity/criteria have to be considered on the basis of nature of the product and production process. For example, a person trading in the imported product is also engaged in some activity connected with the product. However, such trader cannot be regarded as a producer under anti dumping law, even if such trader is paying excise duty for some plausible reasons under the excise law.

40. The Authority further notes that apart from CMAI, another industry association TEMA, in their letter dated 3-Dec-09 has also supported petitioner's stance about the definition of who constitutes domestic industry and their support to the interim decision of the Authority. Clearly traders/assemblers cannot be considered domestic industry. The mere fact that no other so called manufacturer has either participated in the investigation or those who have participated have failed to provide any evidence with regard to their manufacturing activities in the Proforma prescribed for the domestic industry, and also other details elaborately discussed above, further support the conclusion drawn by the Authority that Tejas constitutes "Domestic Industry" within the meaning of the AD Rules.
41. The claims of the petitioner with regard to assessment of Indian production was examined by the authority in detail. The authority in particular examined the claim of the petitioner on the basis of voice and data magazine. It was found that Indian production assessed by petitioner was reasonable and sufficient to establish standing of the petitioner within the meaning of the rules. The investigation has established that the production of the petitioner constituted a major proportion in Indian production (significantly beyond 50% of Indian production). The authority notes in this regard that the petitioner can be expected to provide only such information as is reasonably available to them. None of the interested party have been able to show that petitioner did not provide information which was publically available information and which could have constituted more accurate information.
42. The reasoning of the CESTAT in Dye Stuff Manufacturers Association vs. Designated Authority is not applicable to the present case. In the matter of Dye Stuff Manufacturers Association vs. Designated Authority, the magazine was not periodically reporting the price of Aniline. Instead the magazine had carried an article on Aniline and mentioned the price of Aniline in the market. In the instant case, however, the interested party agreed that Voice and Data magazine regularly mentions the relevant information. Further, the credibility of voice and data magazine gets established if information contained in the journal with regard to operations of Tejas are compared with the actual operations of Tejas.
43. There is no legal requirement to hold a pre-decisional hearing or polling in order to determine standing of the petitioner under Rule 5. The Authority notes that petition contained sufficient information with regard to standing and the same constituted sufficient positive evidence. Further, the investigation conducted by the Authority established that the facts contained in the petition were sufficient and correct in this regard.
44. As regards the argument that applicant is required to be excluded from the constituents of DI as they import PUC, the Authority notes that the petitioner has imported parts and components which are beyond the scope of the product under consideration. Further, the Authority holds that the definition of Rule 2(b) provides discretion to the Authority.

CONFIDENTIALITY

45. Issues regarding the confidentiality have been examined by the Authority at para 75 of the previous Final Findings. The Authority notes that no new substantial fact has been brought about by the interested parties in their post decisional second oral hearing submissions and post decisional Disclosure Statement submissions in this regard, and, thus, the Authority maintains its earlier decision.

46. As regards the non confidential version of the submissions of other interested parties, the same was made available in the public file maintained by the Authority.

PUBLIC INTEREST

47. Issues regarding public interest have been examined by the Authority at paras 76 & 77 of the final findings. The Authority notes that no new substantial fact has been brought about by the interested parties in their post decisional second oral hearing submissions and post decisional Disclosure Statement submissions in this regard, and, thus, the Authority maintains its earlier decision.

DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

48. Issues regarding the market economy treatment and determination of dumping margin have been examined by the Authority from para 78 to 118 of the previous final findings. The Authority notes that no new substantial fact has been brought about by the interested parties in their post decisional second oral hearing submissions and post decisional Disclosure Statement submissions in this regard, and, thus, the Authority maintains its earlier decision.

INJURY AND CAUSAL LINK

49. Issues regarding injury to domestic industry and determination of injury margin have been dealt by the Authority from para 121 to 167 of the final findings. The Authority notes that no new substantial fact has been brought about by the interested parties in their post decisional second oral hearing submissions in this regard, and, thus, the Authority maintains its earlier decision.
50. As regards the arguments that the earlier Disclosure Statement did not disclose all essential facts that formed the basis of decision, it is noted that Authority had disclosed all such essential facts which were required to be disclosed to interested parties and which formed the basis of the Authority's previous decision.
51. As regards the arguments related to the verification in the petitioner's premises, the Authority notes that the investigating team constituted by the Authority visited premises of the petitioner at Bangalore and Pondicherry.
52. As regards the arguments regarding the need of verification at the premises of such third party EMS vendors, it is noted that the Authority has conducted such verification as is considered necessary for the purpose of present determination.
53. The interested parties request the Authority not to issue Final Findings till disposal of the SLP pending in the Hon'ble Supreme Court of India. The Authority is of the view that there is no direction by the Hon'ble Supreme Court that the Designated Authority should not issue final findings. In the absence of any specific direction preventing the Designated Authority from

notifying the finding and considering the orders of the CESTAT, the Authority considers it appropriate to issue the findings in the present matter.

54. As regards the disclosure of non confidential version of the verification report of the domestic industry, the Authority has not disclosed verification report of the foreign producers to other interested parties (the domestic industry also demanded a copy of the verification report of the foreign producers). Further, there is no mandated legal requirement for a verification report to be prepared in respect of verification conducted at the premises of the domestic industry. Verification report in respect of on the spot investigations conducted at the premises of the domestic industry is, therefore, not required to be made available to the interested parties.

Examination by the Authority of the submissions of the Domestic Industry and the opposing interested parties after the post decisional Disclosure Statement dated 6th February, 2012:

55. A number of interested parties have offered comments to Disclosure Statement issued by the Authority on 6th February, 2012, which have been carefully examined by the Authority. The Authority noted that these comments are substantially repetition of the submissions made by these interested parties earlier during the course of the proceedings or in their written/rejoinder submissions filed after the post decisional oral hearing conducted by the Authority pursuant to the orders of the Hon'ble CESTAT. The arguments of the domestic industry are with regard to correctness of the product under consideration proposed by the Authority and standing determination made by the Authority. Further, domestic industry has reiterated their submissions objecting to the grant of market economy treatment to ECI and acceptance of export price for some of the responding exporters in view of allegedly unreported export transactions. The opposing interested parties have reiterated their earlier submissions, arguing incorrect scope of product under consideration (in particular inclusion of SDH-64, SDH-256, Digital Cross Connect, applicability of anti-dumping duty if the product under consideration is imported as part of other product, etc. Interested parties have opposed proposed determination with regard to standing of Tejas to file the present petition and have argued that Tejas cannot constitute domestic industry. At the same time, these interested parties have argued that other domestic companies (such as Prithvi, VMCL etc.) should also be treated as domestic industry.
56. Having regard to various submissions made by the interested parties at the time of oral hearing and thereafter in their written and rejoinder submissions, Disclosure Statement issued by the Authority and comments to the Disclosure Statement offered by various interested parties, and further having regard to the anti-dumping act and the rules, information filed by various interested parties during the course of the investigations and considering the merits in the arguments raised by the interested parties in view of legal and factual position, the Authority holds that the comments offered by various interested parties to the post decisional Disclosure Statement do not call for any reconsideration of factual and legal position earlier reported in the Disclosure Statement.

Indian industry's interest and other issues

57. The Authority recognizes that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. The Authority notes that the anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

58. The Authority recognizes that the purpose of anti dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

Conclusions and Recommendations

59. The Authority notes that the Hon'ble Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT), Principal Bench, New Delhi vide its order dated 11.08.2011 had directed the Authority to make such modifications to the Final Findings as may be necessary as a result of such post decisional hearing.
60. Having regard to final findings earlier notified, various submissions made by the interested parties at the time of second oral hearing and thereafter in their written & rejoinder submissions, Disclosure Statement issued by the Authority and comments to Disclosure Statement offered by various interested parties, and further having regard to the anti-dumping act and the rules, information filed by various interested parties during the course of the investigations and considering the merits in the arguments raised by the interested parties in view of legal and factual position, the Authority holds that the final findings earlier notified by the Authority do not require any modification. The petitioner had standing to file and maintain the petition. The submissions made by the interested parties do not require any modification in the dumping margin earlier determined. Further, the Findings earlier notified by the Authority with regard to existence of injury to the domestic industry and casual link between dumping and injury also do not require any modification. The Authority holds that the product under consideration has been exported from subject countries at a price below normal value, thus, resulting in dumping of the product which has caused injury to the domestic industry. The Authority holds that anti-dumping duties are required to be imposed in order to address injury caused to the domestic industry by dumped imports. The Authority holds that no part of the Final Findings Notification No 14/2/2009-DGAD dated 19th October, 2010 is required to be modified as a result of the post decisional hearing conducted by the Authority and submissions made by various interested parties pursuant to the said hearing. The Authority, hereby, issues its post decisional Final Findings confirming the Final Findings earlier notified vide Notification No. 14/2/2009-DGAD dated 19th October, 2010.
61. An appeal against the order of the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority